चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 13 फरवरी– 19 फरवरी 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

लापता वरुण गांधी का पता मिला

संतोष भारतीय

यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आख़िर वरुण गांधी हैं कहां. उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त होने जा रहा है और वरुण गांधी का कहीं अता-पता नहीं है. इसकी छानबीन करने के लिए हमें पांच मुख्य पात्रों के आसपास के लोगों से बहुत सोच-समझकर और सावधानी के साथ बात करनी पड़ी. इनमें पहली श्रीमती मेनका गांधी, जो वरुण गांधी की मां हैं, दूसरे अमित शाह जी, तीसरे दस जनपथ से रिश्ता रखने वाले लोग, चौथे खुद वरुण गांधी के मित्र और पांचवां जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, वो हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी.

इन सबसे बातचीत करने के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई, वो इतनी रोमांचक है कि अगर सूत्रों से मिली हुई सूचनाओं को एकत्रित कर दिया जाए, तो रोमांच और बढ़ जाता है. आइए, आपके सामने पूरी कहानी रखने की कोशिश करते हैं.

जब वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, उस समय आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री से भाजपा के सांसद वरुण गांधी की कई मुलाकातें हुईं. एक बार गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वरुण गांधी से मिलने उनके घर आए. चूंकि वरुण गांधी महामंत्री थे, इसलिए संगठनात्मक मसलों पर बातचीत के लिए दोनों की मुलाक़ात हुई. नरेन्द्र मोदी बातचीत की शुरुआत कर ही रहे थे कि वरुण गांधी का सेवक उनके लिए चाय लेकर आया. चाय उसने मुख्यमंत्री जी के सामने टेबल पर रख दी. टेबल पर चाय रखते हुए प्लेट में छलक गई. सेवक शायद बिहार का था. बिना यह अहसास किए कि उसने कितनी बड़ी ग़लती कर दी है, वह वापस जाने लगा. अचानक चुटकी की आवाज़ आई और मुख्यमंत्री जी ने उस सेवक को बुलाया. उससे कहा कि ये चाय तुमने छलका दी है, इसे फौरन ले जाओ और बदलकर ले आओ, छलकनी नहीं चाहिए. एक बात याद रखो, कोई भी काम बहुत सावधानी और सफ़ाई से करनी चाहिए. वह सेवक कांप गया और उस ट्रे को उठाकर वापस ले गया और फिर बहुत सावधानी के साथ बिना छलकाए चाय लेकर आया. वरुण गांधी ने इस घटना के बारे में अपने किसी मित्र को बताया कि थोड़ी सी छलकी हुई चाय को लेकर सेवक के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री के व्यवहार से मैं बहुत हैरान रह गया, इस घटना ने मुझे अंदर से हिला दिया.

कांग्रेस के एक नेता हैं शहज़ाद पूनावाला. उनकी बहन की शादी थी. उन्होंने बहुत सारे लोगों को निमंत्रित किया था. इसमें प्रियंका गांधी और वरुण गांधी भी शामिल थे. वरुण गांधी शहज़ाद पूनावाला की बहन की शादी में पहुंचे और वहां लगभग ढाई से तीन घंटे रहे. उन्हें देखते ही प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाकर स्माइल दी और अपने पास बैठने की दावत दी. वरुण गांधी शादी में आए अन्य लोगों से मिलने लगे, उधर प्रियंका गांधी उनका इंतजार करती रहीं. थोड़ी देर बाद वरुण गांधी प्रियंका गांधी के पास जाकर बैठ गए और दोनों लगभग दो घंटे साथ बैठे रहे. शादी में आए तमाम लोगों ने उन्हें आसपास बैठकर बातचीत करते देखा. लोगों ने यह भी देखा कि प्रियंका गांधी वरुण गांधी से काफी बातचीत कर रही हैं या बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं, वरुण मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन कम ही जवाब दे रहे हैं. उस शादी में मौजूद एक व्यक्ति के अनुसार, प्रियंका गांधी वरुण के ऊपर कुछ प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वरुण उस प्रभाव से अपने को मुक्त करने की कोशिश में दिखाई दिए. दोनों लगभग दो घंटे साथ रहे. क्या बातचीत हुई, कोई नहीं जानता. लेकिन दोनों साथ बैठे और बातचीत हुई, इसे बहुत सारे लोगों ने देखा. वरुण गांधी की सुरक्षा में लगे हुए लोगों ने शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह संदेश दे दिया कि आज प्रियंका गांधी और वरुण गांधी में मुलाक़ात हुई है और दोनों में दो घंटे के क़रीब बातचीत हुई है. इस मुलाकात में प्रियंका गांधी के लिए कोई रिस्क नहीं था. अगर कुछ रिस्क था तो वरुण गांधी के लिए था.

एक दिन अचानक वरुण गांधी के पास भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का संदेश आया कि उनसे तुरंत आकर मिलें. वरुण गांधी अमित शाह के घर उनसे मिलने गए. वरुण गांधी के एक मित्र के अनुसार, अमित शाह एक सिंगल सिटेड सोफे पर बैठे थे. उनके सामने एक टेबल रखी थी, जिसके ऊपर वे पैर रखकर बैठे हुए थे. वरुण गांधी आए तो उन्होंने स्माइल दी और उन्हें बैठने के लिए कहा. वरुण गांधी बैठे नहीं, लेकिन उन्होंने अमित शाह से कहा कि अमित भाई, क्या आप मोदी जी के सामने भी इसी तरह बैठते हैं, जैसे अभी मेरे सामने बैठे हैं.

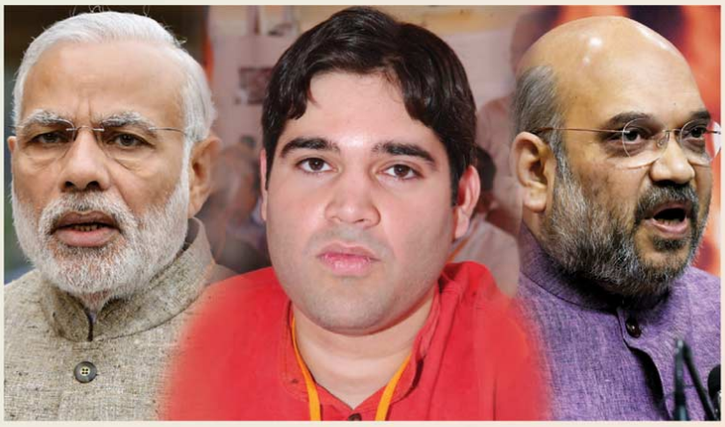

इससे पहले, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मंत्रिमंडल तैयार कर रहे थे. उस समय संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा वरुण गांधी को मंत्री बनाने के लिए दबाव डाल रहा था. लेकिन नरेंद्र मोदी वरुण गांधी को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे. तब कुछ लोगों, जिनमें राजनाथ सिंह प्रमुख थे, ने वरुण गांधी से बात कर ये जानना चाहा कि वरुण गांधी अगर मंत्री न बने, तो क्या फायदा और नुक़सान हो सकता है. दरअसल, वो वरुण गांधी की भविष्य की चाल जानना चाहते थे. संघ के प्रमुख लोगों से वरुण गांधी का संपर्क था, क्योंकि वरुण गांधी को संरक्षक के तौर पर सरसंघचालक सुदर्शन जी का काफी समर्थन मिलता था. संघ के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर वरुण गांधी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वह भारतीय जनता पार्टी में असंतोष को हवा देंगे और कुछ परेशानियां पैदा करेंगे. जब उन लोगों ने वरुण गांधी से बात की, तो उन्हें यह अहसास हुआ कि वरुण गांधी यह चाहते हैं कि उनकी मां को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया जाय. संघ के सूत्रों ने मुझे बताया कि यह इसलिए जरूरी था कि गाय को खूंटे पर बांध दिया जाय, तो बछड़ा बहुत दाएं-बाएं नहीं भागता, वो गाय के पास ही रहता है. इसी उदाहरण के अनुसार, संघ के कुछ लोगों ने और संभवतः राजनाथ सिंह ने (जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं) नरेंद्र मोदी से कहा कि मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में ले लेना चाहिए. अंततः, मेनका गांधी मंत्रिमंडल में आ गईं.

शहजाद पूनावाला की बहन की शादी के बाद वरुण गांधी के घर एक शाम रात्रि भोज पर प्रियंका गांधी आईं. दरअसल, प्रियंका गांधी की ये कोशिश रहती है कि वरुण उनके परिवार से बहुत दूर न जाएं. शायद इसीलिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो कई बार वरुण गांधी 10 जनपथ में देखे गए. 10 जनपथ के एक सूत्र ने मुझे ये बताया कि एक बार तो 10 जनपथ में वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी को सोनिया गांधी के साथ बातचीत करते हुए देख लिया था. वरुण गांधी को देख कर सुब्रमण्यम स्वामी मुस्कुराए. वरुण गांधी चुपचाप प्रियंका गांधी के कमरे में चले गए और वहां उनसे बात करने लगे. जब प्रियंका गांधी को वरुण गांधी ने अपने घर रात्रि भोज पर बुलाया, तो उन्होंने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने का प्रस्ताव दिया. प्रियंका गांधी के नजदीकी सूत्रों के अनुसार, वरुण गांधी इस प्रस्ताव को लेकर अचकचा गए और उन्होंने इसे नकार दिया. जब प्रियंका गांधी ने उनसे कारण पूछा, तो वरुण गांधी ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुना गया हूं और अगर मैं ऐसा करता हूं, तो ये मेरा भागना माना जाएगा. मैं अगर कांग्रेस में जाकर मुख्यमंत्री पद स्वीकारता हूं, तो लोग मुझे अवसरवादी कहेंगे. इसके पहले

(शेष पृष्ठ 2 पर)

डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए हानिकारक है | P-3

किसान आत्महत्या सरकार नहीं अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है | P-4

जनता से पाई-पाई का हिसाब और अपनी कमाई पर पर्दा | P-6

लापता वरुण गांधी का पता मिला

पृष्ठ 1 का शेष

वरुण गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच खूब घूम रहे थे. भारतीय जनता पार्टी में यह आम धारणा बन गई थी कि वरुण गांधी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं. वरुण गांधी के समर्थन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद, सुल्तानपुर और लखनऊ में पोस्टर लगाए. भारतीय जनता पार्टी में यह हवा तेजी से फैल गई कि वरुण गांधी ही मुख्यमंत्री होंगे. शायद भाजपा को ये स्थिति रास नहीं आई और एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी को अपने यहां बुलाया. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था. दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरुण गांधी से स्पष्ट कहा कि उन्हें चुनाव तक उत्तर प्रदेश नहीं जाना है. वरुण गांधी ने इसका कारण पूछा. वरुण गांधी के एक दोस्त ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा, कारण कुछ नहीं है, बस आप उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे. ये बात वहीं खत्म हो गई और वरुण गांधी प्रधानमंत्री निवास से अपने घर आ गए. वे इस स्थिति पर विचार कर रहे थे और अपने मित्रों से बातचीत कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि वे उत्तर प्रदेश न जाएं.

एक दिन अचानक वरुण गांधी के पास भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का संदेश आया कि उनसे तुरंत आकर मिलें. वरुण गांधी अमित शाह के घर उनसे मिलने गए. वरुण गांधी के एक मित्र के अनुसार, अमित शाह एक सिंगल सिटेड सोफे पर बैठे थे. उनके सामने एक टेबल रखी थी, जिसके ऊपर वे पैर रखकर बैठे हुए थे. वरुण गांधी आए तो उन्होंने स्माइल दी और उन्हें बैठने के लिए कहा. वरुण गांधी बैठे नहीं, लेकिन उन्होंने अमित शाह से कहा कि अमित भाई, क्या आप मोदी जी के सामने भी इसी तरह बैठते हैं, जैसे अभी मेरे सामने बैठे हैं. शायद अमित शाह को ये थोड़ा खराब लगा. लेकिन उन्होंने टेबल से पैर हटा लिए और बात शुरू की. अमित शाह ने कहा कि आपको ये संदेश मिल गया होगा कि आपको उत्तर प्रदेश नहीं जाना है. वरुण गांधी ने कहा कि बताइए तो, क्यों नहीं जाना है. अमित शाह ने कहा कि इसलिए नहीं जाना है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में जाने से पार्टी को काफी नुक़सान होगा. वरुण ने पूछा कि कैसे नुक़सान होगा, तो अमित शाह ने कहा कि आपके खिलाफ कुछ लोगों के पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जो मेरे पास भी हैं. मैं नहीं चाहता कि वे फोटोग्राफ्स मीडिया में आएं. अगर वे मीडिया में आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की छवि और भविष्य के ऊपर बहुत असर पड़ेगा. वरुण गांधी सन्न रह गए और कहा कि क्या मैं वे फोटोग्राफ्स देख सकता हूं. अमित शाह अंदर गए, एक लिफाफा लेकर आए और उसमें से उन्होंने फोटोग्राफ्स निकालकर सामने रखे, जिनमें वरुण गांधी जैसा दिखने वाला एक दुबला-पतला शख्स किसी एक लड़की के साथ किसी मुद्रा में था. वरुण गांधी ने उन फोटोग्राफ्स को देखा और देखकर कहा कि अमित भाई इसका एक सेट मुझे आप दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों. वरुण गांधी ने कहा कि मैं इसे अपनी पत्नी को दिखाना चाहता हूं, ताकि मेरी पत्नी ये देखे कि मैं दूसरी महिलाओं से भी मिल सकता हूं. इस पर अमित शाह हंसीनुमा मुस्कुराहट फेंकते हुए बोले, आप पत्नी को दिखाएंगे. वरुण ने कहा कि हां, आप खुद इस फोटोग्राफ को देखिए अमित भाई. मेरा जो शरीर है और इसमें जो लड़का है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. दरअसल, ये फोटोग्राफ हथियारों के सौदे में शामिल कुछ लोगों ने या तो सीबीआई को या सीबीआई के किसी सूत्र को दिए थे. इसकी कहानी ये बनाई गई कि इन फोटोग्राफ्स की वजह से वरुण गांधी ने संसद की रक्षा समिति का सदस्य रहते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां हथियारों के सौदागरों को दी है. अमित शाह ने यह भी पूछा कि क्या आप अभिषेक वर्मा को जानते हैं. वरुण गांधी ने कहा कि हां, जब मैं पढ़ता था तो हम गरीब हुआ करते थे, होटल-रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे, तब अभिषेक वर्मा तीन चार बार मिले थे और वे हम लोगों को अच्छा-अच्छा खाना खिलाते थे. उन्होंने ये भी कहा कि अभिषेक वर्मा के पिताजी और माताजी राज्य सभा के सदस्य रहे हैं और अभिषेक के पिता काफी बड़े बुद्धिजीवी माने जाते थे. उनका इंदिरा गांधी के साथ बहुत अच्छा संपर्क था और उन्होंने ही नारा दिया था कि जात पर न पात पर इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर.

इसके बाद वरुण ने उनसे कहा कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं डिफेंस कमिटी का मेंबर था और डिफेंस से संबंधित जानकारियां मैंने किसी को दी. ये सच नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी डिफेंस कमिटी की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुआ. अब अमित शाह के चौंकने की बारी थी. वरुण गांधी के नजदीकी सूत्रों के हिसाब से अमित शाह ने कहा कि लेकिन ये जानकारी तो सीबीआई के पास आई है. वरुण गांधी ने कहा कि अब आप ये देखें कि सीबीआई की जानकारी कितनी सही है, कितनी नहीं है और फिर इसमें जो लड़का है वो बहुत दुबला-पतला है. आप मुझे देख रहे हैं कि मैं दुबला-पतला नहीं हूं. दरअसल, जिस सूत्र ने ये फोटोग्राफ सीबीआई या अमित शाह के पास पहुंचाए थे और अमित शाह के जरिए शायद भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं के पास पहुंचे होंगे, उसने ये बताया कि ये फोटोग्राफ तब के हैं, जब वरुण गांधी 19 साल के थे. वरुण गांधी ने अमित शाह से कहा कि पहले तो ये मैं हूं नहीं, लेकिन मान लिजिए कि मैं अठारह उन्नीस साल का हूं और मेरा किसी से कोई रिश्ता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है. अमित शाह ने इसके जवाब में कहा कि मैंने बहुत मुश्किल से ये फोटोग्राफ रोक के रखे हैं, ये मीडिया में आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा. डेढ़ घंटे के आसपास ये बैठक चली और वरुण गांधी अमित शाह के घर से वापस आ गए. इसके 15 दिनों के भीतर ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया में और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास लिफाफे में पहुंच गए. मजे की बात कि सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इन फोटोग्राफ्स को बहुत तवज्जो नहीं दी, सिर्फ एक या दो चैनलों ने इन्हें दिखाया.

प्रियंका गांधी के नज़दीकी सूत्र बताते हैं कि इन फोटोग्राफ्स के सोशल मीडिया में आते ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने वरुण को फोन किया और कहा कि घबराना मत, इस परेशानी की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं. हम जानते हैं कि ये तुम्हारे खिलाफ किसी की साजिश है. एक सूत्र ने बताया कि राहुल गांधी ने भी वरुण को फोन कर कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. प्रियंका गांधी ने वरुण के पास ये संदेश पहुंचाया कि हम फैमिली हैं और फैमिली के सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए और एक होना चाहिए (इस जानकारी के ऊपर पक्का विश्वास नहीं है). प्रियंका गांधी के सूत्रों के हिसाब से वरुण गांधी ने इस संदेश का कोई भी सार्थक उत्तर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नहीं भेजा. वरुण गांधी के नज़दीकी सूत्र के हिसाब से, इन फोटोग्राफ्स को भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के द्वारा वितरित कराया गया, जिनमे एक खुद अमित शाह हैं और दूसरे वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं. वरुण के नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि मीडिया के साथ कैसे रिश्ते हों और कब क्या छपे, क्या नहीं छपे, इसका फैसला वित्त मंत्री अरुण जेटली ही करते हैं.

वरुण गांधी का उत्तर प्रदेश जाना बंद हो गया और उन्होंने अपने उन सारे लोगों को संकेत भेजा, जो उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रचारित कर रहे थे. वरुण गांधी ने एक दूसरा रास्ता तलाशा और उन्होंने देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाना शुरू कर दिया. अगर हम सूत्रों की माने, तो पिछले चार महीनों से वे आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र में नौजवानों के बीच घूम रहे है और विभिन्न विषयों पर भाषण दे रहे हैं. इस बीच वरुण गांधी ने हिंदू, जागरण, अमर उजाला, भास्कर जैसे अखबारों में कॉलम लिखना शुरू कर दिया.

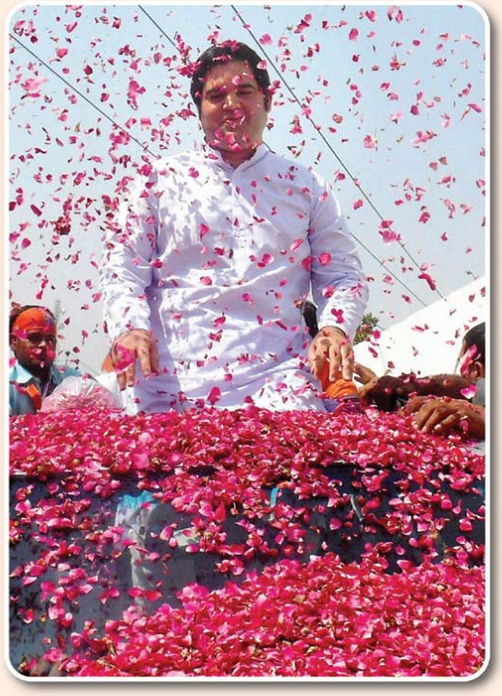

वरुण गांधी का उत्तर प्रदेश जाना बंद हो गया और उन्होंने अपने उन सारे लोगों को संकेत भेजा, जो उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रचारित कर रहे थे. वरुण गांधी ने एक दूसरा रास्ता तलाशा और उन्होंने देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाना शुरू कर दिया. अगर हम सूत्रों की माने, तो पिछले चार महीनों से वे आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र में नौजवानों के बीच घूम रहे है और विभिन्न विषयों पर भाषण दे रहे हैं. इस बीच वरुण गांधी ने हिंदू, जागरण, अमर उजाला, भास्कर जैसे अखबारों में कॉलम लिखना शुरू कर दिया. कहीं पर उनके कॉलम नियमित रूप से आते हैं, तो कहीं पर कभी-कभी आते हैं. वरुण गांधी के लिखने की शैली को पाठकों ने पसंद किया, शायद तभी ये अखबार उन्हें बार-बार छाप रहे हैं. इसके अलावा, वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को ले कर कुछ सार्थक प्रयास किए. वरुण गांधी के नजदीकी सूत्र के अनुसार, उन्होंने करीब 10 से 15 करोड़ रुपए इकट्ठे कर उन किसानों को दिए, जो कर्ज से परेशान थे और जिनके बारे में ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं वे आत्महत्या न कर लें.

वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी में इस समय कोई रोल नहीं है, लेकिन लगभग 15 से 20 सांसद वरुण गांधी को ये संदेश भेज चुके हैं कि उन्हें वरुण गांधी के साथ किया गया व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे राजनीतिक नहीं लेकिन नैतिक रूप से वरुण गांधी के साथ हैं.

वरुण गांधी इस समय उत्तर प्रदेश और भाजपा की सियासत से दूर नौजवानों और किसानों के बीच घूम रहे हैं. उसका प्रचार मीडिया में नहीं हो रहा है, लेकिन उनके कॉलम अखबारों में छप रहे हैं. इधर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वरुण गांधी को बार-बार ये संदेश भेज रहे हैं कि हम एक परिवार हैं, हमें एक साथ हो जाना चाहिए. वरुण गांधी ने इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया. अगर वे स्वीकार कर लेते, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस समय 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही होती और उसे अखिलेश यादव से गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं होती. तब उत्तर प्रदेश में एक दूसरी राजनीति का नजारा होता. वो राजनीति सफल होती या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन जो आज हो रहा है, उससे कुछ अलग हो रहा होता.

बीजेपी के कई समर्थक वरुण गांधी को मुख्यमंत्री का दावेदार नेता मानते हैं. लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया से लापता रहे या यूं कहें कि उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अलग रखा गया. चुनाव के आखिरी मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट में जगह दी है. इसलिए हमने वरुण गांधी के अंतर्धान होने, उनके खबरों से गायब होने या कैंपेन से गायब होने के कारणों को तलाशा, तो हमें ये कहानी मिली. मैं इस कहानी की सत्यता पर 90 प्रतिशत विश्वास करता हूं, क्योंकि जिन सूत्रों ने मुझे ये कहानी बताई है, उन पर मुझे पूरा भरोसा है. मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी का खंडन कहीं से नहीं आएगा.■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 50
13 फरवरी- 19 फरवरी 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए हानिकारक है

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के चुने हुए राष्ट्रपति हैं. अमेरिका में वो कैसी नीतियां लागू करते हैं और किस तरह की विदेश नीति पर चलते हैं, ये उन्हें तय करने का पूरा अधिकार है. हर सरकार को देश की आर्थिक स्थिति और लोगों की आशाओं के मुताबिक चलना चाहिए. लेकिन, अमेरिका की स्थिति दूसरे देशों से अलग है. अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर है. दुनिया के अलग-अलग इलाकों में इसकी सैन्य-उपस्थिति है. वैश्विक संस्थाओं पर अमेरिका का नियंत्रण है. साथ ही, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से अमेरिका उदारवादी प्रजातंत्र, वैश्वीकरण और बाजारवाद का झंडाबरदार रहा है. ऐसे में अमेरिका में अगर कुछ बदलाव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होना लाजमी है. भारत जैसे देशों पर कुछ ज्यादा ही असर होगा क्योंकि 1991 से हम अमेरिका द्वारा तय आर्थिक नीति पर चल रहे हैं. सोवितय रूस के खत्म होने के बाद भारत अमेरिका का एक सहयोगी राष्ट्र बन के उभरा है. मोदी सरकार के दौरान ये नजदीकियां और भी ज्यादा स्पष्ट और मुखर हो गई है. अमेरिका में एक ऐसे राष्ट्रपति का पदार्पण हुआ है जो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से चली आ रही अमेरिकी नीतियों को सिर के बल खड़ा करना चाहता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का असर भारत पर क्या होगा? क्या भारत को ट्रंप से सतर्क रहने की जरूरत है?

मनीष कुमार

जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुशियां मना रहे थे अब उनके चिंतित होने की बारी आ गई है. सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है. हालांकि, इन विरोध प्रदर्शन का क्या असर होगा, ये कहना मुश्किल है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ढोल पीटने वाले उन भारतीयों, जो भारत और अमेरिका में रह रहे हैं, को अब ये समझ में आ गया होगा कि ट्रंप की नीतियां भारत के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली हैं. सबसे पहला खतरा तो उन भारतीयों पर आने वाला है जो एच1बी वीसा लेकर अमेरिका में काम कर रहे हैं. इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो अबकी बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे. शायद अब उन्हें अमेरिका छोड़ किसी और देश या वापस भारत आना पड़े, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने प्रजातंत्र ने अब अमेरिका-फर्स्ट की नीति को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ लेते ही बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन का ऐलान कर दिया. मतलब यह कि अमेरिका में अब सरकार अमेरिकन सामान को खरीदने और सिर्फ अमेरिकी नागरिक को ही नौकरी देने की नीति पर काम करेगी.

डोनाल्ड ट्रंप सरकार की विदेश नीति का भारत पर असर क्या होगा? इसे समझने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को समझना होगा. उनके बयानों से ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां संकुचित राष्ट्रवाद से प्रेरित होगी. अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत को नुकसान होने वाला है. ट्रंप ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि एच1बी वीजा अमेरिकी नागरिकों के साथ अन्याय है. यह एक धोखा है. उन्होंने चुनाव-प्रचार के दौरान यह कहा था कि विदेश से लोग अमेरिका में आकर अमेरिकी नागरिकों की नौकरी खा जाते हैं और उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है. उन्होंने ये वादा किया था कि वो ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जिससे विदेशी नागरिकों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा. इस नीति का सबसे पहला दुष्प्रभाव टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज और इंफोसिस जैसी भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ने वाला है. जिन भारतीयों ने ट्रंप को समर्थन दिया उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि वो एक तरफ भारत को महान बताते रहे और दूसरी तरफ भारतीयों से नौकरी छीन कर अमेरिकी नागरिकों को देने का वादा करते रहे. ट्रंप ने

अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी है. इसे 35 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी कर दिया गया है. मतलब यह कि अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियां अब वापस अमेरिका की तरफ रुख करेंगी. इनमें से कई ऐसी कंपनियां भी होंगी जो फिलहाल भारत में उत्पादन कर रही है. इसका सबसे बुरा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक-इन-इंडिया पर होगा. यही वजह है कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमन्यम ट्रंप की नीतियों पर सार्वजनिक रूप से चिंता जाहिर कर चुके हैं. उनका मानना है कि एच1बी वीजा को खत्म करने से भारत के निर्यात पर नकारात्मक असर होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के अमेरिका से सचेत रहने की जरूरत है. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संरक्षणवाद की ओर ले जाने की नीतियों पर काम कर रहे हैं. संरक्षणवाद वह आर्थिक नीति है, जो विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार में निरोधक लगाता है. व्यापार निरोधक विभिन्न प्रकार से लगाये जा सकते है. जैसे, आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाना, प्रतिबंधक आरक्षण और अन्य बहुत से सरकारी प्रतिबंधक नियम, जिनका उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना और विदेशी कंपनियों द्वारा स्थानीय बाजारों और निकायों के अधिग्रहण को रोकना है. यह नीति अवैश्विकरण से संबंधित है और वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के बिल्कुल विपरीत है. यह चिंताजनक स्थिति है. अमेरिका अब तक पूरे विश्व में वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का पक्षधर रहा है. भारत जैसे देशों पर संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जैसे वैश्विक संस्थाएं बाजारीकरण का दबाव देते रहे है.

कई दशकों से लगातार अमेरिका ने पूरी दुनिया को उदारवाद, बाजारवाद और वैश्वीकरण के दलदल में ढकेलने की नीति अपनाई. अब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद अचानक इन नीतियों पर पूर्णविराम लगा दिया है. इसका असर घातक होने वाला है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों पर जो मुक्त व्यापार के देश से अभी तक उबरा नहीं है. इसकी वजह से घरेलू व्यापार और पारंपरागत कारोबार खत्म हो गए बेरोजगारी बढ़ गई. इन नीतियों की वजह से देश में गरीब और अमीर के बीच का फासला बढ़ा है. शहरों और ग्रामीण इलाकों में काफी अंतर बन चुका है. समाज में कई क्षेत्रों और स्तर पर ऐसा अंतर्विरोध पैदा हो गया है जो भविष्य के लिए एक चिंताजनक स्थिति है. कहने का मतलब यह कि बाजारवाद आधारित प्रजातंत्र का झंडाबरदार अमेरिका अब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संरक्षणवाद का पैरोकार बन जाएगा. यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में अराजकता को जन्म देगी. ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों, जहां लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, को सतर्क रहने की जरूरत है.

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विश्व-व्यापार में अराजकता तो आएगी ही, साथ ही यह भारत को नई मुसीबत में फंसाने वाला है. ट्रंप के शासनकाल में चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से और भी खराब होने के आसार नजर आ रहे हैं. साथ ही, मुस्लिम देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भी ठीक नहीं है. आंतकवाद से लड़ने के नाम पर ट्रंप ने इस्लाम को ही निशाने पर ले लिया है. इससे दुनिया भर के मुसलमान हैरान हैं. ट्रंप ने सात मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीजा देने से मना कर दिया है. माना ये जा रहा है कि पश्चिम एशिया के देश, खासकर ईरान भी डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर होंगे. पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप एक अस्थिर और आंतकवादियों का पनाहगार देश बता चुके हैं. मतलब यह कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका का सारा ध्यान मुस्लिम देशों और चीन पर होने वाला है. साउथ चाइना सी (दक्षिणी चीन सागर) विवाद की वजह से अमेरिका और चीन के रिश्ते में कड़वाहट तेज हो गई है. अगर अमेरिका और चीन के बीच आमना-सामना जैसी स्थिति बनती है, तो पूरे पूर्व-एशिया में अस्थिरता का महौल बनेगा. ऐसे हालात में भारत भी इसकी चपेट में आएगा.

भारत के लिए यह एक खतरे की घंटी है. पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं. ये रिश्ते कई सालों की मेहनत और सहयोग का नतीजा है. पश्चिम एशिया के देशों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी योजनाओं को दोनों हाथों से लिया. इन देशों ने भारत में निवेश किया. ईरान के साथ भारत के रिश्ते सुदृढ़ हैं. प्रतिबंध के बावजूद भारत ने ईरान के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा. इन देशों में काफी बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं. ये भारत की सीमा से सटे हुए नहीं हैं लेकिन पड़ोसी ही है. भारत अब तक मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को अलग-थलग करने में सफल रहा है. पश्चिम एशिया के देश पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तरजीह दे रहे हैं. भारत को अमेरिका का इस्तेमाल पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए करना है. वैसे भी आतंकवाद से निपटने के मामले में पाकिस्तान भी ट्रंप की विदेश नीति का एक केंद्र होगा. ऐसे में, भारत अपने रिश्ते अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों के साथ कैसे संतुलित करेगा, ये मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मोदी सरकार को देश के अंदर भी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है. डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और नीतियों से भारत के मुसलमान भी चिंतित हैं. ऐसे में अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियां देश के अंदर वातावरण को दूषित करेगी. वह इसलिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति तर्कहीन और सार्थक विचारों से विहीन है. मोदी सरकार पर यह दायित्व है कि उसे भारत के वर्तमान और भविष्य के हितों की भी रक्षा करनी है और साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ-साथ मुस्लिम देशों में काम करने वाले भारतीयों के हितों को भी सुरक्षित रखना है. भारत को अमेरिका से सामरिक मदद के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी साख मजबूत करने के लिए मदद भी चाहिए और मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते भी मजबूत रखने की जिम्मेदारी है. सवाल ये है कि क्या पश्चिम एशिया के देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हुए भारत ट्रंप प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकता है? मोदी सरकार को तलवार की धार पर चलना है, जरा सी चूक खतरनाक साबित हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भारत के लिए हानिकारक हो सकती है. ■

manishbph244@gmail.com

डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पर असर

डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतते ही पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई थी. डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक अस्थिर और खतरनाक देश मानते आए हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आगे बढ़ कर स्थिति को अपने अनुकूल करने की कोशिश की. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की. लेकिन यहां पाकिस्तान सरकार से एक चूक हो गई. उसने फोन पर हुई बातचीत को सार्वजनिक कर दिया. वो भी झूठा. पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कॉल किया. उन्होंने पाक को एक शानदार देश बताया और नवाज शरीफ को एक शानदार नेता बताया और पाक का दौरा करने का वादा शरीफ से किया. डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से इन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया गया. इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने न्यूयार्क भी गए. वे नी दिनों तक वहां इंतजार करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप तो दूर, उनकी टीम के अदने से अधिकारी ने भी पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार से मिलने से इनकार कर दिया.

राष्ट्रपति की शपथ लेते ही ट्रंप ने जब यह ऐलान किया कि वो चरमपंथी इस्लामिक आतंकवाद का नामोनिशान मिटा कर रहेंगे, तब से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई. इसके बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी. इन देशों में इराक, सीरिया, सूडान, ईरान, सोमालिया, लीबिया और यमन शामिल हैं. पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं था. लेकिन, पाकिस्तान को झटका तब लगा जब ट्रंप ने पहला इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों की छानबीन अब और भी कड़ाई से की जाएगी. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने भी संकेत दिया कि पाकिस्तान इस सूची का हिस्सा हो सकता है. इसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान ने लश्कर प्रमुख हाफिज सईद को छह महीने के लिए नजरबंद कर दिया है. हाफिज सईद मुंबई आतंकी हमले का मास्टर माइंड है. भारत द्वारा मुंबई में हुए आतंकी हमलों में हाफिज सईद की संलिप्तता के तमाम सबूत दिए जाने के बावजूद, सालों से वह पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से रहता आ रहा है. पाक-मीडिया के मुताबिक, यह कार्रवाई पाकिस्तान ने अमेरिका की उस चेतावनी के बाद की, जिसमें अमेरिका ने कहा कि अगर जमात-उद-दावा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा सकता है. ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जमात-उद-दावा को अमेरिका ने 2014 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था.पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो चिंता है वो जायज भी है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 17 जनवरी 2016 को ट्विटर पर लिखा था कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त नहीं है. अमेरिका ने पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ अमेरिका को धोखा मिला है. राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने आतंकवादी संगठनों के पनाहगार देशों को चिन्हित किया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था. देखना ये है कि पाकिस्तान कितने दिनों तक न्यूक्लियर बम और अफगानिस्तान में मदद के नाम पर अमेरिका को ब्लैकमेल करने में सफल रहता है. ■

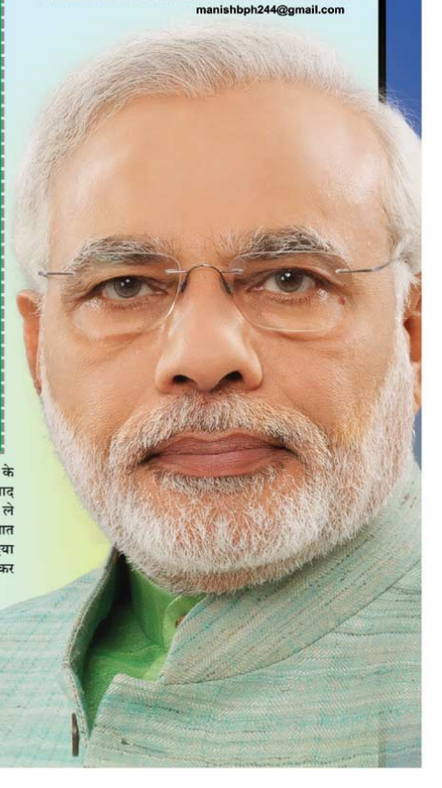

किसान आत्महत्या

सरकार नहीं अब सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा है

शफीक आलम

देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों ने किसानों की सुध लेना छोड़ दिया है. यह बात न सिर्फ किसानों की आत्महत्या के बढ़ते हुए आंकड़ों से साबित होती है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने भी इसपर अपनी मुहर लगा दी है. वर्ष 2003 से 2012 के बीच गुजरात में 600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी. इस संबंध में एक एनजीओ द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया. कोर्ट ने कहा कि किसान आत्महत्या के दो महत्वपूर्ण कारणों, क़र्ज़ और मौसम की मार से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है. कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चार हफ़्तों के भीतर इस संबंध में जवाब मांगा है.

दरअसल, किसान कल भी हालात से मजबूर हो कर आत्महत्या कर रहे थे और आज भी आत्महत्या करने पर मजबूर हैं. हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है. लेकिन इस संबंध मे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राजनेताओं की ओर से या तो उल्टी सीधी दलीलें दी जाती हैं या फिर ख़ामोशी अख्तियार कर ली जाती है. किसानों की आत्महत्या पिछले कई वर्षों से सुर्ख़ियों में है. इस दौरान कई सरकारें आईं और चली भी गईं. हालांकि सरकारों ने इस ओर ध्यान भी दिया, लेकिन मामला जहां से शुरू होता है वहीं आ पहुंचता है. आम तौर पर सरकारों की कोशिश रहती है कि मामला दबा रहे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर पहुंच जाता है तो राहत और पुनर्वास के पैकेज की घोषणा कर दी जाती है. लेकिन आत्महत्या के पीछे के कारणों से निपटने की कोशिश नहीं की जाती. लिहाज़ा साल-दर-साल यह सिलसिला चलता रहता है.

बहरहाल, जो काम सरकारों को अपना दायित्व समझ कर करना चाहिए वह काम गैर-सरकारी संस्थाएं कर रही हैं. ऐसे ही एक मामले में मल्लिका साराभाई द्वारा स्थापित एनजीओ सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव ने आरटीआई के तहत आवेदन दाखिल कर गुजरात सरकार से राज्य में 2003 और 2012 के बीच किसानों की आत्महत्या से संबंधित आंकड़े तलब किए थे. जवाब में गुजरात सरकार ने यह सूचना दी कि उस अवधि में राज्य में 619 किसानों ने आत्महत्या की थी. एनजीओ ने 41 मामलों में किसान आत्महत्या की विस्तृत जानकारी इकट्ठा की थी. इस जानकारी के मुताबिक इन किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारण थे- क़र्ज़ की बढ़ती हुई राशि, कम बारिश के कारण कपास की फसल की नाकामी, खराब आर्थिक हालात और ट्रैक्टर, बीज, खाद, कृषि उपकरण आदि की खरीद हेतु लिए गए क़र्ज़ और ब्याज के बोझ. इस सिलसिले में सबसे दर्दनाक घटना राजकोट जिले के डालडी गांव की थी, जहां अप्रैल 2013 में एक किसान परिवार ने चलती ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या की कोशिश की थी. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए थे.

सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने से पहले सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव ने प्रभावित किसानों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए गुजरात सरकार से अपील की थी और फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था. उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने केवल गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था.

सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने से पहले सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव ने प्रभावित किसानों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए गुजरात सरकार से अपील की थी और फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था. उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने केवल गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस एनवी रमना की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह बहुत अजीब बात है कि किसानों की आत्महत्या के अनेकों मामलों के सामने आने के बावजूद उनकी फसल बर्बाद होने की स्थिति में उन्हें राहत देने या उनकी सुरक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है. कोर्ट की यह टिप्पणी सरकारों के लचर रवैये की कहानी बयान कर रही है. यह टिप्पणी यह सवाल भी खड़ी करती है कि नव उदारवादी व्यवस्था की आंधी ने बुनियादी, मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी उखाड़ कर कहीं दूर फेंक दिया है. इसके लिए मौजूदा सरकार के साथ पिछली सभी सरकारें तो ज़िम्मेदार हैं ही, नागरिक समाज भी अपने आपको इस ज़िम्मेदारी से अलग नहीं कर सकता.

नोटबंदी की लीपापोती

2014 के आम चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी का एक भाषण बहुत मशहूर हुआ था. उस भाषण को सभी न्यूज़ चैनलों ने लाइव दिखाया था. उस भाषण में मोदी ने बहुत बारीकी से एक एक बिन्दू पर ज़ोर देकर स्पष्ट रूप से किसानों को समझाया था कि यदि उनकी सरकार आएगी, तो वे ऐसा प्रावधान करेंगे कि किसानों को फसल उगाने में आई लागत के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य से दो गुना ज्यादा लाभ दिया जाय. मोदी सरकार को आए लगभग तीन वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस सिलसिले में सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है. ले दे कर तान फसल बीमा पर ही टूटती है. जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है कि किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण होता है, मौसम की मार से फसल की बर्बादी और आर्थिक हानि. लेकिन आत्महत्या को मजबूर किसानों के लिए नीति बनाने की बात कौन करे, मौजूदा सरकार ने नोटबन्दी का 'साहसिक' कदम उठाकर देश के लगभग सभी किसानों को आर्थिक रूप से भारी नुक़सान उठाने पर मजबूर कर दिया.

क़ाबिल-ए-गौर बात ये है कि जब नोटबन्दी लागू की गई, उस समय खेतों में तैयार सब्जियों और फसलों के बाजारों में जाने का समय था, लेकिन जल्द खराब होने वाली वस्तु होने के कारण किसानों को उन्हें औने-पौने दामों में बेचना पड़ा. ज़ाहिर है, किसानों को इसका आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ा है. कई शोध संस्थाओं के साथ खुद भारत सरकार के इकोनोमिक सर्वे में भी यह माना गया है कि नोटबंदी की वजह से कृषी क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ा है. लेकिन किसानों को आर्थिक राहत देने की बात अब तक सुनाई नहीं दी है. इधर सरकार यह कह कर अपनी पीठ थपथपा रही है कि नोटबंदी के बाद देश में रिकॉर्ड बुआई हुई है.

बजट का पुराना राग

हालांकि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक प्रमुख अंग है. लेकिन यदि न्यायपालिका लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व से आगाह करने लगे, तो यह न तो सरकार के लिए ही ठीक है और न ही लोकतंत्र के लिए. हालांकि अपने बजट स्पीच में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पिछले वर्ष की भांती इस बार भी 'किसान' शब्द का कई बार ज़िक्र किया, लेकिन इसमें किसान आत्महत्या का कहीं ज़िक्र नहीं आया. किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने की बात की गई, लेकिन धरातल पर कोई प्रयास नज़र नहीं आया. न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई राशि आवंटित की गई और न ही किसानों की मांग के मुताबिक प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुआवज़े की राशि को 10,000 रुपया प्रति एकड़ की गई. बटाईदारों के लिए भी कोई घोषणा नहीं हुई. सबसे बड़ी बात यह है कि देश की 50 प्रतिशत आबादी, जो कृषि पर निर्भर है उसके लिए कुल बजट की 3.5 प्रतिशत राशि आवंटित करके ही अपनी पीठ थपथपा ली गई.

किसान आत्महत्या से संबंधित एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़े सरकार के लिए चेतावनी तो थे ही, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह और अधिक ज़रूरी हो जाता है कि सरकार इस संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करे और किसानों को मौत के अंधे कुएं में गिरने से बचाए. सरकार की तरफ से निराश किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी डूबते को तिनके का सहारा है.■

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र : आश्रमशालाओं में 15 साल में 1500 आदिवासी बच्चों की हुई मौत

सैकड़ों मासूमों की मौत का ज़िम्मेदार कौन

चंदन राय

महाराष्ट्र में खमगांवा ताल्लुका स्थित आश्रमशाला में 70 आदिवासी बच्चियां रहती हैं. यहां से एक बच्ची पिछले साल दिवाली की छुट्टी में अपने घर गई थी. वह घर में अपनी मां से पेट दर्द की शिकायत करती है. मां आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में ले जाती है. जांच के बाद डॉक्टर बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि करते हैं. डरी-सहमी बच्ची स्वीकार करती है कि आश्रमशाला में स्वीपर कई महीनों से उसके साथ गलत कर रहा था. उसने प्रिंसिपल से भी इसकी शिकायत की थी, पर उसे चुप रहने के लिए कहा गया. इसके बाद इसी स्कूल में एक और आदिवासी बच्ची ने स्वीपर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. दोनों बच्चियां 12 साल से कम उम्र की हैं. हालत यह है कि यहां 70 आदिवासी बच्चियों के लिए एक भी फीमेल वार्डेन नहीं है. एक साल पहले गढ़चिरौली स्थित आश्रम में एक शिक्षक ने नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. नासिक में तीन साल पहले एक आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला भी सामने आ चुका है. ये तो बस उंगलियों पर गिनने लायक कुछ आंकड़े हैं, जबकि आश्रमशालाओं की स्थिति और भयावह है. सवाल ये है कि क्या सरकारी अधिकारी इन्हीं वहशियाना तरीकों से आदिवासी बच्चियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का ख्वाब संजोए हैं. क्या आश्रमशालाओं को अय्याशी का अड्डा बनाकर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आगे बढ़ेगा?

आश्रम नहीं, मौत का कुआं : महाराष्ट्र सरकार पूरे राज्य में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए 1100 आश्रमशालाएं चलाती है. इन आश्रमशालाओं में 1.6 लाख आदिवासी बच्चियां और 2.3 लाख बच्चे रहते हैं. ट्राइबल डेवलपमेंट विभाग की योजना के तहत, इनमें से 529 आश्रमशालाओं को महाराष्ट्र सरकार चलाती है और 546 को आर्थिक सहायता देती है. अब आश्रमशालाओं की बदहाली पर भी एक नजर डाल लेते हैं. 15 साल में इन आश्रमशालाओं में 1500 आदिवासी बच्चों की रहस्यमयी स्थितियों में मौत हो चुकी है, जिसमें 740 बच्चियां हैं. अब इन बीमारियों की वजह जानकार भी आप हैरान रह जाएंगे. इनमें से 23 प्रतिशत की मौत सामान्य ज्वर, 13 प्रतिशत बच्चों की अचानक मौत, 17 प्रतिशत अज्ञात कारणों से, तो वहीं 12 प्रतिशत बच्चों की मौत का कोई कारण नहीं बताया गया है. इतना ही नहीं, यहां 31 आत्महत्या के मामले भी सामने आ चुके हैं. कह सकते हैं कि ये आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम नहीं, बल्कि एक डेथ ट्रैप है.

7 अक्टूबर 2016 को कौशल्या भारसत ने शाम 6.30 बजे वार्डेन को लूज मोशन की शिकायत की. हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. अस्पताल में रिकॉर्ड से पता चला कि वह कई दिनों से बीमार थी, लेकिन डेथ रिपोर्ट में किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया गया. शलुन्खे कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि 67 प्रतिशत आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में बीमारी का कोई कारण नहीं बताया गया है. नासिक में देवगांव स्थित आश्रमशाला के एक अधिकारी बताते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहां से 12 किलोमीटर दूर है, जबकि सिविल अस्पताल 70 किलोमीटर.

छुट्टियों से लौटने पर कराते हैं प्रेग्नेंसी टेस्ट

इन आश्रमशालाओं में आदिवासी बच्चियों का मेन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड रखा जाता है. इतना ही नहीं, घर से लौटने या अनियमित मेन्स्ट्रेशन होने पर उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट होता है. जांच समिति ने इस अमानवीय, अनैतिक और अवैधानिक प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं. परिजनों की सहमति के बिना मेन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड या प्रेग्नेंसी टेस्ट कोई स्कूल कैसे रख सकता है? एनएचआरसी ने सरकार से पूछा है कि यह आदिवासी बच्चियों की जीवन के अधिकार और गरिमा का उल्लंघन है.

हाल में एनएचआरसी ने 1500 आदिवासी बच्चों की मौत पर मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. इससे पहले भी दो नोटिस विगत वर्ष भेजे गए, पर इसे काहिली कहिए या लापरवाही, सरकार ने इसका जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा. ये आदिवासी बच्चे शिक्षा का ख्वाब लिए पहली बार अपने घरों से बाहर निकले हैं. मुफ्त शिक्षा, कपड़ा और दो समय भोजन की सुविधा ने उनके लक्ष्य को आसान जरूर किया, लेकिन असमय मौत और यौन हिंसा के भय से अब इनके परिजन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं. यही वजह है कि आश्रमशाला से ड्रॉप आउट करने वालों में बच्चियां ज्यादा हैं. हालात ऐसे हैं कि सभ्य समाज के लोग इन स्थितियों की कल्पना कर भी सिहर जाते हैं. 1500 आदिवासी बच्चों की मौत से बेपरवाह सरकार व उनके कारिंदे कब संवेदनशील होंगे? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है?■

अगर कोई बच्ची बीमार हो जाती है, तो ऐसे में हम किसी ट्रांसपोर्ट सुविधा के अभाव में प्रार्थना के अलावा और क्या कर सकते हैं.

सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट हैं आश्रमशाला : एक जांच समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि आदिवासी बच्चियों की मौत का सबसे बड़ा कारण यौन शोषण है. पैनल ने यह भी पाया कि कुछ आश्रमों की चहारदीवारी में शाम ढलते ही शिक्षक शराब का सेवन करते हैं. अधिकतर आश्रमशालाओं में शाम के बाद बिजली नहीं होने से अंधेरा छाया रहता है. ऐसे में इन स्कूलों के शिक्षक व मेल वार्डेन बच्चियों को यौन हिंसा का शिकार बना लेते हैं. लड़कियों की सुरक्षा की बात तो जाने दें, यहां कई आश्रमशालाओं में चहारदीवारी भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि सरकार व अधिकारी इन तथ्यों से अनजान हैं. हाल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने आश्रमशालाओं को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था. सवाल ये है कि इन स्थितियों की जानकारी होने पर भी सरकार आदिवासी बच्चियों की मौत पर चुप क्यों है?

अगस्त 2015 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) ने एक विस्तृत रिपोर्ट में बताया कि अधिकतर आश्रमशालाओं में हेल्थकेयर और सैनिटेशन की कोई सुविधा नहीं है. 29 फीसद सहायता प्राप्त आश्रमों और 20 फीसद सरकारी आश्रमों में ड्रेनेज की सुविधा है, बाकी आश्रमशालाओं की स्थिति नारकीय है. सरकारी प्रावधान के मुताबिक, यहां 20 बच्चियों पर एक शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, पर हालत ये है कि बच्चियां खुले में शौच जाने को मजबूर हैं. गंदगी व जमा पानी से बच्चे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं.

एक समस्या और है. आश्रमशालाओं के सभी कार्य ठीकेदारों द्वारा कराए जाते हैं. विभिन्न सामानों की खरीदारी के लिए ठेकेदारों को करोड़ों रुपयों का भुगतान किया जाता है, जहां पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है. हाल में विभाग ने आदिवासी बच्चों के लिए स्वेटर खरीदे जाने का निश्चय किया था. ठेकेदारों ने एक स्वेटर के दाम 2100 रुपए तय किए थे, जबकि उनकी वास्तविक कीमत 500 रुपए प्रति स्वेटर थी. बाद में सरकार ने तय किया कि ठेकेदारों और मिडिल मैन की बजाय यह राशि सीधे बच्चों को उपलब्ध कराई जाए. ट्राइबल डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आश्रमशालाओं के लिए फंड की कोई कमी नहीं है. अभी 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण आदिवासी बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है.

शालुन्खे रिपोर्ट में कुपोषण को आदिवासी बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण बताया गया था. 2014 में गोंडिया जिले में आश्रमशाला से 40 बच्चे इसलिए भाग गए थे, क्योंकि उनके भोजन में शीशे और प्लास्टिक के टुकड़े मिले थे. जून 2015 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि आश्रम में पोषक भोजन उपलब्ध कराना एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के समान है. एक साल से अधिक बीत गए, लेकिन आश्रमशालाओं में कोई परिवर्तन की लहर नहीं पहुंची. यहां तक कि कुछ स्कूलों में ही सेंट्रल रसोई की व्यवस्था की जा सकी है. रोटी, पुलाव और अंडे की सरकारी घोषणा तो दिवास्वप्न है, बच्चों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है. आश्रमशाला के एक शिक्षक बताते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्रत्येक बच्चे को 900 रुपए प्रति माह मिलता है, वहीं सरकारी स्कूल में बच्चों को 2500 रुपए मिलता है. इतने कम पैसे में दो टाइम भोजन और नाश्ता कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

जिस गठबंधन को बिहार में नकारा उसे यूपी में स्वीकारा

टूटी डाल पर बैताल

विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश में गठबंधन का पूरा चक्र घूम गया. अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस की और लखनऊ में रोड शो किया. लेकिन इस घटना के फौरन बाद अखिलेश के पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि वो इस समझौते से खुश नहीं हैं और न ही इसका समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि वो इस गठबंधन के पक्ष में प्रचार भी नहीं करेंगे. श्री मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है. इन 105 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों को बिना वजह पार्टी से निकाल दिया गया, अब वो क्या करेंगे.

मुलायम सिंह की इस घोषणा ने उत्तर प्रदेश में एक नई स्थिति को जन्म दे दिया है. पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अन्दर कुछ घटनाएं हुईं, जिनमें एक घटना यह थी कि अखिलेश यादव ने एक उम्र का ध्यान रखते हुए नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित किया. ये आकर्षण विचार का आकर्षण न होकर सत्ता का आकर्षण था और इनमें से बहुत सारे नौजवान वो थे, जिन्हें जिलों में सरकार द्वारा किए जाने वाले कामों का ठेका मिला. अखिलेश यादव ने शायद यह रणनीति इसलिए बनाई होगी कि अगर प्रदेश में मज़बूत नौजवान कार्यकर्ता तैयार होते हैं और उनका आर्थिक आधार भी मज़बूत होता है तो यह समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा होगा. दूसरी तरफ़ मुलायम सिंह यादव पूरे पांच साल समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे, जिन्होंने उनके साथ पिछले 15-20-25 सालों से संघर्ष किया. मुलायम सिंह का यह मानना रहा है कि जो लगातार संघर्ष में रहा है या पार्टी के साथ रहा है, उसी को विधानसभा और लोकसभा में भेजना चाहिए. लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने एक तरफ़ संभावित नौजवान उम्मीदवार तलाशे, जिन्हें उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, वहीं उन्होंने विधान परिषद में भी अपने विश्वासपात्रों को भेजा. दरअसल, अखिलेश यादव ने अधूरा काम किया. अगर वो पूरा काम करते, तो इन नौजवानों में वैचारिक शिविरों के द्वारा समाजवाद के प्रति आस्था जगाते. लेकिन इस पूरी खेप को न तो समाजवादी विचारों के बारे में पता है और न उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कोई किताब पढ़ी है. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने विचारों से और अपने जीवन से इस देश की राजनीति पर बहुत ज़बरदस्त असर डाला था.

शायद यही वजह है कि जब पार्टी में अंतर्द्वंद्व पैदा हुआ, एक तरफ़ श्री मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव हुए, दूसरी तरफ़ प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव हुए और विधायकों ने अपना समर्थन अखिलेश यादव को दिया, तो अखिलेश यादव के सामने एक परेशानी पैदा हो गई. अखिलेश यादव की एक रणनीति रही होगी कि वो विधानसभा में 400 नए विधायक लाएंगे. लेकिन जब चुनाव आयोग को ध्यान में रख विधायकों ने अपना समर्थन दिया, तो अखिलेश यादव के सामने मजबूरी हो गई कि वो उन्हें दोबारा टिकट दें. कुछ लोगों को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, जिनमें से अंबिका चौधरी और नारद राय बहुजन समाज पार्टी में मिल गए. ओम प्रकाश सिंह ने साफ़ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, इसलिए उन्हें अख़िरी वक्त में टिकट दे दिया गया.

महत्वपूर्ण अंतर्विरोध नए सिरे से यहां पैदा हुआ. वो नौजवान जो पिछले पांच साल से इस आशा में थे कि अखिलेश यादव चूंकि नौजवान हैं और पार्टी को नौजवान चेहरों में परिवर्तित करना चाहते हैं, वो सारे हतप्रभ रह गए और तब उन्होंने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे. मोटे तौर पर 80 के आस पास ऐसे प्रत्याशी हैं, जिन्होंने पिछले पांच साल समाजवादी पार्टी की अखिलेशीय शैली में राजनीति की, विभिन्न अनुशांगिक संगठनों के पदाधिकारी रहे या उसके सक्रिय कार्यकर्ता रहे, वे टिकट ना मिलने की स्थिति में बाग़ी होकर चुनाव लड़ रहे हैं. एक तरफ समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट ना मिलने की स्थिति में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. अगर इनका समाजवाद या डॉक्टर लोहिया की विचारों से वास्ता होता, या इन्होंने उनके विचारों को जाना होता, तो शायद ये अगले चुनाव का इंतजार करते, विद्रोही उम्मीदवार बनकर चुनाव ना लड़ते. दूसरी तरफ बहुत सारे वे लोग जिनकी आस्था शिवपाल यादव या मुलायम सिंह यादव में थी, उनका भी एक बड़ा तबका निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहा है. ये स्थिति बहुजन समाज पार्टी में नहीं है. इससे थोड़ी अलग स्थिति भारतीय जनता पार्टी में अवश्य है. कांग्रेस के पास बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं हैं. वहां पर उनके उम्मीदवार के रूप में समाजवादी पार्टी के ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं. अब देखना ये है कि प्रियंका गांधी चुनाव में प्रचार करती हैं या नहीं करतीं. लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इसका टालने वाला जवाब दिया कि वो तय करेंगी कि प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी. हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच यह बात बहुत पुख्ता ढंग से फैली हुई है कि मुलायम सिंह यादव के अध्यक्ष पद से हटने से पहले अखिलेश यादव प्रियंका गांधी का फोन भी नहीं उठाते थे. एक समाचार पत्र के अनुसार प्रियंका ने 11 बार अखिलेश को फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया. लेकिन मुलायम सिंह यादव के अध्यक्ष पद से हटने के बाद प्रियंका गांधी ने संभवत: डिंपल यादव के जरिए अखिलेश से संपर्क किया. इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन घोषित हो गया.

> इस गठबंधन का सबसे बड़ा अंतर्विरोध मुलायम सिंह यादव हैं. दो साल पहले जब बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे, उनके गठबंधन में कांग्रेस शामिल थी. जिसका सहारा लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के जरिए उस गठबंधन को तोड़ दिया था. उसके पहले मुलायम सिंह यादव के घर पर देश के सारे बड़े विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी, जिनमें ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला, अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला, लालू यादव, नीतीश कुमार, कमल मोरारका और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी शामिल थे. इन सबने यह तय किया था कि हम अपनी-अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर देंगे. समाजवादी पार्टी का झंडा नई पार्टी का झंडा होगा. नई पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे और वे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे. एक तरह से सारे दलों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन वो गठबंधन सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ने कांग्रेस को साथ ले लिया था. मुलायम सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जनता को गठबंधन न होने का यही कारण बताया था. अब प्रोफेसर रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के रणनीतिकार हैं, मुख्य चाणक्य हैं. दिल्ली में कांग्रेस से बात करने में उनका रोल रहा है. अब वे ही कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं. देश में अगर आज भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई विकल्प नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ दोष प्रोफेसर रामगोपाल यादव और स्वयं मुलायम सिंह यादव का है. अगर वो पार्टी बन गई होती, तो आज देश में एकमात्र विरोधी नेता मुलायम सिंह यादव होते, जिन्हें लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प मानकर 2019 की तैयारी कर रह होते. लेकिन इतिहास ऐसे ही खेल खेलाता है. उस समय अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लोगों ने बता रखा था. प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अभी एक महीने पहले घोषणा की कि अखिलेश यादव ही प्रधानमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव भविष्य के प्रधानमंत्री हैं. कांग्रेस को लेकर बन रहे इस दल के पास हरियाणा, बिहार और कर्नाटक में विधायक होते, बिहार में सरकार होती. इनका समझौता शरद पवार और ममता बनर्जी से भी हो जाता, वामपंथी भी इनके साथ होते. लेकिन इस संभावित पार्टी का शिराज़ा बिखेरने में प्रोफेसर रामगोपाल यादव प्रत्यक्ष रूप से और श्री अखिलेश यादव वैचारिक तौर पर मुख्य भूमिका निभाने वाले बन गए. और आज उसी कांग्रेस के साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव को बात करनी पड़ी और अखिलेश यादव को गठबंधन घोषित कर विधानसभा चुनाव प्रचार में साथ-साथ सभाएं करने का फैसला भी लेना पड़ा. सिर्फ मुलायम सिंह यादव अकेले हैं, जो कांग्रेस विरोध की अपनी रणनीति पर कायम हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो इस गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे. ■

समाजवादी पार्टी के बाग़ी विधायक

1. विधायक अंबिका चौधरी सपा छोड़ कर बसपा में शामिल हुए. बलिया के कोपाचीट विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया. अब वहीं से बसपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे. अंबिका चौधरी के प्रवास से कौमी एकता दल का सपा में विलय हुआ था, अब उन्हीं के चलते कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया.
2. विधायक नारद राय सपा छोड़ कर बसपा में शामिल हुए. विधायक नारद राय को भी अखिलेश ने टिकट नहीं दिया था. बसपा ने नारद राय को बलिया सदर से टिकट दिया.
3. विधायक रामपाल यादव- रामपाल यादव को अखिलेश यादव ने सीतापुर के विसवां विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया. अब वे लोकदल (सुनील सिंह) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.
4. विधायक रामवीर सिंह यादव- रामवीर सिंह भी सपा से बगावत कर लोकदल में शामिल हो गए. लोकदल ने रामवीर सिंह को उनकी सीट फिरोजाबाद के जसराना से टिकट दिया है.
5. विधायक अशफाक अली- अशफाक अली भी सपा के बागी हैं और लोकदल से चुनाव लड़ेंगे. अशफाक को लोकदल ने अमरोहा से टिकट दिया है.
6. विधायक आशीष यादव- आशीष यादव ने भी अखिलेश के खिलाफ बगावत कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया. बसपा ने आशीष यादव को एटा सदर विधानसभा सीट से टिकट दिया है. आशीष यादव उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे हैं.
7. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर- कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा में शरीक हुए हैं. भगवंतनगर से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भाजपा ने बांगरमऊ से टिकट दिया है.
8. विधायक गुड्डू पंडित- बुलंदशहर डिबाई से सपा विधायक श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित रालोद में शामिल हो गए. रालोद ने उन्हें बुलंदशहर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है.
9. विधायक मुकेश पंडित- शिकारपुर से सपा विधायक मुकेश पंडित ने भी अपने भाई गुड्डू पंडित के साथ बगावत करके रालोद का झंडा थाम लिया. रालोद ने मुकेश शर्मा को शिकारपुर से टिकट दिया है.
10. विधायक विजय मिश्रा - भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से लगातार तीन बार विधायक रहे विजय मिश्रा को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया. बागी विजय मिश्रा को पीस पार्टी और निषाद पार्टी दोनों ने ज्ञानपुर सीट से ही अपना साझा उम्मीदवार बनाया है.
11. विधायक डॉ. अजय कुमार पासी - इलाहाबाद की बारा विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. अजय कुमार पासी भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा ने बारा से ही उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है.
12. विधायक अरिदमन सिंह- आगरा की बाह विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राजा अरिदमन सिंह भाजपा में गए. भाजपा ने उन्हें बाह से प्रत्याशी बनाया.
13. विधायक रविदास मेहरोत्रा- सपा के जुझारू विधायक रविदास मेहरोत्रा का टिकट घोषित होने और नामांकन दाखिल होने के बाद अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया. आख़िरी समय में लखनऊ मध्य की प्रतिष्ठा वाली सीट अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी. अब रविदास मेहरोत्रा के निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है.

इन विधायकों को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया. अब वे मुख़ालफ़त कर रहे हैं

1. विधायक रघुराज सिंह शाक्य - इटावा जनपद की सदर सीट से विधायक रघुराज सिंह शाक्य ने अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत कर समाजवादी पार्टी छोड़ दी. शाक्य अभी बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यह स्पष्ट नहीं है.
2. विधायक नंदिता शुक्ला - गोंडा के मेहनौन विधानसभा सीट से सपा विधायक नंदिता शुक्ला का टिकट कटा.
3. विधायक राम प्रकाश सिंह - फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक राम प्रकाश सिंह का टिकट कटा.
4. विधायक वसीम अहमद- आजमगढ़ के गोपालपुर से सपा विधायक वसीम अहमद का टिकट कटा.
5. विधायक जीनत खान- पटियाली से सपा विधायक जीनत खान का टिकट कटा.
6. विधायक लाल मुनि सिंह - सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़ से सपा विधायक लाल मुनि सिंह का टिकट कटा.
7. विधायक शादाब फातिमा- जहूराबाद से सपा विधायक शादाब फातिमा का टिकट कटा.
8. विधायक राम सरन- लखीमपुर खीरी की श्रीनगर से सपा विधायक राम सरन का टिकट कटा.
9. विधायक अजीत सिंह- फर्रुखाबाद के किस्मतिया-जंगीपुर सीट से विधायक अजीत सिंह का टिकट कटा.
10. विधायक राजमति- पिपराइच से सपा विधायक राजमति का टिकट कटा.
11. विधायक बृजलाल सोनकर - मेहनगर सु. सीट से सपा विधायक बृजलाल सोनकर का टिकट कटा.
12. विधायक इंदल रावत- मलिहाबाद सु. सीट से सपा विधायक इंदल रावत का टिकट काटा.
13. विधायक प्रमोद गुप्ता- विधूना से सपा विधायक प्रमोद गुप्ता का टिकट कटा.

सपा के बाग़ी पूर्व विधायक

1. पूर्व विधायक छोटे लाल यादव - समाजवादी पार्टी के बाराबंकी से पूर्व विधायक छोटे लाल यादव लोकदल के टिकट पर बाराबंकी सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.
2. पूर्व विधायक सरवर अली- सरवर अली अखिलेश से बगावत कर पीस पार्टी में शामिल हो गए हैं. वे कुर्सी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी फरीद किदवई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

राजनीतिक चंदे में अनियमितता को सभी दलों का मौन समर्थन

जनता से पाई-पाई का हिसाब और अपनी कमाई पर पर्दा

बजट पेश होने के अगले ही दिन राजस्व सचिव का एक बयान आया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिले हुए चंदे को गोपनीय रखा जाएगा. साथ ही बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी. यानी, पहले वाले नियम में तो समीक्षा के बाद भी लूपहोल है ही, इस नए नियम के द्वारा भी राजनीतिक दलों को मनमानी के लिए स्वतंत्र रखा गया है

निरंजन मिश्रा

नोटबंदी के बाद हुई लोगों की परेशानी के बीच मीडिया और सोशल मीडिया में यह आवाज उठी कि जब आम लोगों की कमाई और पैसों के हिसाब को लेकर सरकार इतने नियम बना रही है, फिर राजनीतिक दलों को चंदे के जरिए खुला खेल खेलने की छूट क्यों दी गई है. शायद इसी का असर था कि प्रधानमंत्री को इस मामले में सफाई देनी पड़ी. 19 दिसंबर 2016 को कानपुर की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, 'राजनीतिक दलों के खिलाफ अविश्वास है. इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को हम अपनी ईमानदारी पर भरोसा दिलाएं. मैंने इस पर चर्चा करने के लिए कहा है कि राजनीतिक दलों को किस तरह से चंदा लेना चाहिए. मैं चुनाव आयोग से इसे आगे बढ़ाने और दलों पर दबाव डालने का आग्रह करता हूं. देश के हित में जो भी फैसला लिया जाएगा, हमारी सरकार उसे लागू करेगी.' प्रधानमंत्री के इस बयान और इस मामले में सरकार के कदमों की तुलना की जाय तो स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है. पहला तो यही कि इस मामले में कोई भी फैसला लेने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है, तो फिर प्रधानमंत्री किसे फैसला लेने के लिए बोल रहे हैं. इससे पहले 2015 में तो भारत सरकार ने राजनीति दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का खुलेआम विरोध किया था. 19 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि कोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग के उस फैसले को लागू कराए, जिसमें राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की बात कही गई है. इसके जवाब में 21 अगस्त 2015 को भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सरकार राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंतर्गत लाने का विरोध करती है. अगर राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आ गए होते, तो चंदे के नाम पर कालेधन का खुला खेल ही बंद हो जाता. हालांकि चंदों में पारदर्शिता को लेकर जो दूसरे नियम बने, उनमें भी सियासी सह पर अव्यवस्था साफ नजर आती है.

राजनीतिक चंदे के नए नियम भी नाकाफी हैं

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो ऐसे कदमों का ऐलान किया, जिन्हें राजनीतिक दलों के चंदों में पारदर्शिता के लिए कारगर बताया गया. लेकिन पड़ताल करने पर पता चलता है कि पारदर्शिता के मामले में इनकी भी सार्थकता नाम मात्र की ही साबित होगी. एक तरफ तो वित्त मंत्री जी ने कैश में लिए जाने वाले चंदे की सीमा घटाकर 2,000 कर दी, वहीं दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे में राजनीतिक दलों की मनमानी का एक नया विकल्प खोल दिया.

बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिशें मान ली है. अब राजनीतिक दल चेक और डिजिटल भुगतान के जरिए ही 2,000 रुपये से अधिक का चंदा ले सकते हैं. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यह सुधार राजनीतिक वित्त पोषण में काफी पारदर्शिता लाएगा और आगे कालेधन पर रोक लगाएगा. लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो, इस कदम में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसके जरिए चुनावी चंदों में पारदर्शिता लाई जा सकती है. जिस तरह से दलों ने पुराने नियम का तोड़ निकाला और अपनी अधिकांश कमाई को 20,000 से कम की राशि में ही दिखाया था. उसी तरह से इस नए नियम को भी राजनीतिक दल ताक पर रख सकते हैं. सियासी पार्टियों के सामने यह विकल्प खुला रखा गया है कि वे अलग-अलग नामों से रसीद कटाकर 2,000 से कम में कितना भी चंदा ले सकते हैं. इसलिए उनके लिए यह मुश्किल नहीं कि वे अपने अधिकांश चंदे को 2,000 से कम की राशि में ही मिला हुआ दिखा दें. दूसरे कदम के रूप में अरुण जेटली ने यह कहा कि सरकार ने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. दानदाता चेक के जरिए बॉन्ड खरीद सकते हैं. यह धनराशि संबंधित राजनीतिक पार्टी के पंजीकृत खाते में चली जाएगी. बजट पेश होने के अगले ही दिन राजस्व सचिव का एक बयान आया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिले हुए चंदे को गोपनीय रखा जाएगा. साथ ही बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी. यानी, पहले वाले नियम में तो समीक्षा के बाद भी लूपहोल है ही, इस नए नियम के द्वारा भी राजनीतिक दलों को मनमानी के लिए स्वतंत्र रखा गया है.■

इलेक्टोरल ट्रस्ट में फर्जीवाड़ाः राजनीतिक पार्टियों और कॉर्पोरेट कंपनियों के बीच चंदे के लेन-देन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2013 में इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी थी. इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी. हालांकि 2013 से पहले भी कुछ इलेक्टोरल ट्रस्ट थे, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया करते थे. इन ट्रस्ट्स को 2013 के गाइडलाइन से दूर रखा गया, जिससे इन्हें पैसों का खुला खेल खेलने का छूट मिल गया. ये ट्रस्ट चंदों के वितरण में सीबीडीटी के मानकों का भी पालन नहीं करते हैं. ऐसे छह इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भी सवाल उठाया था. एडीआर ने कहा था कि इनकी कार्यप्रणाली को देखकर लगता है कि ये या तो कर-माफी के लिए बनाए गए हैं या काला धन को सफेद करने के लिए. हालांकि ये सभी ट्रस्ट राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में चंदा देते रहे हैं, लेकिन उसका हिसाब नहीं देते. एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इन छह इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2004-05 से 2011-12 के बीच राजनीतिक दलों को 105 करोड़ का चंदा दिया. लेकिन किसी भी ट्रस्ट ने यह नहीं बताया कि उसके पास इतनी रकम आई कहां से. इन छह में से एक ट्रस्ट ने तो केवल 2014-15 में अकेले ही सात पार्टियों को 131.65 करोड़ का चंदा दिया है. लेकिन इसने भी कोई जानकारी नहीं दी है कि उसे किन कंपनियों से या कहां से इतने पैसे मिले. एडीआर ने मांग की थी कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इन ट्रस्ट को भी 2013 के नियमों के दायरे में लाना चाहिए और इन पर दबाव बनना चाहिए कि वे उन कंपनियों का नाम सार्वजनिक करें जिनसे उन्हें चंदा मिला.

चुनावी चंदे के नाम पर कालेधन का खुला खेल खेलने वाले इन ट्रस्ट पर केंद्रीय सूचना आयोग ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है. पिछले महीने ही केंद्रीय सूचना आयोग ने आयकर विभाग को आदेश दिया कि 2003-04 के बाद बने इलेक्टोरल ट्रस्ट के नामों की सूची सार्वजनिक की जाय. साथ ही यह भी बताया जाय कि क्या उन्हें टैक्स में कोई छूट मिली है. आयोग ने ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के वितरण के ब्योरे की भी मांग की है.

हमाम में सब नंगे हैंः एडीआर ने पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट जारी किया. इस रिपोर्ट के आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं कि राजनीतिक चंदे के नाम पर किस तरह से पर्दे के पीछे पैसों का खुला खेल चल रहा है. 24 जनवरी को जारी किए गए इस रिपोर्ट में एडीआर ने कहा है कि 2004-05 से 2014-15 के दौरान राजनीतिक दलों को कुल 11 हजार, 367 करोड़ 34 लाख रुपए चंदे के रूप में मिले. जिनमें से 7 हजार 855 करोड़ की राशि अज्ञात स्त्रोतों से मिली है. गौरतलब है कि अब तक यह नियम था कि 20,000 से ज्यादा के चंदे का ही हिसाब देना पड़ता था. इसलिए दलों ने अपनी 69 फीसदी कमाई को 20,000 से कम के चंदे में ही दिखा दिया. इन 11 सालों के दौरान कांग्रेस को 3 हजार 323 करोड़ अज्ञात स्त्रोतों से मिले, वहीं इस दौरान भाजपा का बेनामी चंदा 2 हजार 125 करोड़ 95 लाख है. क्षेत्रीय दलों की बात करें, तो इस दौरान समाजवादी पार्टी को 766.27 करोड़ रुपये जबकि शिरोमणि अकाली दल को 88.06 करोड़ रुपये अज्ञात स्त्रोतों से मिले. मायावती की पार्टी बसपा ने तो अपने पूरे चंदे को ही अज्ञात स्त्रोतों से मिला हुआ बता दिया. यह हैरान करने वाली बात है कि स्त्रोत दिखाए गए चंदे की राशि मात्र 1 हजार 835 करोड़ है. एडीआर की इस रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय दलों को अज्ञात स्त्रोतों से हुई आमदनी 274.13 करोड़ रुपये थी, जो 2014-15 में बढ़कर 1,130.92 करोड़ रुपये हो गई. इस दौरान क्षेत्रीय दलों की आय भी 37.393 करोड़ रुपये से बढ़कर 281.01 करोड़ हो गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड चुनाव

मुख्यधारा की पार्टियों से परेशान जनता ने उतारे जन उम्मीदवार

चौथी दुनिया ब्यूरो

देवकी नंदन शाह

गुड्डू लाल

सुशील बहुगुणा

मनमोहन लखेड़ा

गणेश भट्ट

मोहन काला

हाल के वर्षों में जिस तरह से राजनीतिक दल जन सरोकारों से दूर होते जा रहे हैं, इससे आम जनता में यह भावना प्रबल हुई है कि वह चुनावों में अपनी भूमिका सिर्फ एक मतदाता तक सिमित न रखे और अपनों के बीच से अपना प्रतिनिधि चुने. इसी भावना के तहत उत्तराखंड में जनता का एक वर्ग इस विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में सार्थक करने के लिए कमर कस चुका है. सियासी पार्टियों के मायाजाल से लोकतंत्र को निकालने के जनता के इस प्रयास को खूब समर्थन भी मिल रहा है. उत्तराखंड के कई इलाकों में इन जन उम्मीदवारों की धमक महसूस की जा सकती है. आम लोग भी मान रहे हैं कि दलों के दलदल में फंसने से अच्छा है कि इन जन उम्मीदवारों को समर्थन दिया जाय.

गौरतलब है कि 2013 में उत्तराखण्ड में अपने 10 दिनों की जनतंत्र यात्रा रैली में अन्ना हजारे ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन राजनीतिक विकल्प के तौर पर जन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे. इन जन उम्मीदवारों के लिए अन्ना जी ने कहा था कि ये वे लोग होंगे जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं होना चाहिए और न ही अन्य कोई दाग होने चाहिए. अन्ना हजारे के इस ऐलान के बाद से ही जन उम्मीदवारों की स्वीकार्यता बढ़ने लगी थी. अब स्थानीय स्तर पर काम करने वाले संगठन भी जन उम्मीदवारों के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की आवाज बुलंद करने वाले संगठन किसान मंच ने भी जन उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है. किसान मंच की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप द्वारा की गई थी, जिसकी शाखाएं भारत की सभी प्रदेशों में हैं. वीपी सिंह का स्वर्गवास होने के बाद किसान मंच कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था. लेकिन अब कमल मोरारका और विनोद सिंह सहित कई लोगों द्वारा इस मंच को सक्रिय करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया जा रहा है. किसान मंच ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में छह प्रत्याशियों को जन उम्मीदवार के रूप में उतारा है. किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशि वर्मा, व किसान मंच के उपाध्यक्ष, अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व रामायण, विक्रम बेताल जैसे सिरियलों के निर्माता श्री चन्द जैन ने 24 जनवरी को इन नामों की घोषणा की.

किसान मंच ने उत्तराखंड चुनाव के लिए जिन छह जन उम्मीदवारों को उतारा है, वे इस प्रकार हैं-

1. सुशील बहुगुणा- बहुगुणा टिहरी विधानसभा सीट से जन उम्मीदवार हैं. ये सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं. इनकी संस्था रॉट्स ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करती है. शादी समारोहों में कॉकटेल पार्टी बन्द कराने के प्रयास के लिए बहुगुणा को पुरस्कृत किया जा चुका है.

2. गणेश भट्ट- भट्ट देवप्रयाग विधानसभा से जन उम्मीदवार हैं. भट्ट ने डडूवा में शराब की फैक्ट्री के विरोध में आत्मघाती आंदोलन किया था, जिसके बाद यहां शराब की फैक्ट्री का शासनादेश निरस्त हुआ. गणेश भट्ट ने कीर्तिनगर में तहसील बनाने के लिए भी आंदोलन चलाया था जो सफल रहा.

3. मोहन काला- मोहन काला लोकप्रिय समाजसेवी व उद्योगपति हैं, जो श्रीनगर विधानसभा से जन उम्मीदवार हैं. 2013 की केदारनाथ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए इन्होंने विशेष सहयोग किया था. अब भी आपदा प्रभावित दर्जनों बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं. इसके अलावा वे खेल, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं को भी समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं. इन्होंने धर्मशाला व मठ-मंदिरों के संरक्षण के लिए भी बहुत से काम किए हैं.

4. एडवोकेट देवकी नंदन शाह- देवकी नंदन शाह पौड़ी विधानसभा क्षेत्र से जन उम्मीदवार हैं. इन्होंने इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव निर्दलीय जीता है. शाह कई समाजिक आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं एवं ईमानदार छवि के लिए प्रख्यात हैं.

5. मनमोहन लखेड़ा- लखेड़ा देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट से जन उम्मीदवार हैं. ये वर्तमान में श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही पूर्व में देहरादून प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे हैं. पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण में इनकी भूमिका उल्लेखनीय है.

6. गुड्डू लाल- गुड्डू लाल चमोली जिले की थराली विधानसभा (आरक्षित) सीट से जन उम्मीदवार हैं. गरीब परिवार से संबंध रखने वाले गुड्डू जनहित के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. विकास खंड घाट में महाविद्यालय निर्माण के लिए आंदोलन के साथ-साथ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते रहते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में यूपी का साइड इफेक्ट

सरोज सिंह

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से जनता दल (यू) के अलग रहने का फैसला हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दल का अपना निर्णय है, पर सूबे की राजनीति के लिए यह सहज-सामान्य परिघटना नहीं है- विशेष तौर पर सत्तारूढ़ महागठबंधन के लिए. नीतीश कुमार अपने 'मिशन 2019' के तहत वहां के विधानसभा चुनावों में अपनी भूमिका को आकार देने में गत एक साल से लगे थे. यहां तक कि वहां अपनी उपस्थिति का अहसास करवाने के लिए उनकी पार्टी अकेले भी चुनाव मैदान में जाने को तैयार थी. बिहार प्रदेश जद (यू) के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह इस बारे में स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर चुके थे. सब कुछ तय था, दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी गई थी. पर ऐन मौके पर लंबे विचार-विमर्श के बाद जद (यू) नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से दल को अलग रखने का निर्णय ले लिया. वहां के चुनावों में दल का उम्मीदवार न देने का तो निर्णय लिया ही गया, यह भी फैसला हुआ कि उसके नेता वहां किसी के पक्ष-विपक्ष में चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे. इस फैसले के कई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं. यह फैसला दल के भीतर हिलकोरें पैदा कर रहा है. यह सूबे के सत्तारूढ़ महागठबंधन के तीनों दलों के आपसी संबंध में तनाव के नए रंग भरने का माद्दा रखता है. बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने लगातार तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 20 नवम्बर 2015 को आयोजित उक्त समारोह में भारतीय राजनीति के गैर भाजपाई नक्षत्रों को इकट्ठा किया गया था. इसके बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका तय करते हुए दो कदम उठाए. वह जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति के विस्तार के रोड-मैप को अघोषित तौर पर जारी किया था. चूंकि पटना से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है, लिहाजा उसे अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखना उनकी राजनीतिक जरूरत थी. उन्होंने वही किया.

नीतीश कुमार ने पिछले एक साल में मिशन 2019 के एक विशिष्ट अवयव के तौर पर ही मिशन उत्तर प्रदेश चलाया. बिहार के बाहर उनकी

2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जद (यू) ने कोई पौने तीन सौ उम्मीदवार दिए थे और मतदान में किसी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची थी. दल के सूत्रों पर भरोसा करें तो इस बार भी दलील दी गई कि अकेले चुनाव में उतरने से परिणाम में कोई तात्विक फर्क नहीं आएगा. हालांकि दल के सीनियर नेता शरद यादव ने धन की कमी को चुनाव न लड़ने का कारण बताया, पर उससे बड़ा कारण वोट की कमी का माना गया.

राजनीति का मूल केन्द्र उत्तर प्रदेश ही बना. एक साल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन की प्राण-प्रतिष्ठा की. वाराणसी, इलाहाबाद सहित आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जद (यू) की रैली और कार्यकर्त्ता सम्मेलन किए गए. पूर्ण शराबबंदी अभियान को लेकर भी नीतीश कुमार लखनऊ, कानपुर व अन्य स्थानों पर आयोजित समारोहों में भाग लिए और बिहार के अनुभवों को साझा किया. पार्टी को चुनाव के लायक बनाने के लिए अपने विश्वस्त महासचिव आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी. चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से ऐन पहले किसी दौर में मुख्यमंत्री के खास रहे संजय झा को महासचिव बनाया गया. नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में दल के सांगठनिक विस्तार की व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक मंच हासिल करने की भी पूरी कोशिश की. इस सिलसिले में सबसे पहले पीस पार्टी के सुप्रीमो अयूब के साथ जद (यू) की बात हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसकी अच्छी पैठ होने की बात बताई जा रही है. खबर आई कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब फाइनल टच देना ही बाकी रह गया है. पर, इस फाइनल टच का क्या हुआ, अब तक पता नहीं चला. फिर, अपना दल के एक गुट से बातचीत की खबर आई. पर, इसका क्या हस्र हुआ, यह भी किसी को पता नहीं चला. चौधरी अजित सिंह के राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के साथ जद (यू) के संबंध की बात तो बार-बार सामने आई. यह बातचीत दोनों दलों के विलय से आरंभ हुई थी. इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ी और सक्रिय भूमिका निभाई थी. फिर, तालमेल पर मामला आ कर टिक गया. अजित सिंह के पुत्र जयंत चौधरी दो-तीन बार पटना भी आए. मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं से उनके मिलने की भी खबर आई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजित सिंह के विशेष प्रभाव के कारण जद (यू) सुप्रीमो नीतीश कुमार भी उनसे तालमेल को उत्सुक ही दिख रहे थे. पर बात रास्ते से भटक गई और यह धुरी भी जद (यू) के दायरे से बाहर चली गई, दोनों अलग-अलग ही रह गए. अजित सिंह का भी अनेक कोशिश के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं हो सका. बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन में नीतीश कुमार के सहयोगी कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस गठबंधन के साथ अपनी सहमती जता दी. हालांकि यह उसकी पूर्व की घोषणा के अनुरूप ही था. ऐसे में जद (यू) को तय करना था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अखाड़े में बगैर किसी सहयोगी के अकेले ही उतरना है या रिंग के बाहर बैठ कर पहलवानों के दांव देखने हैं. दल ने दूसरा विकल्प चुना.

इस निर्णय का एक संदेश यह भी गया कि इतनी मेहनत के बावजूद पिछले पांच साल में वहां जद (यू) की हैसियत कोई खास बनी नहीं. 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जद (यू) ने कोई पौने तीन सौ उम्मीदवार दिए थे और मतदान में किसी प्रत्याशी की जमानत नहीं बची थी. दल के सूत्रों पर भरोसा करें तो इस बार भी दलील दी गई कि अकेले चुनाव में उतरने से परिणाम में कोई तात्विक फर्क नहीं आएगा. हालांकि दल के सीनियर नेता शरद यादव ने धन की कमी को चुनाव न लड़ने का कारण बताया, पर उससे बड़ा कारण वोट की कमी का माना गया. किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव न लड़ने का यह कारण तो कतई सम्मानजनक नहीं है. उत्तर प्रदेश के सवाल पर दल में फिलहाल खामोशी है. इस फैसले ने नीतीश कुमार और जद (यू) के बाहर-भीतर उनके 'भक्तों' को भीतरी टीस दी है. यह घाव तो फूटेगा, पर कुछ दिन बाद. यह स्थिति जद (यू) नेतृत्व के लिए खतरनाक बन सकती है.

उत्तर प्रदेश का मसला जद (यू) में जो भी हालात पैदा करे, बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन को भी तनावों से भर देने की पुरकश हैसियत रखता है. सूत्रों पर भरोसा करें, तो नीतीश कुमार को महागठबंधन के सहयोगियों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद हो गई थी. हाल के हफ्तों में जद (यू) के अनेक छोटे-बड़े नेता वहां भाजपा को पराजित करने के लिए बिहार की तर्ज पर महागठबंधन की जरूरत पर जोर दे रहे थे. लेकिन सपा में जारी उठा-पटक में इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था. सपा के विवाद के कुछ हद तक शांत होने के बाद वहां जब गठबंधन की बात चली तो सपा नेतृत्व ने कांग्रेस के अलावा किसी को तरजीह ही नहीं दी- रालोद को भी नहीं. हालांकि इन सबके बावजूद जद (यू) नेतृत्व को उम्मीद थी कि सरकार का साझीदार होने के कारण कांग्रेस और राजद उनका पक्ष रखेंगे और महागठबंधन बनाने पर जोर डालेंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. राजद खुद अपनी पूछ के लिए परेशान रहा, तो सपा के नेतृत्व से कांग्रेस को भी जरूरत भर ही तवज्जो मिली. कांग्रेस जब खुद ही सपा के कंधे पर जगह पाने को ललायित थी तो दूसरे के लिये क्या करती. राजद नेतृत्व तो इसका ही इंतजार करता रह गया कि कोई उससे भी कुछ पूछ ले. इस पूरे प्रकरण में कुछ और राजनीतिक तथ्य भी कांग्रेस व राजद नेतृत्व के जेहन में रहे. बिहार विधानसभा चुनावों से महीनों पहले नीतीश कुमार को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करवाने में कांग्रेस की भूमिका जगजाहिर है. ऐसी घोषणा के कारण ही सबसे बड़ा दल होने के बावजूद महागठबंधन सरकार में राजद ने पहले नम्बर की बात कभी नहीं की और दूसरे नम्बर पर रहने को विवश रही. उसके बाद भी जब-जब राजद ने सार्वजनिक तौर पर आंखें कड़ी करने का मन बनाया, तो उस पर लगाम कसने में भी कांग्रेस आगे आई. इसके अलावा भाजपा के साथ नीतीश कुमार के मधुर होते रिश्ते को भी दोनों सहयोगी दलों ने अनदेखी करने की कोशिश ही की. नोटबंदी व अन्य कई मुद्दों पर जद (यू) व नीतीश कुमार के स्टैंड इसके प्रमाण के तौर पर पेश किए जा रहे हैं. ऐसे में बताने की आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस या कोई दूसरा भाजपा विरोधी दल किस दूरी तक जद (यू) की वकालत करेगा. पर गठबंधन की राजनीति में एक दायरे में रहते हुए किसी की अपेक्षा पर दूसरा दल कैसे लगाम लगा सकता है, जब तक सब कुछ खुला खेल न बन जाए. वस्तुतः एक साथ सारे लाभ नहीं हासिल किए जा सकते हैं, वह राजनीति की बात ही क्यों न हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी फैसले पर असहमति से खुलकर सामने आई है भाजपा की गुटबाजी

रघुवर दास के लिए मुसीबत बनते मुंडा

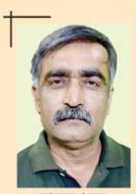
प्रशान्त शरण

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के आरोपों से आहत पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अब रघुवर के खिलाफ बाण चलाने के लिए अपनी तरकश तान ली है, और कभी भी झारखंड में राजनीतिक भूचाल ला सकते हैं. मुंडा ने सीएनटी एसपीटी एक्ट को अपना हथियार बनाया है और इसी बहाने मुख्यमंत्री रघुवर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विपक्षी दल के साथ-साथ सरकार में शामिल सहयोगी पार्टी आजसू भी मुंडा की इस मुहिम का खुलकर साथ दे रही है. भाजपा छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने तो आदिवासी भावना जगाकर अर्जुन मुंडा की तारीफों के पुल बांध दिए. साथ ही प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पर्दे के पीछे से मुंडा के साथ हो गया है. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि अर्जुन मुंडा के पास भाजपा के 22 विधायकों के साथ ही अन्य दलों के लगभग 25 विधायकों का समर्थन प्राप्त है.

गौरतलब है कि झारखंड भाजपा में अब दो धुरी बन गए हैं. रघुवर और मुंडा के बीच छत्तीस का रिश्ता जगजाहिर है. झारखंड में आदिवासी विधायकों का एक बड़ा तबका अर्जुन मुंडा के साथ है. वे इस समर्थन के कारण ही काफी उत्साहित हैं और कभी भी सत्ता परिवर्तन की क्षमता रखते हैं. इसका भली-भांति अहसास मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी है. लेकिन अपनी पीठ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हाथ होने के कारण वे अहंकार से चूर हैं. यही कारण है कि वे न तो पार्टी में और न ही प्रशासन में किसी को तवज्जो देते हैं. वे पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा एवं उनकी टीम को किनारा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. झारखंड में भ्रष्टाचार एवं विकास न होने का दोष रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री मुंडा पर थोप दे रहे हैं. मुंडा भी पार्टी में अब अपने को असहज महसूस करने लगे हैं. दो साल शांत बैठने के बाद अब उन्होंने सरकार के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुंडा भी अब रघुवर दास से आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं.

एक पखवाड़ा पूर्व जमशेदपुर में हुए प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दोनों नेताओं ने नाम लिए बिना एक-दूसरे पर जमकर हमला बोला. मुंडा ने सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ ही आदिवासी एवं मूलवासी से जुड़े मुद्दे को लेकर रघुवर दास पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिना इन लोगों के हित को ध्यान में रखे नए संशोधन और अधिनियम लाए जा रहे हैं. इसके कारण आदिवासी और मूलवासियों में आक्रोश पनप रहा है और इससे पार्टी की छवि भी धूमिल हो रही है. मुंडा का यह स्पष्ट कहना था कि कोई भी कानून आदिवासियों की हित को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए. एक तरह से उन्होंने इस सरकार को आदिवासी और मूलवासी विरोधी ही बता दिया. वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुंडा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी नेता विरोधी दलों के नेता की भाषा में बात नहीं करें, साथ ही यह भी कहा कि किसी भी बात को पार्टी मंच पर लाने की जरूरत है न कि विरोधियों की तरह सार्वजनिक मंच से आरोपों की बौछार करने की. उन्होंने मुंडा पर निशाना साधते हुए कहा कि चौदह साल में झारखंड का विकास नहीं हो पाया, केवल लूट मची हुई थी, भ्रष्टाचार चरम पर था. मैंने काफी हद तक भ्रष्टाचार पर काबू पाया है और अब राज्य में विकास की गंगा बहनी शुरू हुई है, तो पार्टी के कुछ नेता ही विरोध का रास्ता थाम लिए हैं. गौरतलब है कि इन चौदह सालों में लगभग नौ साल अर्जुन मुंडा ही राज्य के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे थे. मुख्यमंत्री एक तरह से अर्जुन मुंडा को ही राज्य का विकास नहीं होने का दोषी मान रहे हैं.

मुंडा और रघुवर के बीच छत्तीस का रिश्ता कोई नया नहीं है. दोनों ही कोल्हान प्रमण्डल की राजनीति में सक्रिय थे. मुंडा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी, पर बाद में भाजपा में शामिल हो गए. झारखंड

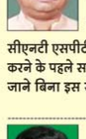

जब कोई संगठन या परिवार बड़ा होता है, तो कुछ मनभेद होते ही हैं, पर इसे मतभेद कहना बिल्कुल गलत होगा. एक तरफ सरकार बखूबी काम कर रही है, वहीं रघुवर दास एवं अर्जुन मुंडा पूरी क्षमता के साथ संगठन बढ़ाने में लगे हुए हैं.

-लक्ष्मण गिलुवा

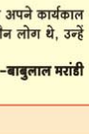

सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन से आम जनमानस पर सीधा असर पड़ा है. संशोधन करने के पहले सभी पहलुओं पर सोचना चाहिए, पर सरकार ने इसका दूरगामी परिणाम जाने बिना इस संशोधन को पारित करा दिया.

-अर्जुन मुंडा

मुंडा को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि किस लॉबी के दबाव में वे अपने कार्यकाल में सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन लाने वाले थे. इसके पीछे कौन लोग थे, उन्हें बताना चाहिए. इस संशोधन के विरोध पर मेरी पार्टी उनके साथ है.

-बाबुलाल मरांडी

गठन के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार में कल्याण मंत्री बने, लेकिन राजनाथ सिंह का आशीर्वाद मिलते ही बाबूलाल की सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बन गए. वहीं रघुवर दास के राजनीतिक कद को छोटा करने का प्रयास करते रहे. हद तो तब हो गई जब भाजपा झामुमो गठबंधन में रघुवर दास उप-उपमुख्यमंत्री थे और शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत को उपमुख्यमंत्री का पद दिया गया था. कहा जाता है कि मुंडा ने शिबू से इसी रणनीति के तहत बात की और गुरुजी को आश्वस्त किया कि हेमंत का राजनीतिक कद बढ़ाने में सहयोग करेंगे. इसके बाद रघुवर दास और अर्जुन मुंडा की दूरियां बढ़ती ही गई और दोनों एक-दूसरे के कट्टर राजनीतिक विरोधी हो गए.

राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले मुंडा को रघुवर ने इस बार पटकनी दे दी. विधानसभा चुनाव में भी उन्हें मात खानी पड़ी और रघुवर दास अपनी जाति का सहारा लेते हुए अमित शाह के करीबी हो गए और मुख्यमंत्री का ताज मुंडा ने छीन ली. स्वजातीय होने के कारण रघुवर दास राष्ट्रीय अध्यक्ष के कृपापात्र बने हुए हैं. लेकिन अब रघुवर के लिए यह ताज कांटो भरा साबित हो रहा है. सरकार में शामिल आजसू तो सरकार के खिलाफ मुखर हुई ही है. मंत्रिमंडल में शामिल सरयू राय ने भी एक तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. अब देखना है कि रघुवर दास, राष्ट्रीय नेताओं के बलबूते कितने दिनों तक सरकार चलाने में सफल रह पाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

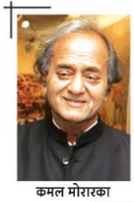

कमल मोरारका

यह सरकार नीतिगत अभाव से जूझ रही है

पूरा बजट बदले की भावना से भरा हुआ है. हालांकि बजट में अच्छी चीजें भी हैं. जैसे, कम आमदनी वालों को टैक्स में छूट दी गई है और करों में कटौती कर के छोटे कॉरपोरेट्स को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है. ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट आवंटन की राशि में थोड़ा इज़ाफ़ा किया गया है. जैसे, मनरेगा की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है. ऐसा इसलिए हो सकता है कि वित्त मंत्री वित्तीय घाटे को 3.2 फ़ीसदी तक सीमित रखना चाहते हों. हालांकि इसमें तर्क नहीं है. भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने भी वित्तीय घाटे को 3 फीसदी तक सीमित रखने की बात कही थी. लेकिन ये ऐसा साल है, जिसमें वित्तीय घाटे को 4 फ़ीसदी तक रखना चाहिए था. इससे बड़े पैमाने पर निवेश की प्रक्रिया शुरू होती. बहरहाल, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर हम उनकी आलोचना कर सकते हैं.

आइए इस बार पेश हुए आम बजट पर एक नज़र डालते हैं. देश में एक अजीब घटनाक्रम चल रहा है. आम तौर पर सरकार या प्रधानमंत्री के पास अपनी नीतियों की स्पष्ट समझ और दृष्टिकोण होती है. अगर कभी सरकार में अस्थिरता होती भी है, तो गठबंधन के सहयोगियों के अलग व्यवहार के कारण. अभी जो अजीब बात है, वो यह कि संख्या के लिहाज़ से यह सरकार पूरी तरह से स्थिर है, क्योंकि सत्ताधारी दल के 282 सांसद हैं और उनके अलावा उनके सहयोगी भी हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री और उनके नज़दीकी राज़दारों के दिमाग में पूर्ण अस्थिरता है.

प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की नीति के तहत दूसरे देशों से निवेश आकर्षित करना चाहते हैं. वे औद्योगिकरण और रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि कर व्यवस्था को सरल बनाया जाय. वे कई अन्य चीजों के अलावा यह भी चाहते हैं कि लोग आधुनिक बने और जितना संभव हो सके पारदर्शी अर्थव्यवस्था अपनाएं. लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बड़े पैमाने पर संशोधन की आवश्यकता है. मौजूदा सरकार के द्वारा चार बजट पेश किए जा चुके हैं, लेकिन इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया है. आयकर प्रणाली वैसी ही है, जैसी यूपीए के शासनकाल में थी. आयकर विभाग जैसे पहले था (अच्छा, बुरा या भ्रष्ट) अब भी वैसा ही है. केवल मेक इन इंडिया का जाप कर के आप बदलाव कैसे ला सकते हैं? कंपनियों को लाने के लिए आपको चीजें आसान करनी होंगी. दरअसल, चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या राहुल गांधी को गाली दे कर भारत को महान बनाने की राजनीतिक चाह पूरी नहीं की जा सकती. इससे आगे बढ़ने की राजनीतिक इच्छा और कमजोर होती है. जब देश के संचालन की बात होती है, तो ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं. देश के मतदाताओं ने देश के संचालन का अधिकार आपको दिया है. आपके पांच साल के कार्यकाल में से तीन साल निकल गए हैं. आप यूपीए के 10 साल की पुनरावृति नहीं कर सकते. अगर ऐसा करेंगे तो उसे यह ज़ाहिर होगा कि नया करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है. मतदाताओं को यह संदेश जाएगा कि अगली बार फिर से उन्हें (यूपीए को) ही सत्ता में ले आइए, क्योंकि वे देश के लिए कुछ कर रहे थे.

अब विजय माल्या का मामला ही देख लीजिए. विजय माल्या पर बात करने से पहले मैं यह साफ़ करता चलूं कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. सामाजिक तौर पर मैं उनको बहुत अधिक नहीं जानता. लेकिन यह मेरी समझ से परे है कि आप एक व्यक्ति को इतना कैसे डरा सकते हैं कि वो अपना लोन वापस न करने की स्थिति में देश छोड़ कर भाग जाए. उसके बाद अब इस मसले को सुलझाने के बजाय वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कहते हैं कि हम कानून को इतना सख्त बनाएंगे कि कोई अगर कर्ज लेने के बाद देश छोड़ कर भागे, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. अपने लोगों के साथ आपका ये बर्ताव है! ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य है, उसने देश की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस संचालित की, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर के विदेशी निवेशकों को आप क्या सन्देश देना चाहते हैं? जब आपके देश के प्रमुख लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो एक विदेशी निवेशक यहां आ कर कैसे सुरक्षित महसूस करेगा. जाहिर है कि आप उसे

> **सुप्रीम कोर्ट भी कोई गौरवपूर्ण काम नहीं कर रहा है. पहले तो उसने सुब्रत रॉय को बिना किसी आरोप के, बिना एफआईआर के, बिना ट्रायल के जेल में रखा. ये सर्वोच्च अदालत द्वारा स्थापित अच्छा उदाहरण नहीं है. अब, बीसीसीआई की बात करते हैं. यहां मुख्य शिकायत ये है कि कुछ लोग हमेशा पॉवर में रहते हैं. जैसे, अरुण जेटली, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, राजीव शुक्ला आदि. तो क्या अदालत इन्हें हटाएगी और क्रिकेट के संचालन के लिए उन्हें बहाल करेगी, जो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते?**

गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि उसका दूतावास इसमें हस्तक्षेप करेगा. टीवी पर ये प्रचारित किया जा रहा है कि विजय माल्या और ललित मोदी को निशाना बनाया जाएगा. ये बहुत छोटी सोच है. सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन काम बहुत छोटे (तुच्छ) करती है.

पूरा बजट बदले की भावना से भरा हुआ है. हालांकि बजट में अच्छी चीजें भी हैं. जैसे, कम आमदनी वालों को टैक्स में छूट दी गई है और करों में कटौती कर के छोटे कॉरपोरेट्स को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है. ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट आवंटन की राशि में थोड़ा इजाफा किया गया है. जैसे, मनरेगा की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है. ऐसा इसलिए हो सकता है कि वित्त मंत्री वित्तीय घाटे को 3.2 फीसदी तक सीमित रखना चाहते हों. हालांकि इसमें तर्क नहीं है. भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने भी वित्तीय घाटे को 3 फीसदी तक सीमित रखने की बात कही थी. लेकिन ये ऐसा साल है, जिसमें वित्तीय घाटे को 4 फीसदी तक रखना चाहिए था. इससे बड़े पैमाने पर निवेश की प्रक्रिया शुरू होती. बहरहाल, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर हम उनकी आलोचना कर सकते हैं. वित्तीय घाटा एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिमान है, जिसपर हर व्यक्ति अपना अलग नजरिया रख सकता है. मेरे हिसाब से एक विकासशील देश सिर्फ वित्तीय घाटे के बारे में हमेशा नहीं सोच सकता है. मुद्रीकृत घाटा और महंगाई दर मापने रखते हैं. यदि उच्च वित्तीय घाटा बर्दाश्त किया जा सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. आप इंफ्रास्ट्रक्चर और नई परियोजनाओं आदि पर भारी निवेश सीमित संसाधनों से नहीं कर सकते, आपको अपने संसाधन के आधार को विस्तार देना होगा. कहने का मतलब ये है कि इस बजट के विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है. ये अच्छा बजट है. जहां तक अरुण जेटली का सवाल है, उन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया है. उन्होंने गरीबों को राहत देने की कोशिश की है. लेकिन एक बार फिर अखबार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रो-पुअर (गरीब के हित में) और एंटी-रिच (अमीर विरोधी) बजट है. अगर ये अमीर विरोधी बजट होता तो फिर शेयर मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए था. शेयर मार्केट में उछाल क्यों आया? मैं इस तर्क को नहीं समझ पा रहा हूं कि अचानक शेयर मार्केट गरीबों का कैसे हो गया. हमें ये समझना होगा कि इस सरकार में पॉलिसी डेफिसिट (नीतिगत कमजोरी) है.

अब राजनीतिक दलों के चंदे को ही देख लीजिए. ये किस तरह का संशोधन है कि 20 हजार की बजाय एक आदमी केवल 2 हजार रुपये ही नगद में चन्दा दे सकता है. क्या इस देश में लोगों की कमी है? अब एक नकली रसीद की जगह राजनीतिक दलों को दस नकली रसीद काटने पड़ेंगे. हम क्या कर रहे हैं? यह एक विचारविहीन फैसला है. प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे कुछ सोचते हैं और दोपहर में लोगों से उसे लागू करने के लिए कहते हैं, फिर हर व्यक्ति उस काम में लग जाता है. कोई उनसे तर्क-वितर्क नहीं करता, क्योंकि वे ऐसा पसंद नहीं करते हैं.

ये तो बजट हुआ. अब दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट भी कोई गौरवपूर्ण काम नहीं कर रहा है. पहले तो उन्होंने सुब्रत रॉय को बिना किसी आरोप के, बिना एफआईआर के, बिना ट्रायल के जेल में रखा. ये सर्वोच्च अदालत द्वारा स्थापित अच्छा उदाहरण नहीं है. अब, बीसीसीआई की बात करते हैं. यहां मुख्य शिकायत ये है कि कुछ लोग हमेशा पॉवर में रहते हैं. जैसे, अरुण जेटली, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, राजीव शुक्ला आदि. तो क्या अदालत इन्हें हटाएगी और क्रिकेट के संचालन के लिए उन्हें बहाल करेगी, जो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते? क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है, जिसमें भारत दुनिया में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. आप इसे नष्ट कर देना चाहते हैं. बेशक, आप इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी अच्छे हैं, वे अच्छा खेलेंगे ही. लेकिन, अदालत कर क्या रही है? अदालत बीसीसीआई से कह रही है कि जो राज्य लोढा कमेटी के समर्थन में वोट नहीं कर रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं दो. कल को अदालत अटॉर्नी जनरल से कह सकती है कि जो राज्य नरेन्द्र मोदी को सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा बन्द कर दिया जाना चाहिए. क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं? क्या यह धनतंत्र है? क्या हम किसी हास्यासपद तंत्र में रह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को इन सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए. अब जस्टिस ठाकुर जा चुके है. जस्टिस खेहर ने उनकी जगह ले ली है, जो अपनी ईमानदारी और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं. उन्हें इन दोनों मामलों (सुब्रत रॉय और बीसीसीआई) की फिर से समीक्षा करनी चाहिए. इसमें कोई हानि नहीं है यदि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को रद्द कर सामान्य स्थिति कायम कर देता है. ऐसा करने में सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर चोट नहीं पहुंचेगी. जैसे बीसीसीआई चल रहा था वैसे चलने दें. अगर वहां कोई गलत काम हो रहा है, तो देश का कानून वहां पर लागू होगा. अगर कोई गलत तरीके से चुन कर आता है, तो देश का कानून इस पर लागू होगा. अगर कोई सही तरीके से चुन कर आता है, तो उसे आने दीजिए. आप उसे क्यों रोक रहे है? कांग्रेस ने कई सालों तक देश पर शासन किया, कोई अदालत उसे रोकने नहीं आई. लोगों ने सरकार बदली. मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा उदाहरण नहीं पेश कर रहा है. अमेरिका में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं. इंग्लैंड में भी यही सिस्टम है. वहां जज, जज की नियुक्ति नहीं करते हैं. भारत ही एक ऐसा देश है, जहां सुप्रीम कोर्ट इतना सुप्रीम (बड़ा) हो गया है कि वे अपने लोगों की नियुक्ति खुद ही करते हैं और हर बात पर टिप्पणी करते हैं. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक समय ऐसा आएगा, जब लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना विश्वास खोने लगेंगे. ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात होगी. सुप्रीम कोर्ट इस बात को जितनी जल्दी समझ लेगा, उतना ही बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू के मुसलमानों के साथ भी न्याय होना चाहिए

शुजात बुखारी

जम्मू-कश्मीर में फिर से सांप्रदायिक कलह की आशंका पैदा हो गई है. इसी तरह की स्थिति 2008 में देखी गई थी, जब अमरनाथ भूमि विवाद के कारण दो क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर (घाटी) के बीच नाजुक संबंधों में दरार आ गई थी. इस बार का विवाद पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ लाख शरणार्थियों के अधिकारों पर केंद्रित है. 1947 में विभाजन के समय, पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदू और सिख परिवार जम्मू आ गए थे. इन परिवारों की संख्या आज बढ़ गई है. उस समय भारत के अन्य भागों में बसे अन्य 'शरणार्थियों' की तुलना में इन शरणार्थियों को कुछ अलग अधिकार मिले हुए हैं.

कश्मीर में बहुत सारे लोग इसे एक मुस्लिम बहुल राज्य की आबादी के स्वरुप को बदलने के प्रयास के रूप में देखते हैं. एक शिकायत यह भी है कि जम्मू के डिवीजनल प्रशासन ने राजस्व मंत्रालय को नजरअंदाज कर सीधे भारत सरकार से आदेश लिया. यह घटना इस तथ्य को भी सत्यापित करती है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं अलग-अलग हैं. एक संयुक्त संसदीय समिति ने इन शरणार्थियों को अन्य लोगों के साथ ही मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की थी. राज्य सरकार ने हाल ही में उन्हें आवास प्रमाण पत्र जारी किए, लेकिन इसकी वजह से यह शक पैदा हुआ कि कहीं यह कदम इन लोगों को राज्य में पूरी तरह से जोड़ने की प्रक्रिया तो नहीं है. अगला कदम उन्हें राज्य का नागरिक प्रमाण पत्र देना होगा. लोगों का तर्क है कि उन्हें आवास प्रमाण पत्र देने के लिए अन्य तरीकों जैसे आधार कार्ड जारी करने का इस्तेमाल किया जा सकता है.

ये शरणार्थी सही मायने में कई समस्याओं का सामना कर रहे है, जिनका सहानुभूति पूर्वक समाधान करने की जरूरत है. लेकिन इन समस्याओं से निपटने में राज्य सरकार बड़ा जोखिम उठा रही है. दरअसल, एक बहस पहले ही कश्मीर में शुरू हो चुकी है. इस सन्दर्भ में संघ परिवार का विभाजनकारी हिन्दू राष्ट्रवाद का एजेंडा इस मामले को और भी हवा दे रहा है, जिसमें घर वापसी यानी मुसलमानों और ईसाइयों को हिन्दू धर्म में वापस लाना भी शामिल है.

बहस का एक हिस्सा संख्या और आबादी के स्वरूप के विवाद में फंस गया है. पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी संगठन के अध्यक्ष, लाभा राम गांधी का दावा है कि केवल 5,764 हिंदू और सिख परिवार 1947 में पलायन कर जम्मू से आए थे. लेकिन अब उन परिवारों की संख्या बढ़ कर 25,460 हो गई है, जिनमें कुल 1,50,000 लोग रहते हैं. कुछ लोगों को इन आंकड़ों पर एतराज है. जम्मू के मुसलमानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर काम करने वाले एक विशेषज्ञ के अनुसार, उस समय इन शरणार्थी परिवारों की संख्या लगभग 12,000 थी, जो आज बढ़कर अवश्य ही 50,000 हो गई होगी. जिनकी आबादी अनुमानत : 3,00,000 होगी. वे कहते हैं कि ऐसे कई परिवार हैं, जो इस संगठन के साथ पंजीकृत नहीं हुए. वास्तविक आंकड़ा जो भी हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्हें आवास अधिकार देने का फैसला राजनीति से प्रेरित है. सबसे विवादास्पद सिफारिश, उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान करने की है. भाजपा इस मुद्दे को चर्चा का विषय बना रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में इसका जिक्र कर रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है. लोग यह भी देख रहे हैं कि पीडीपी चुपचाप इन घटनाओं का अनुमोदन कर रही है.

भविष्य में यह फैसला उन ताकतों को मदद पहुंचाएगा, जो सीटों की संख्या के मामले में जम्मू को कश्मीर के बराबर देखना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि कश्मीर के मतदाताओं पर निर्भर रहे बिना उन्हें राज्य में सत्ता मिल सके. हालांकि विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2026 तक नहीं होगा, लेकिन इस कदम से उन पार्टियों को फलने-फूलने का मौका मिलेगा, जो 'भेदभाव' और 'कश्मीरी वर्चस्व' को हथियार बनाती हैं.

जिस तरह पलायन पर बहस जोर पकड़ रही है, उस तरह एक और पलायन हुई थी, जिसपर कोई बात नहीं हो रही है. एक सवाल यह भी है कि इन शरणार्थियों को 1947 में जम्मू ही क्यों भेजा गया? उन्हें भारत के किसी अन्य हिस्से में क्यों नहीं भेजा गया? जैसे-जैसे इतिहास के पन्ने खुलते गए, यह स्पष्ट होता गया कि यह काम राज्य की आबादी के स्वरूप को बदलने के उद्देश्य से किया गया था. शायद 3 लाख मुसलमानों के कत्ल के साथ-साथ यही तरीका था, जम्मू की मुस्लिम बहुल क्षेत्र की पहचान को बदलने का. दहते डोगरा राजशाही ने जाते-जाते अपनी उस प्रजा को यह 'अनमोल उपहार' (नरसंहार) दिया था, जो सदियों से उसकी वफादार रही थी. आज जम्मू में मुस्लिम आबादी मात्र 5 फीसदी है, जबकि 1947 में यह 39 फीसदी थी. उसी तरह 1947 में कठुआ जिले में 30 फीसदी मुस्लिम थे, आज मात्र 8 फीसदी रह गए हैं. कश्मीरी पंडितों के पलायन के पच्चीसवें वर्षगांठ पर 19 जनवरी 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर लिखते हैं कि हमारा मीडिया अपने स्वतंत्र और मजबूत भाषण पर गर्व करता है, फिर भी उसने कथित राष्ट्रीय हित से संबंधित कुछ मुद्दों पर साजिश भरी चुप्पी साध रखी है. स्वामीनाथन

> **जम्मू के मुसलमानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर काम करने वाले एक विशेषज्ञ के अनुसार, उस समय इन शरणार्थी परिवारों की संख्या लगभग 12,000 थी, जो आज बढ़कर अवश्य ही 50,000 हो गई होगी. जिनकी आबादी अनुमानत : 3,00,000 होगी. वे कहते हैं कि ऐसे कई परिवार हैं, जो इस संगठन के साथ पंजीकृत नहीं हुए. वास्तविक आंकड़ा जो भी हो, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्हें आवास अधिकार देने का फ़ैसला राजनीति से प्रेरित है.**

अय्यर का इशारा 1947 में बड़े पैमाने पर हुए मुसलमानों की हत्या और पलायन की तरफ था. उन्होंने लिखा कि इस कहानी को इस निराशाजनक बरसी पर याद किया जाना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर से गए करीब 1.2 मिलियन शरणार्थी मुख्य पाकिस्तान (पीओके के अलावा) में रहते हैं. उनमें से लगभग 1.1 मिलियन तत्कालीन जम्मू और कठुआ जिलों से गए हुए लोग हैं. किस तरह से उनकी हत्या हुई और उन्हें अपना घर छोड़ना पडा, उसकी कहानी प्रतिष्ठित पत्रकार वेद भसीन ने बयान की है. 2003 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि यह योजना महाराजा की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाई गई थी. मीर चंद महाजन (प्रधानमंत्री) एक बार तब जम्मू आए थे, जब सांप्रदायिक दंगें हो रहे थे. उन्होंने कुछ अल्पसंख्यक नेताओं को आमंत्रित किया, जिसमें सांप्रदायिक दल और नेशनल कांफ्रेंस भी शामिल थे. त्रिलोक चंद दत्त, गिरधारी लाल डोगरा और ओम सर्राफ वहां थे. मैं भी एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में वहां उपस्थित था. महाराजा पैलेस में उन्होंने कहा था कि सत्ता जब जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों को दी जा रही है, तो आप हिंदू और सिख समानता की मांग क्यों नहीं करते हो? समानता का मतलब हिंदू और मुसलमान (मुस्लिम लीग) में बराबर का प्रतिनिधित्व. ओम सर्राफ को छोड़कर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया. सर्राफ ने कहा कि हम कैसे समानता की मांग कर सकते हैं? हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या में भारी अंतर है. मुसलमानों के पास एक विशाल बहुमत है, हिंदू अल्पसंख्यक हैं. यह कैसे व्यावहारिक और संभव है? इस पर मीर चंद महाजन ने महाराज पैलेस के नीचे एक वन क्षेत्र (जहां कुछ गुर्जरों के शव पड़े हुए थे) की ओर इशारा करते हुए कहा कि जनसंख्या बदल भी सकती है. भसीन कहते हैं कि इसका क्या मतलब था? इन शरणार्थियों के पास कोई पूर्ण अधिकार नहीं था, सिवाए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में आरक्षित आठ सीटों के.

पाकिस्तान में रहने वाले जम्मू एवं कश्मीर के शरणार्थियों की वापसी के लिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक पुनर्वास विधेयक 1977 में (जिसे बिल संख्या 9 के नाम से भी जाना जाता है) ले कर आए. यह बिल 1954 तक पलायन कर चुके लोगों के लिए था. लेकिन अभी तक इस बिल पर कोई निर्णय नहीं हो सका है.

अभी जब पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, ऐसे में कोई भी उनकी बात नहीं करता है, जो न केवल 1954 बल्कि 1990 के बाद भी सीमा पार से होने वाली गोलाबारी से बचने के लिए पाकिस्तान में पलायन कर गए. ऐसे लोगों की संख्या 35,000 से अधिक है और वे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक कठिन जीवन जी रहे हैं. कश्मीरी पंडितों की वापसी और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हुए लोगों, इन दोनों मुद्दों का समाधान एकरूपता के साथ निकालना चाहिए. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आज की राजनीति ग़रीबों के हितों के ख़िलाफ़ है

जिन दिनों कांग्रेस देश में प्रमुख सत्ताधारी पार्टी हुआ करती थी और दिल्ली व देश के कई राज्यों में कांग्रेस का राज था, उस समय एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ. उस सिद्धांत का नाम था गैर कांग्रेसवाद. वो सभी राजनीतिक दल, जो सत्ता में नहीं थे, वो गठबंधन बनाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की तकनीक पैदा कर चुके थे. इसके मुख्य सिद्धांतशास्त्री डॉ. राममनोहर लोहिया थे. उत्तर प्रदेश में पहली संविद सरकार इसी सिद्धांत के आधार पर बनी थी. जो दल गैर कांग्रेसवाद के समर्थक थे, उनके सिद्धांतों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं भी थीं. इस गैर कांग्रेसवाद का पहला बड़ा प्रयोग सन् 77 में हुआ, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी लोग साथ आए. जनता ने उनका समर्थन किया और श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में दिल्ली में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी. दूसरा गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय हुआ, जिसमें सिर्फ कांग्रेस के विरोध को आधार बनाकर वामपंथी, दक्षिणपंथी, केंद्रीय, मध्यमार्गी सभी साथ आए और 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी.

यहां से एक नया चलन शुरू हुआ. देश में धार्मिक आधार पर राजनीति का चेहरा बदलने लगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने लगी. श्री अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में सरकार बनी. इस सरकार में बहुत सारे वो लोग शामिल हुए, जो गैर कांग्रेसवाद के कट्टर समर्थक थे और सांप्रदायिकता के धुर विरोधी थे. अटल जी की सरकार तीन बार बनी. इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आई, जिसके नेता नरेन्द्र मोदी थे. यहीं से गैर भाजपावाद का एक नया सिद्धांत शुरू हुआ. इस सिद्धांत के जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक विचार था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेन्द्र मोदी निकट भविष्य में कमजोर होते नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे लोग इकट्ठे हों. इस सिद्धांत को मूर्त रूप देने की बात राजनीतिक दलों में तेजी से चलने लगी. बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव के साथ कांग्रेस भी गठबंधन में आई. वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक होकर मुकाबला किया और उसे हरा दिया.

गैर भाजपावाद के नाम पर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं की बैठक हुई. इसमें एक नयी पार्टी बनाने का फैसला किया गया, लेकिन वो फैसला इसलिए सिरे नहीं चढ़ पाया क्योंकि हवा में ये बात फैली कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के ही एक प्रमुख नेता के जरिए इस गठबंधन को बनने से रोक दिया. उत्तर प्रदेश के चुनाव में गैर भाजपावाद का प्रयोग पूरी तौर पर नहीं हो

पाया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस प्रयोग को करने से इंकार कर दिया. उसे ये लगा कि अगर वो सभी दलों को इकट्ठा करेंगे, तो सभी को कुछ न कुछ सीटें देनी पड़ेंगी, इसलिए सिर्फ कांग्रेस के साथ समझौता किया जाए. इसके साथ ही पहली बार इतिहास में समाजवादी पार्टी की पिछली तीस साल पुरानी राजनीति समाप्त हो गयी. मुलायम सिंह अकेले हो गए और उनके बेटे अखिलेश यादव ने उन्हीं की नीतियों की धज्जियां उड़ा दीं. वे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा कर रहे हैं. वे सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही मिलकर सरकार बनाने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह गठबंधन आगे दिल्ली के चुनाव में भी चलेगा, इसकी घोषणा कर रहे हैं. शायद मुलायम सिंह अपनी आंखों के सामने अपनी राजनीति की चिता जलती देख रहे हैं.

दरअसल इस पूरे सिद्धांत पर एक बार नये सिरे से सोचना चाहिए. कांग्रेस, आरजेडी और जद यू के सिद्धांतों में कितनी समानता और असमानता है, इसका विचार बिहार में नहीं हुआ. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों में क्या समानता और असमानता है, इसका भी कोई विचार नहीं हुआ. सिर्फ एक विचार हुआ कि हमें बुनियादी आधार, सत्ता और सत्ता में हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए. इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं बचा. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन बनाए. उनके गठबंधन का नाम एनडीए है. उसमें ऐसी पार्टियां शामिल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी नीतियों से सहमत नहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी नीति धार्मिक राजनीति के अलावा समान नागरिक आचार संहिता और कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना है. यह अंतर्विरोध कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी विचार के आधार पर कुछ कर रहे हैं, ये अप्रासंगिक हो गया है. अब सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत बचा है और वो है सत्ता.

> **अब ये मान लेना चाहिए कि सिद्धांत, विचार, गरीब, नौजवान, पिछड़ा और दलित इनके प्रति समर्पण या इनके हितों के प्रति प्राथमिकता अब ये कोई मायने नहीं रखते. अब मायने रखते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता. उस सत्ता के लिये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग गठबंधन में हैं, उनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी नीतियां नहीं मानते और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बना रहे हैं, उनमें और कांग्रेस की बुनियादी नीतियों में बहुत अंतर है.**

यहीं देश के विकास के अंतर्विरोध के बीज दिखाई देते हैं. वो अंतर्विरोध हैं कि हिन्दुस्तान के 70 प्रतिशत लोग, जो गांवों में रहते हैं, जो गरीब और वंचित हैं, उन्हें उनके हिस्से का विकास शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा. पहले समाजवादी सिद्धांत का आधार यह था कि सबसे पहले वंचितों, दलितों, पिछड़ों, औरतों और गरीबों को हिस्सा मिले, उसके बाद जो देश की संपत्ति बच जाती है, दूसरे वर्गों को दी जाए. वामपंथी भी इसी राय के थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. जिस तरह से दलों के गठबंधन हो रहे हैं, उनमें वैचारिक सिद्धांत की जगह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नाम का शब्द ज्यादा बोला जाता है. इसकी वजह से देश में गरीबी, असमानता बढ़ रही है, गांव में कुपोषण बढ़ रहा है, शिक्षा समाप्त हो रही है या कहें कि कॉर्पोरेट के हाथ में जा रही है. खेती विदेशी ताकतों के हाथ में जा रही है. स्वास्थ्य भी कॉर्पोरेट के हाथ में जा रहा है. गरीब के लिए कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें हैं नहीं. पहले ही उसके मरने के कम साधन नहीं थे, अब वो और ज्यादा बढ़ गये हैं.

अब ये मान लेना चाहिए कि सिद्धांत, विचार, गरीब, नौजवान, पिछड़ा और दलित इनके प्रति समर्पण या इनके हितों के प्रति प्राथमिकता अब ये कोई मायने नहीं रखते. अब मायने रखते हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता. उस सत्ता के लिये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग गठबंधन में हैं, उनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी नीतियां नहीं मानते और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बना रहे हैं, उनमें और कांग्रेस की बुनियादी नीतियों में बहुत अंतर है.

इन दोनों तरह की राजनीति को मैं अवसरवादिता की राजनीति मानता हूं. मेरा मानना है कि एक नयी तरह की राजनीति होनी चाहिए, जिनमें अगर गठबंधन बनाना है तो दलों को एक दूसरे के साथ विलय कर देना चाहिए. गठबंधन का मतलब मैं मानता हूं सैद्धांतिक समानताएं. हर दल प्रदेश या देश की जनता के सामने अपनी नीतियों को रखे और ये कहे कि उसी को सबसे ज्यादा समर्थन क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो सबमें अच्छा है. लेकिन जहां पर गठबंधन आता है वहां जनता के हित की बात समाप्त हो जाती है और जनता के हित के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों की आभा क्षीण हो जाती है, उनकी ताकत समाप्त हो जाती है. मेरा ये मानना है कि इस राजनीति से उलट कोई राजनीति होनी चाहिए. वो राजनीति हाल-फिलहाल में होगी, पता नहीं, फिर भी हम लोगों के सामने अपना मंतव्य तो रखना ही चाहते हैं. जबतक सिद्धांत, विचार और गरीबों के प्रति समर्पण की राजनीति शुरू नहीं होगी, तबतक इस देश में उस विचार के प्रबल रूप से बढ़ने की संभावना दिखायी देगी, जो विचार गठबंधन या लोकतंत्र के खिलाफ हैं. अब इसे रोकना है या नहीं रोकना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका फैसला तो जो राजनीति में हैं, वो करें. पर आज की राजनीति और गठबंधन कम से कम लोकतंत्र या इस देश के गरीबों के पक्ष में तो नहीं हैं और न ही गरीबों के पक्ष में आवाज उठाने की इच्छा रखते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

कमज़ोर होता फ़िलिस्तीनी आंदोलन

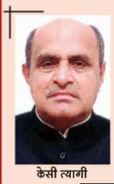

केसी त्यागी

फिलिस्तीन को लेकर पश्चिम एशिया के देशों में हलचल बढ़ रही है. फरवरी में ईरान की राजधानी तेहरान में फिलिस्तीनी एकजुटता को लेकर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 150 मुल्कों के सांसद व राजनयिक आमंत्रित हैं. आयोजन की खबर से फिलिस्तीन समर्थकों में एक बार फिर उत्साह का संचार हुआ है. इससे पूर्व 28-29 नवम्बर 2016 को एक ऐसा ही आयोजन तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आयोजित हुआ था, जिसमें 400 से अधिक सांसद व राजनेता आमंत्रित थे. अधिकतर प्रतिनिधि एशिया, अफ्रीका तथा लातिन अमेरिका के थे. सम्मेलन की मेजबानी तुर्की संसद के अध्यक्ष इस्माइल कहरमन तथा उद्घाटन वहां के राष्ट्रपति रिसेप तैयप द्वारा किया गया था, जिससे समारोह की अहमियत और बढ़ गई थी. संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 29 नवम्बर को फिलिस्तीन की राजधानी रमाल्लाह से लेकर विभिन्न देशों की राजधानियों में फिलिस्तीनी एकजुटता दिवस मनाया गया था. कई मायनों में सफल रहने के बावजूद सम्मेलन में अमेरिकी विरोध का फीकापन स्पष्ट नजर आ रहा था. नाटो के जन्मकाल से ही तुर्की अमेरिकी सैन्य संगठन का संस्थापक सदस्य है. अमेरिका द्वारा इजरायल को प्रारम्भ से दी जा रही सैन्य सुविधाएं जगजाहिर हैं. अपने बाह्य-आंतरिक राजनीतिक समस्याओं से घिरे होने के बावजूद तुर्की फिलिस्तीनियों की शांति के लिए संघर्षरत रहा है. नये वर्ष के पहले दिन हुए आतंकी हमले तथा पिछले वर्ष 15 जुलाई को तख्ता पलट की घटना से यह देश अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है. 300 से अधिक लोगों की मौत, तीस हजार से ज्यादा लोग, जिसमें सेना के अफसर, विश्वविद्यालय व कॉलेज के प्राध्यापक, बड़े सामाजिक-धार्मिक लोग शामिल हैं, को बंदी बनाया जाना निश्चित रूप से बड़ी घटना है. पुष्ट खबर है कि एक धार्मिक संगठन और उसका अगुआ, जो अमेरिका में शरणार्थी बना हुआ है, का इस मुहिम को समर्थन प्राप्त था. एफ-16 जहाजों, बख्तरबंद गाड़ियों, हेलिकॉप्टर व टैंकों द्वारा राष्ट्रपति निवास व संसद भवन पर भयंकर बमबारी की घटनाएं भयभीत करने वाली हैं. तुर्की आईएसआईएस समेत दक्षिणपंथी धार्मिक संगठनों के मुहाने पर स्थित है. हालिया हमला इस खबर को पुष्ट भी करता है. कभी धार्मिक नेता कमाल अतातुर्क ने इस्लामी दुनिया में सुधारवादी आंदोलन चलाकर पूरी दुनिया को आंदोलित किया था. फिलहाल वहां इतना भय का माहौल है कि समारोह व अन्य आयोजन खुफिया पुलिस तथा फौज की निगरानी में संपन्न हो पाता है.

नवंबर में आयोजित सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा फिलिस्तीन की समस्या और उनकी बदहाली का जिक्र किया गया. संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा पारित प्रस्ताव 242 तथा 338 का अमल नहीं करने पर इजरायल सरकार की निंदा भी की गई. फिलिस्तीनी सरजमीं के अलावा येरूशलम स्थित अलास्का मस्जिद भी पूरे समारोह के दौरान चर्चा का विषय बना रहा. इसे पैगम्बर से जुड़ा पवित्र स्थान माना गया है. वहां इस समय सुरक्षा कारणों को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबियों की आवाजाही पर रोक है. पहले फिलिस्तीनियों की मुक्ति के समर्थन में आयोजित ऐसे आंदोलनों में फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के सर्वोच्च नेता यासिर अराफात के चित्र कार्यक्रम स्थल की शोभा बढ़ाया करते थे. अफसोसजनक रहा कि इस बार ऐसा नहीं हुआ. राष्ट्रपति ने भी इस बार उनका जिक्र करना उचित नहीं समझा. यह घटना फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहा. एक-दो प्रतिनिधियों को छोड़कर अधिकतर प्रतिनिधियों ने अमेरिका के दखल की निंदा करने से भी गुरेज ही किया. पूर्व में ऐसे विषयों पर आयोजित सम्मेलनों में मुख्य चर्चा अमेरिकी साम्राज्यवाद के दखल और उसके क्रिया-कलापों पर आधारित होती थी. इजरायल सरकार की आलोचना अवश्य की गई, लेकिन यहूदीवाद पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, वह नदारत रही. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही इजरायल व यहूदियों ने वहां डेरा जमाना शुरू कर दिया, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का

> **संयुक्त राष्ट्र में भी फिलिस्तीन पर हमले पर भारत न तो एतराज़ जताता है, न ही इज़रायल के विरुद्ध वोटिंग में अपनी निर्णायक भागीदारी निभाता है. प्रधानमंत्री मोदी की इज़रायल यात्रा और वहां के उभ्र प्रधानमंत्री की संभावित भारत यात्रा से दोनों ही देशों के राजनयिक संबंधों में मधुरता संभव है, जिसके फलस्वरूप दर्जनों सौदे व दूरगामी दोस्ती के आसार हैं. अंततः इनके परिणाम फिलिस्तीनी हितों के विरुद्ध ही होंगे.**

खुला समर्थन प्राप्त था. उस समय अब्दुल गुलाम नासिर अरब के बड़े नेता के रूप में उभरे थे, जिनका फिलिस्तीन को खुला समर्थन प्राप्त था. पंडित नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जोर पकड़ने पर चाउ-एन-लाई, मार्शल टीटो, एनक्रुमा तथा सुकार्णो जैसे नेता खुलेआम फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे. भारत पहला गैर अरब मुल्क था, जिसने फिलिस्तीन को मान्यता देकर राजनीतिक संबंध स्थापित किया. अफसोस है कि उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, 1992 में इजरायल को मान्यता देकर भारत की गुट निरपेक्षता पर प्रश्न खड़ा करने का काम किया. इसके बाद से भारत-इजरायल सैन्य संबंध परवान चढ़ा और कई लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे तय हुए, जो भारत की स्वघोषित फिलिस्तीनी नीति के विरुद्ध साबित हुआ. मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद तो मानो इजरायल की मुराद ही पूरी हो गई. मंत्रियों का आना-जाना बेरोक-टोक जारी है. संयुक्त राष्ट्र में भी फिलिस्तीन पर हमले पर भारत न तो एतराज जताता है, न ही इजरायल के विरुद्ध वोटिंग में अपनी निर्णायक भागीदारी निभाता है. प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा और वहां के उभ्र प्रधानमंत्री की संभावित भारत यात्रा से दोनों ही देशों के राजनयिक संबंधों में मधुरता संभव है, जिसके फलस्वरूप दर्जनों सौदे व दूरगामी दोस्ती के आसार हैं. अंततः इनके परिणाम फिलिस्तीनी हितों के विरुद्ध ही होंगे. इराक, लीबिया, सीरिया के सत्ता परिवर्तन ने भी इस आंदोलन की कमर तोड़ने जैसा काम किया है. कभी वहां के शासनाध्यक्ष आंदोलन को सभी प्रकार के साधन मुहैया कराया करते थे परंतु अब आलम पूरी तरह से बदला हुआ है. इराक और लीबिया की सत्ता पलट और बर्बादी में अमेरिका के योगदान की जिस तरह से तीखी आलोचना होनी चाहिए थी, वहां से गायब दिखी. सम्मेलन में चर्चा के दौरान रूस का सीरिया में दखल अधिक मुखर रहा. इस तरह की विषयगत अदला-बदली पश्चिम एशिया में आये राजनीतिक परिवर्तन के संकेत भी हैं. फिलिस्तीन आंदोलन भी कई संगठनों में विभाजित हो चुका है. क्रांतिकारी संगठन 'हमास' का प्रभाव निरंतर बढ़ा है जिसको अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों तथा अरब दुनिया के शासक भी शुभ संकेत नहीं मानते. सोवियत संघ के विघटन के बाद समाजवादी देशों और तीसरी दुनिया के देशों में फिलिस्तीनी एकजुटता की जड़ें कमजोर हुई हैं. पहले ऐसे सम्मेलनों में सोवियत संघ, चीन, वियतनाम, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र आदि देशों के प्रतिनिधियों की भरमार होती थी और उनका मुख्य निशाना अमेरिकी विस्तारवाद और साम्राज्यवाद हुआ करता था. आज लगभग 78 फीसदी भूमि पर इजरायल का कब्जा बना हुआ है तथा शेष 22 फीसदी पर ही फिलिस्तीनियों का गुजर बसर हो रहा है. दुखद है कि इजरायल के निरंतर बढ़ते हस्तक्षेप और हमले अब विश्व को चिंतित नहीं कर रहे हैं. लाखों शरणार्थी दर-बदर घूम रहे हैं. हाल में सीरिया से उत्पन्न संकट से प्रभावित 30 लाख शरणार्थियों ने तुर्की में शरण ली है. वहां के राष्ट्रपति को चुनाव में इन शरणार्थियों का भरपूर लाभ प्राप्त हुआ है.

दुनिया में सैन्य संतुलन बिगड़ चुका है. फिलिस्तीनियों की हकमारी अब तीसरी दुनिया के शासनाध्यक्षों को चुभनी बंद हो गई है. अरब देशों के शेख अपनी मस्ती में व्यस्त हैं. सत्ता पलट से प्रभावित तत्व भी अमेरिका की शरण में चले गए हैं. वामपंथी आंदोलन अपने अवसान पर है. ऐसे में सांसदों, यहूदीवाद के विरोधियों, पत्रकारों, लेखकों व अन्य बुद्धिजीवियों और तीसरी दुनिया की एकजुटता के हामी लातिन अमेरिका में परिवर्तन समर्थक संगठन, यूरोप के समाजवादी संगठन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. फरवरी में तेहरान में आयोजित सम्मेलन से भी उम्मीदें पुनर्जीवित हुई हैं. ईरान अमेरिकी हितों को पश्चिमी एशिया में चुनौती देता दिखता है. सभी की निगाहें ईरान में होने वाले सम्मेलन पर टिकी हैं. शायद फिलिस्तीन आंदोलन को पुरानी धार दिलाने में यह कार्यक्रम किसी नई रूप रेखा के साथ आए, जिसके तेवर पुराने आंदोलनों की याद दिलाने वाली साबित हो सकती हैं. ■

तुर्की से लौटकर

(लेखक पूर्व सांसद और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला

Call : 95340 95340

मनोज तिवारी

पुल निर्माण पर भूमि अधिग्रहण की मार

बिहार सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को परवत्ता के एमडी कॉलेज मैदान में इसका शिलान्यास किया था और 9 मार्च 2015 को मोरारका कॉलेज सुल्तानगंज के मैदान से पुल निर्माण का कार्यारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया. इस पुल के निर्माण से उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच का फासला काफी कम हो जाएगा. इसके अलावा प्रति वर्ष श्रावणी मेला में देवघर जाने वाले लाखों कांवरियों को इससे फायदा होगा. इस पुल तथा सड़क के निर्माण से एनएच 31 तथा एनएच 80 आपस में जुड़ जाएंगे.

गीता कुमार

उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए सरकार का प्रयास अब रंग लाने लगा है. गंगा पर बन रहे इस पुल को इस क्षेत्र का लाइफ लाइन भी कह सकते हैं. शुरुआती झटकों के बाद खगड़िया के परवत्ता प्रखंड के दक्षिणी छोर में गंगा नदी पर अगुवानी और सुल्तानगंज घाटों के बीच विगत दो वर्षों से बनाए जा रहे फोर लेन पुल का काम फिर से तेजी पकड़ने लगा है. विगत अगस्त माह में आई बाढ़ के बाद से पुल निर्माण का कार्य बाधित था. इसके अलावा बाढ़ में निर्माण सामग्री मिश्रण के लिए लगाए गए मिनी प्लांट के साथ-साथ बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री डूब गई थी. बहरहाल निर्माण के लिए चयनित कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अधिकारी व कर्मचारी अब इन परेशानियों से निबटकर काम को गति देने में जुट गए हैं.

बिहार सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को परवत्ता के एमडी कॉलेज मैदान में इसका शिलान्यास किया था और 9 मार्च 2015 को मोरारका कॉलेज सुल्तानगंज के मैदान से पुल निर्माण का कार्यारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया. इस पुल के निर्माण से उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच का फासला काफी कम हो जाएगा. इसके अलावा प्रति वर्ष श्रावणी मेला में देवघर जाने वाले लाखों कांवरियों को इससे फायदा होगा. इस पुल तथा सड़क के निर्माण से एन एच 31 तथा एनएच 80 आपस में जुड़ जाएंगे.

गौरतलब है कि परवत्ता प्रखंड तीन तरफ से गंगा नदी से घिरा एक द्वीप की तरह है. यहां के

क्या होगी पुल की विशेषता

- फोर लेन पुल, जिसमें दो-दो लेन का दो अलग-अलग पुल बनेगा
- गंगा की मुख्यधारा में पीलर की जगह केबल पर झूलता हुआ पुल होगा
- दो पिलरों के बीच 125 मीटर की दूरी होगी.
- पुल की कुल लंबाई-3160 मीटर
- पुल का प्रकार-केबल स्टैंड आधारित
- इंटेलीजेंट ट्रैफिक प्रणाली
- पहुंच पथ की लंबाई-25 किमी
- डॉल्फिन वेधशाला

निवासियों को खेती तथा पशुपालन के लिए प्रतिदिन गंगा नदी को पार करना पड़ता है. इसके अलावा खगड़िया जिला से दक्षिण बिहार जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अगुवानी सुल्तानगंज घाट के बीच गंगा नदी को नाव के सहारे पार करते हैं. अगुवानी घाट में विगत कई वर्षों से नियमों के विरुद्ध नौका का परिचालन जारी है. बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इन नावों के परिचालन से यात्रियों की जान हमेशा जोखिम में रहती है. परिवहन विभाग के नियमानुसार सभी नावों में भार संकेतक पट्टी, लाइफ जैकेट तथा आपातकालीन स्थिति में तेज आवाज करने वाली घंटी या सीटी का होना जरूरी है. किन्तु अगुवानी घाट में अवैज्ञानिक तरीके से पम्पसेट लगाकर बनाई गई नाव पर सवार यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही रहती है.

गंगा नदी पर पुल निर्माण के कार्य ने तेजी पकड़ लिया है, किन्तु भूमि अधिग्रहण की रफ्तार धीमी ही है. इस वजह से इस पुल निर्माण को उम्मीद की नजर से देखने वाले लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि पुल निर्माण हो जाने के बावजूद एप्रोच पथ नहीं होने से लोगों को पुल का फायदा शीघ्र नहीं मिल पाएगा. जानकारों का कहना है कि दीघा पुल, मुंगेर पुल तथा विजय घाट पुल में एप्रोच नहीं रहने के कारण इन पुलों के बन जाने के बावजूद यह आम लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो पा रहा है. अगर वही अगुवानी सुल्तानगंज पुल का भी हुआ तो सारी उम्मीदें धरी रह जाएंगी.

अंचल अधिकारी शिवशंकर गुप्ता ने बताया कि पुल निर्माण कंपनी द्वारा चिन्हित भूमि के अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया चल रही है. समय-समय पर कंपनी द्वारा दी गई सूचना पर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चलती रहेगी. इससे परियोजना का कार्य प्रभावित नहीं होगा. प्रथम दृष्टया किसानों और सरकार के पास उपलब्ध अभिलेख में अंतर होने का दावा किया जा रहा है. सभी अभिलेखों को देखने एवं परीक्षण करने के बाद ही स्पष्ट निर्णय लिया जा सकेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा मुकाबला

सुनील सौरभ

बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दलीय परंपराएं टूटेंगी या क्या कोई समीकरण बनेगा? यह सवाल इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के बीच गूंज रहा है. 2011 में हुए निर्वाचन में सभी दलों ने लगातार जीत रहे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण कुमार को अपना समर्थन दिया था. तब जद (यू) के बागी प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर प्रो. अरुण कुमार को हरा कर निर्वाचित हुए थे. संजीव श्याम सिंह की जीत पर चुनावी विश्लेषकों के अनुमान भी फेल हो गये थे. 1972 से लगातार एक क्षेत्र और एक पार्टी से निर्वाचित होते रहे प्रो. अरुण कुमार के हारने ने बहुतों को आश्चर्य में डाल दिया था. लोगों ने संजीव श्याम सिंह की जीत को गया के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नए मतदाताओं की नई सोच और बदलते राजनीतिक समीकरण का परिणाम बताया था. जबकि प्रो. अरुण कुमार की छवि एक साफ-सुथरे शिक्षक नेता के रूप में थी और 2011 का चुनाव उनका अंतिम चुनाव बताकर वोट मांगा गया था. इसके बावजूद अंतिम परिणाम में संजीव श्याम सिंह ने जीत हासिल की थी.

गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इस बार भी आधा दर्जन प्रत्याशी दलीय व निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं. वर्तमान विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह भी अपनी जीत के लिए मतदाताओं के बीच घूम रहे हैं. मगध व भोजपुर के 14191 मतदाता गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपने विधान पार्षद को चुनेंगे. सबसे अधिक मतदाता गया जिले में 3243 हैं, तो सबसे कम जहानाबाद में 771 मतदाता हैं. बक्सर में 1457, भोजपुर में 1457, कैमूर में 2031, रोहतास में 1015, अरवल में 871, औरंगाबाद में 1961 मतदाता हैं. इसमें तमाम शिक्षक संघ और राजकीयकृत उच्च विद्यालय के शिक्षक, मगध और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों, स्नातकोत्तर विभागों, संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक मतदाता होते हैं.

बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी मई माह में होने वाले चुनाव में जिन संभावित प्रत्याशियों के नामों की

चर्चा है या जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनमें रालोसपा से वर्तमान विधान पार्षद् संजीव श्याम सिंह पुन: अपनी जीत के लिए मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं. 2011 में संजीव श्याम सिंह निर्दलीय जीत कर बाद में रालोसपा में जाकर एनडीए का हिस्सा बन गए थे. उम्मीद है कि भाजपा गठबंधन उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगा या समर्थन देगा. जद (यू) से बक्सर के पूर्व विधायक हृदय नारायण यादव भी गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं. ये बसपा से विधायक थे, बाद में राजद में शामिल हुए थे. फिलहाल ये जद (यू) में हैं. जहानाबाद के एसएस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. दिनेश प्रसाद सिन्हा राजद से अपनी दावेदारी कर महागठबंधन का समर्थन मिलने की बात कर रहे हैं. ये मगध विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं. रोहतास जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व सचिव देववंश यादव भी इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं. पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के प्रो. बीएन सिन्हा भी इस चुनाव में सक्रिय हैं. पिछले विधान परिषद् के चुनाव में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी.

बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में दलों द्वारा बहुत ज्यादा उलट फेर नहीं हुआ, तो अनुमान है कि यहां सीधी लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच ही होगी. हालांकि पिछले विधान परिषद् के चुनाव में इस शिक्षक क्षेत्र के मतदाताओं ने तमाम मिथक और परंपराओं को तोड़कर साबित कर दिया कि दलीय आकाओं के निर्णय और निर्देश हम मानने को बाध्य नहीं हैं. 2011 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रो. अरुण कुमार को तब एनडीए में शामिल नीतीश कुमार के जद यू समेत एनडीए का समर्थन भी मिला था. राजद ने भी अपना समर्थन उन्हें दिया था. प्रो. अरुण कुमार का एक शिक्षक नेता और साफ-सुथरे राजनेता के रूप में ऊंचा कद है. लेकिन पिछले चुनाव में जद (यू) से टिकट नहीं मिलने पर बागी संजीव श्याम सिंह ने निर्दलीय खड़े होकर उन्हें बड़ी चुनौती दे डाली और जीत हासिल की. हालांकि यह जीत बहुत कम अंतर से हुई. अंतिम और चौथी वरीयता मत की गिनती में संजीव श्याम सिंह ने 3266 मत प्राप्त किए, जबकि प्रो. अरुण कुमार 3230 मत प्राप्त कर सके. इस चुनाव में प्रो. अरुण कुमार की हार से बिहार के राजनीतिक मठाधीशों को करारा झटका लगा था.

इस बार भी संजीव श्याम सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि हमने शिक्षकों, विशेषकर नियोजित शिक्षकों, संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों, मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए संघर्ष कर जो सुविधाएं, मान-सम्मान और वेतनमान दिलाया है, उसका फल मुझे जरूर मिलेगा. फिलहाल हर संभावित प्रत्याशी दलीय और जातीय आधार पर अपना समीकरण बनाने में जुटा है.■

feedback@chauthiduniya.com

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

भारतीय रेल आतंकियों के निशाने पर

कानपुर रेल हादसे से आईएसआई का तार जुड़ा

राकेश कुमार

आतंकी संगठनों और नक्सलियों की गठजोड़ का ही परिणाम था कानपुर का रेल हादसा. पूर्वी चम्पारण के घोड़ासहन स्टेशन के पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर रेल ट्रैक उड़ाने के असफल प्रयास में पकड़े गए नक्सली से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली. भारत को दहलाने की साजिश का संचालन पड़ोसी देश नेपाल और दुबई में बैठे आतंकियों द्वारा आईएसआई के इशारे पर किया जा रहा है.

21 नवम्बर 2016 को कानपुर के रूरा में पटना इन्दौर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 148 लोग मारे गए थे. तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह एक आतंकी घटना है और इसके तार नेपाल से जुड़े हैं. इसे महज संयोग ही कहेंगे कि पूर्वी चम्पारण के आदापुर में दर्ज दोहरे हत्याकांड में मोतिहारी पुलिस ने उमाशंकर प्रसाद उर्फ उमाशंकर पटेल को रक्सौल से और मोतीलाल पासवान और मुकेश यादव को आदापुर से गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान मोतीलाल ने बताया कि पूर्वी चम्पारण के घोड़ासहन स्टेशन के पास 1 अक्टूबर 2016 को आईईडी आईएसआई के इशारे पर लगाया गया था. विस्फोट की जिम्मेदारी आदापुर के अरुण और दीपक को दी गई थी. विस्फोट नहीं करा पाने के कारण ही दोनों की हत्या कर दी गई. इस खुलासे ने पुलिस को चौंका दिया और गहन तफ्तीश में घोड़ासहन में आईईडी लगाने के मामले में गिरफ्तार आदापुर के मोती पासवान ने नेपाल के कलेया निवासी ब्रजकिशोर के साथ मिलकर आईएसआई के इशारे पर इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की. साथ ही कानपुर रेल हादसे को भी आईएसआई के इशारे पर नक्सलियों द्वारा अंजाम देने की जानकारी दी. पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों को दी. आईबी, एटीएस, रॉ और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ कर चुकी है. मोती ने पूछताछ के दौरान अपने अन्य 12 सदस्यों का नाम भी बताया.

पुलिस मोती के दो करीबी राकेश शर्मा और गजेन्द्र को सरगर्मी से खोज रही है. दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक और नक्सली मामले दर्ज हैं. मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र राणा ने कहा कि पकड़े गए मोती पासवान, उमाशंकर प्रसाद और मुकेश यादव के आईएसआई से संबंध होने के प्रमाण मिले हैं. उनकी निशानदेही पर नेपाल से वहां की पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें नेपाल का कलेया निवासी ब्रजकिशोर गिरी, शम्भू उर्फ लड्डू और मोजाहिर अंसारी शामिल हैं. नेपाल पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार आईएसआई ने बिहार में विध्वंसक कार्रवाई की जिम्मेवारी ब्रजकिशोर को दे रखी थी. इसके लिए दुबई से उसके एकाउंट में तीस लाख रुपए भी मुहैया कराए गए थे. इसमें से साढ़े सात लाख ब्रजकिशोर के लिए थे और साढ़े सात लाख गजेन्द्र को मिले. उसी तीस लाख में से दीपक और अरुण को घोड़ासहन में ब्लास्ट कराने के लिए तीन लाख रुपए दिए गए थे. लेकिन वे 1 अक्टूबर को धमाका कराने में विफल रहे. इसकी असफलता ही दोनों की मौत का कारण बनी. मोतीलाल, मुकेश यादव, उमाशंकर, राजू पटेल और गजेन्द्र शर्मा 25 दिसंबर 2016 को अरुण और दीपक को अपने साथ नेपाल ले गए और वहां दोनों की हत्या कर दी. उन्होंने हत्या की मोबाइल से विडियो बनाकर ब्रजकिशोर को भेज दिया था. ब्रजकिशोर ने नेपाल पुलिस को बताया कि शम्शुल होदा ने दुबई में आईएसआई का कमान संभाल रखा है. उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि पूर्वी चम्पारण के शातिर बदमाशों को एक सूत्र में बांध कर पूरे बिहार और पड़ोसी राज्यों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे. इसके लिए बारह लोगों का गैंग बनाया था.

गिरफ्तार आईएसआई एजेंट के साथ एसपी जितेन्द्र राणा

कानपुर में 21 नवंबर 2016 को पटना-इंदौर एक्सप्रेस और 28 दिसंबर 2016 को सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस हादसे में भी इसी गैंग की संलिप्तता थी. यूपी एटीएस टीम की पूछताछ में मोतीलाल पासवान ने बताया कि दोनों घटनाओं का नेतृत्व ब्रजकिशोर गिरी ने किया था, जिसमें मोतीलाल पासवान, गजेन्द्र और राकेश शर्मा शामिल थे. तीनों रक्सौल के रास्ते कानपुर पहुंचे थे. कानपुर रेल हादसे में मिले सुराग के आधार पर यूपी एटीएस की टीम द्वारा दिल्ली से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के दौरान मोतीलाल ने दिल्ली से पकड़े गए मोहम्मद जुबैद के फोटो की पहचान की. उसने पुलिस को बताया कि कानपुर हादसे में जुबैद भी रेल ट्रैक के नट-वोल्ट खोलने में शामिल था.

कानपुर में 21 नवंबर 2016 को पटना-इंदौर एक्सप्रेस और 28 दिसंबर 2016 को सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस हादसे में भी इसी गैंग की संलिप्तता थी. यूपी एटीएस टीम की पूछताछ में मोतीलाल पासवान ने बताया कि दोनों घटनाओं का नेतृत्व ब्रजकिशोर गिरी ने किया था, जिसमें मोतीलाल पासवान, गजेन्द्र और राकेश शर्मा शामिल थे. तीनों रक्सौल के रास्ते कानपुर पहुंचे थे. कानपुर रेल हादसे में मिले सुराग के आधार पर यूपी एटीएस की टीम द्धारा दिल्ली से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था.

खुली सीमा होने के कारण आतंकी नेपाल में शरण लेते हैं और विध्वंसक घटनाओं को अंजाम देकर वहां भाग जाते हैं. जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में आतंकी हमले के बाद नेपाल सरकार ने भी हाई एलर्ट जारी कर दिया था. आतंकियों द्वारा नेपाल में घुसपैठ को गंभीरता से लेते हुए तीन माह पूर्व आयोजित सुरक्षा परिषद् की बैठक में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से नेपाल में आतंकी संगठनों के सदस्यों की गिरफ्तारी पर लंबी वार्ता हुई थी. फिलहाल आतंकी संगठनों का नेपाल कनेक्शन भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है. इसी चौकसी का परिणाम था कि नेपाल के बारा जिले में 27 दिसम्बर को मुठभेड़ में ब्रजकिशोर गिरी, शंभू उर्फ लड्डू और मो. जहीर अंसारी नेपाली पुलिस के हत्थे चढ़ा.

दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी समन्वय बनाकर इंडो-नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई के नेपाल कनेक्शन का खुलासा किया. इसी के साथ घोड़ासहन से लेकर कानपुर रेल हादसे में आईएसआई का तार जुड़ता गया.

भारतीय एजेंसी रॉ के सेंट्रल डेस्क के एक अधिकारी के अनुसार पाकिस्तान में करांची के मोहम्मद शेख ने शम्शुल होदा को आईएसआई से संबंध स्थापित कराया. नेपाल निवासी होदा दुबई में एनआरआई के रूप में रहता है और भारत विरोधी विध्वंसक कार्रवाई का नेतृत्व करता है. हालांकि दिखाने के लिए वह दुबई में विदेश भेजने के एजेंट के रूप में काम करता है. सीमाई क्षेत्र के इस आतंकी अभियान को नेपाल मॉड्यूल का नाम दिया गया है.

आतंक से प्रभावित मलेशिया की खुफिया रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है. हाल में मलेशिया ने नेपाली मूल के एनआरआई जंग बहादुर को अपने देश से निकाल दिया था. जंगबहादुर मलेशिया के एनआरआई संघ का अध्यक्ष भी था. उसपर आरोप है कि वह इस्लामिक आतंकी संगठनों के लिए काम करता है. बताते हैं कि जंगबहादुर और शम्शुल होदा में गहरी नजदीकी है.

इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के काठमांडू स्थित यूनिट ने भी अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि विभिन्न आतंकी संगठनों ने नेपाल को अपना शेल्टर बना लिया है. रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन नेपाल को अपने कार्य के लिए सॉफ्ट स्टेट मानते हैं. यहां आतंकी संगठन धन का लोभ देकर आसानी से युवाओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं.

खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, आईएसआई और अन्य आतंकी संगठन नेपाल में कैंप कर भारत में विध्वंसात्मक कार्रवाई को बढ़ावा दे रहे हैं. नेपाल मॉड्यूल के तहत आतंकी संगठनों का मुख्य उद्देश्य है भारत में रेलवे को निशाना बनाना.

बेंगलुरू धमाका, पटना और दिल्ली को दहलाने की योजना के खुलासे के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर सीमाई क्षेत्रों पर रही है. इस दौरान दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के सीमाई क्षेत्रों से आतंकियों के संबंधों की जानकारी प्राप्त हुई. सुरक्षा एजेंसियों ने पड़ताल शुरू की. इसी दौरान इंडियन मुजाहिदीन का सह-संस्थापक यासीन भटकल, असदुल्लाह उर्फ हकी, जाली नोट का सरगना इमरान तेली, बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड करीम टुंडा के नेपाल में होने की सूचना मिली थी. एनआईए की टीम ने जाल बिछाकर 2013 में इन आतंकियों को पकड़ने में भी सफलता पाई थी. इस दौरान इंडियन मुजाहिदीन के अफजल उस्मानी की भी गिरफ्तारी हुई. ■

feedback@chauthiduniya.com

गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ
COMFED
सुधा
वादा शुद्धता का
देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. बरौनी

नगर निगम, बेगूसराय के बढ़ते कदम
26 जनवरी, 2017 गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के अवसर पर जिलावासियों को नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं
- नगर निगम क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत वर्तमान में 15 वार्डो में डोर-टू-डोर संग्रहण का कार्य कराया जा रहा है।
- जनता से अपील है कि वे कूड़ा-कर्कट प्लास्टिक की पन्नी थर्माकोल वगैरह को नालों में न डालकर निर्धारित स्थान पर प्रातः 07.00 बजे के पूर्व डाले ओर शहर को साफ-सुथरा रखे।
- शहर में जलजमाव न हो इसलिए सभी नालों की उड़ाही का कार्य लगातार कराया जा रहा है।
- संक्रामक रोग पर नियंत्रण के लिए कीटनाशक/फोंगिंग का छिड़काव कराया जा रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रो के शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत योग्य लाभुकों से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
- नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों के अवागमन के मद्देनजर प्रत्येक वार्ड में वर्तमान में खराब स्ट्रीट लाईट के मरम्मत का कार्य जारी है।
- नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है।
- होल्डिंग कर दाताओं से अपील है कि वे अपना बकाया कर का भुगतान शीघ्र कर और दण्ड शुल्क के भागी न बनें।
- होडिंग एवं बोर्ड लगाले वालो से अपील है कि वे निर्धारित शुल्क नगर निगम में जमा कर ही होडिंग लगायें अन्यथा उनके होडिंग जब्त कर लिये जाऐगें।
- मोबाईल टावर कम्पनी वालों तथा भवन के उपर मोबाईल टावर लगाने वालों से अपील है कि वे नगर निगम में रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं सालाना कर जमा कर ही मोबाईल टावर लगाये अन्यथा जबसे टावार अधिष्ठापित हुए है तब से सभी शुल्क, दण्ड शुल्क के साथ वसूल की जाएगी।
- भवन/दूकान मालिकों से अपील है कि वे अपने भवनों के सामने स्थित नालों पर स्थायी रुप से ढ़क्कन न लगायें अन्यथा नाला उड़ाही के दौरान ढ़क्कन को हटा दिया जाएगा एवं क्षतिग्रस्त होने वाली ढ़क्कनों की मरम्मत पर व्यय होनेवाली राशि आपसे वसूल की जाएगी।
- नगर निगम द्वारा गरीबों/निसहाय व्यक्ति के लिए निजी बस पड़ाव एवं हरहर महादेव चौक के निकट निःशुल्क रैल बसेरा (आश्रय स्थल) संचालित किया जा रहा है एवं स्थायी रैन बसेरा के निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।
- जनता से अपील है कि वे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अवश्य करायें

राजीव कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त, नगर निगम बेगूसराय
राजीव रंजन, उप महापौर, नगर निगम बेगूसराय
उपेन्द्र प्रसाद सिंह, महापौर, नगर निगम बेगूसराय

बच्चों में निमोनिया
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
Dr. S.K. Mishra (MBBS,MD,)
Mira Takiz Road, SAHARSA

सहरसा के कुशल चिकित्सक डॉ. एस.के मिश्रा ने बातचीत के दौरान बताया कि नवजात बच्चों की देखभाल बहुत जरूरी हैं वे देश के भविष्य हैं। खास कर ठंढ के मौसम में बच्चों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान दें गर्म कपड़े, गर्म कमरा का भी ख्याल रखें। उन्होंने निमोनिया के बारे में बताते हुए कहा कि निमोनिया...जिसे हम आमतौर पर मामूली बीमारी ही समझते आए हैं वो अब घातक रूप ले चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर घंटे निमोनिया से 45 बच्चों की मौत होती है। यानी करीब हर मिनट हमारे देश में एक बच्चा निमोनिया की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए निमोनिया को मामूली बीमारी समझने की भूल न करें। 45 फीसदी बच्चों में पोषण की कमी है। उन्हें निमोनिया का बैक्टीरिया जल्दी अपने शिकंजे में ले सकता है। निमोनिया की वैक्सीन होने के बावजूद भारत में वैक्सिनेशन की दर महज 50 फीसदी है। यानी देश के आधे बच्चों को वैक्सीन दी ही नहीं जाती। किसी एक बीमारी से हमारे देश में इतनी मौतें नहीं होतीं जितनी निमोनिया से होती हैं। निमोनिया केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। निमोनिया एक प्रकार का संक्रमण है। हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। डॉक्टर के परामर्श से एंटीबायोटिक दवा लेने पर बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। लक्षण और इलाज -सर्दी, हाई फीवर, कफ, कंपकपी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द निमोनिया के लक्षण हैं। छोटे या नवजात बच्चों में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देता है। बच्चे देखने से बीमार लगें तो उन्हें निमोनिया हो सकता है। डॉक्टर के परामर्श के बाद ही एंटीबायोटिक दवाएं लेकर निमोनिया को खत्म किया जा सकता है। निमोनिया के मरीज को सादा खाना खाना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। मरीज को मसालेदार और बाहर के खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। परामर्श के बाद मार्केट से एचआईबी एवं न्यूमोनोकस नामक वैक्सिन बाजार में उपलब्ध है उसे ले सकते हैं। ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

यूपी के आम मतदाताओं को रास नहीं आ रहा अखिलेशवादी रवैया

अपनों से बैर, गैरों से प्रेम

आम मुस्लिम मतदाताओं और उर्दू सहाफ़ियों की राय से मिल रहे हैं भविष्य के संकेत

सूफी यायावर

अपनों से बैर और परायों से प्रेम का अखिलेशवादी रवैया लोगों को सुहा नहीं रहा है. समाजवादी पार्टी के नवोदित अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कांग्रेस से गठबंधन करने और इस नाम पर मुलायम और शिवपाल से जुड़े सपाइयों का टिकट काट कर किनारे लगाने की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयों से परिपक्व मतदाता नाराज है. खास तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा मुस्लिम मतदाता इस सियासी पचड़े में अपना कीमती मत बर्बाद नहीं करना चाहता. आम मतदाताओं से लेकर बुद्धिजीवियों और उर्दू सहाफियों (पत्रकारों) की राय में भी अखिलेश-राहुल गठबंधन लोगों को रास नहीं आ रहा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बरेली, रामपुर जिलों को लें या पूर्वांचल के आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया जैसे जिलों को देखें, सब जगह आम परिपक्व मतदाता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बचकाने फैसलों और कांग्रेस से बेसिर-पैर के गठबंधन को पचा नहीं पा रहे हैं. कुछ दिन पहले तक मुस्लिम मतदाताओं में भ्रम की स्थिति जरूर थी, लेकिन विरोधाभास भरे गठबंधन के बाद उन्होंने अधिकांशतः यह तय कर लिया कि उन्हें बसपा को वोट देना है.

आजमगढ़ के लालगंज निवासी मौलाना मोहम्मद सरवर कहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी में लंबी कलह और सत्ता-पलट के बाद अब वे सपा से ऊब चुके हैं और वे सपा छोड़कर बसपा का साथ देना चाहते हैं. बरेली के मोहनपुर गांव निवासी महताब आलम कहते हैं कि वे सपा में हुए अलोकतांत्रिक दंगल से असंतुष्ट जरूर हैं, लेकिन फिर भी वे अखिलेश यादव को ही वोट देंगे. अलीगढ़ के मुफ्ती मोहम्मद खालिद हामिद मोदी सरकार की नीतियों से असहमत हैं. वे कहते हैं कि जम्हूरियत में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सार्वजनिक झगड़े को वे अनुचित ठहराते हैं और राजनीतिक विकल्प की जरूरत पर जोर देते हैं. दारुल उलूम देवबंद के एक वरिष्ठ मौलाना ने कहा कि यूपी में भाजपा को हराना सबसे अहमियत रखता है, लेकिन पार्टी, प्रत्याशी और क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण भी खासे मायने रखते हैं. जहां तक प्रत्याशियों के चयन का मसला है, इसमें बहुजन समाज पार्टी सबसे अव्वल साबित हुई है. लिहाजा, वे तो बसपा का समर्थन करते हैं. मौलाना कहते हैं कि अगर सभी मुस्लिम एकजुट होकर वोट करें तो यूपी में राजनीतिक बदलाव आ सकता है.

बसपा द्वारा कौमी एकता दल का अपनी पार्टी में विलय कराने से मुस्लिम मतदाताओं में प्रसन्नता है. वे इसे मायावती की राजनीतिक-चतुराई मानते हैं. खास तौर पर पूर्वांचल में मुस्लिम मतदाताओं पर इसका सकारात्मक असर है. बुद्धिजीवी डॉ. मुहम्मद सरफे आलम कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को टिकट देने को लेकर मीडिया वाले कुछ भी कहते रहें, लेकिन असलियत यही है कि मुख्तार अंसारी को आम मुसलमान 'हीरो' मानता है और उसे अपना राजनीतिक प्रतिनिधि बनाने में गौरव महसूस करता है. बसपा प्रमुख मायावती द्वारा करीब सौ मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने को भी डॉ. आलम मुसलमानों के बीच सकारात्मक संदेश जाने के नजरिए से देखते हैं और कहते हैं कि इसका असर चुनाव में दिखेगा. चुनाव कवरेज करने कोलकाता से लखनऊ में कैंप कर रहे उर्दू अखबार अखबारे मशरिक के वरिष्ठ पत्रकार अजमत जमील सिद्दीकी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव से काफी पहले से सपा में मचे घमासान पर मुस्लिम मतदाता निराश था. इसे मायावती ने अच्छी तरह भांपा. मायावती को लगा कि ऐसे मौके पर मुसलमानों का वोट बसपा की तरफ मुड़ सकता है. उन्होंने खासी संख्या में मुसलमानों को प्रत्याशी बनाने की रणनीति बनाई और उस पर काम किया. इसका मायावती को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा. सिद्दीकी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 फीसदी है, जबकि दलित आबादी करीब 21 फीसदी है. रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ज्योतिबा फूले नगर, आवस्ती, बागपत, बदायूं, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर और पीलीभीत की कुल 113 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. ऐसे में अगर मायावती को मुस्लिम वोट एकजुट होकर मिल गया तो यूपी में बसपा की सरकार बननी तय है. मुख्तार अंसारी को बसपा में शरीक करने और उन्हें टिकट देने के मसले पर मायावती ने यह कह कर मुसमलानों का भावनात्मक समर्थन हासिल किया कि कोर्ट में अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी अपराधी हैं. मायावती ने तो यहां तक कहा कि मुख्तार को जान-बूझकर फंसाया गया है. अजमत कहते हैं कि सपाइयों को खिसियाने के लिए ही मायावती ने अपने पूर्व घोषित प्रत्याशियों का नाम काट कर मुख्तार अंसारी को मऊ से, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को घोसी से और मुख्तार के भाई सिग्बतुल्लाह अंसारी को मोहम्मदाबाद से टिकट देने की घोषणा की. सपा और कांग्रेस के गठबंधन से मुसलमान कितना प्रभावित हुआ है? इस सवाल पर सिद्दीकी कहते हैं कि फौरी तौर पर यह गठबंधन तो ठीक दिख सकता है, लेकिन मतदाता बिहार में गठबंधन की दुर्गत बनाने में सपा की भूमिका को कहां भूला है. खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को यह अच्छी तरह याद है कि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने ही गठबंधन तोड़वाया था और आज उसी गठबंधन के बड़े खैरख्वाह बन रहे हैं. सिद्दीकी यह भी कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण वगैरह के कांग्रेसी आश्वासन बिल्कुल नहीं सुहाते. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी अजमत जमील सिद्दीकी की इन बातों की तस्दीक करते हैं. मौलाना कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण का दांव नहीं लुभाता. गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन से घिरा मुस्लिम तबका अपने मसाएल को लेकर ही परेशान रहता है. शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना याकूब अब्बास कहते हैं कि इस बार पार्टियों के कोरे वादे नहीं चलेंगे, बल्कि उन्हें खास तौर पर शिया मुसलमानों के कल्याण के लिए पक्की योजना पेश करनी होगी.

मुस्लिम नागरिकों और बुद्धिजीवियों की इन बातों से स्पष्ट हुआ कि 'बहुप्रचारित यूपी को ये साथ पसंद है', असलियत में पसंद नहीं किया जा रहा है. राहुल-अखिलेश के लखनऊ में रोड-शो के दौरान भी लोगों की भीड़ से यह सवाल उठता रहा, 'क्या मुसलमानों को यह साथ पसंद है'? मुस्लिम बुद्धिजीवियों और मुस्लिम मतदाताओं ने इस पर नकारात्मक ही जवाब दिया. ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष शाइस्ता अंबर का कहना है कि मुसलमान अब किसी मौलाना या नेता के कहने पर नहीं बल्कि स्वयं निर्णय लेता है. मुसलमान अब अखिलेश, राहुल या मायावती के दिखाए इस डर की भी परवाह नहीं करता कि भाजपा के सत्ता में आने से मुसलमानों को कोई खतरा है. लेकिन लब्बोलुबाब यही है कि मुसलमान राजनीतिक विकल्प की छटपटाहट से भरा है. उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद सपा और कांग्रेस के गठबंधन को धोखा करार देते हैं. उनका मानना है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को नुकसान इन्हीं दोनों दलों ने पहुंचाया है. कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कल्बे जव्वाद कहते हैं कि 50 साल से ज्यादा केंद्र में हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने सबसे ज्यादा तबाही पहुंचाई है. अखिलेश की सरकार में सैकड़ों की संख्या में और कांग्रेस के शासनकाल में हजारों दंगे हुए हैं. ये दोनों ही पार्टियां मुस्लिम विरोधी हैं. मौलाना कहते हैं कि मुलायम सिंह भी अखिलेश पर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगा चुके हैं. उलमा समाजवादी पार्टी की वादा खिलाफी से नाराज हैं. अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान सिद्दीकी भी बसपा को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं.

मौलाना कल्बे जव्वाद की बातों को आगे बढ़ाएं और मुसलमान मतदाताओं का मन टटोलें तो पाएंगे कि खास तौर पर मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर अखिलेश यादव की सरकार पूरी तरह कटघरे में है. ऐसे में शांति और अच्छे प्रशासन के लिए बहुत से मुसलमान मायावती के दिन को याद कर रहे हैं. मऊ के शाहिद जमाल बीडीसी हैं. वे अखिलेश सरकार से खासे खफा हैं. उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह मुजफ्फरनगर दंगा है. जमाल कहते हैं, 'आप जाकर मुजफ्फरनगर की हालत देखिए. वहां आज भी लोग शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं. मुलायम सिंह ने कहा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो जितने भी बेकसूर मुसलमान जेल में बंद हैं सबको रिहा करवाएंगे. लेकिन अखिलेश सरकार ने तारिक कासमी के साथ क्या किया? मुलायम सिंह ने वादा किया था कि जितने मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं, वहां हर थाने में मुस्लिम थानेदार होगा. बुनकरी पूर्वांचल के लोगों की रोजी-रोटी का सबसे बड़ा जरिया है. सपा ने कहा था कि हम बुनकर को उद्योग-धंधे में शामिल करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को 18 फीसद आरक्षण देंगे. अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया. मुलायम सिंह ने ही कहा है कि अखिलेश मुसलमानों को नजरअंदाज करते हैं. अखिलेश तो एक मुस्लिम डीजीपी की पोस्टिंग से भी नाखुश थे. इससे तो अच्छा है कि बसपा आए. हमारा अनुभव है कि बसपा के राज में शांति रहती है और गुंडे जेल में रहते हैं.'

घोसी (मऊ) के शमशाद अहमद कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में अखिलेश सरकार नाकाम रही. कुंडा में शहीद हुए डीएसपी जियाउल हक के परिवार को इंसाफ नहीं मिला. मुख्तार को यह कहकर टिकट नहीं दिया कि वह माफिया है लेकिन दूसरे अपराधियों को मंत्री पद देने से कोई गुरेज नहीं किया. कुशीनगर के मोहम्मद आरिफ हर पार्टी से निराशा जताते हुए कहते हैं कि अन्य सभी पार्टियां भाजपा का डर दिखा कर हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं. आरिफ पीस पार्टी और उसके नेता डॉक्टर अय्यूब की वकालत करते हुए कहते हैं कि वे एक पढ़े-लिखे नेता हैं, जो विधानसभा में अकेले दम पर फिरकापरस्तों के खिलाफ डट कर मुकाबला करते हैं. वही एकमात्र नेता हैं, जो सच्चे दिल से गरीबों और बुनकरों की लड़ाई लड़ते हैं. इलाहाबाद के शाहिद को अखिलेश सरकार से कोई शिकायत नहीं है. शाहिद मानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा को सिर्फ अखिलेश यादव ही टक्कर दे सकते हैं. वे कहते हैं कि अखिलेश तरक्कीपसंद युवा हैं और उनकी एक साफ-सुथरी छवि है, इसलिए उन्हें दूसरा मौका देना ही चाहिए. आपको यह याद दिलाते चलें कि लोकसभा चुनाव के पहले ही पसमांदा मुसलमान समाज ने बसपा के प्रति अपना समर्थन जताया था. समाज का कहना था कि बसपा हमेशा मुसलमानों के हितों को लेकर सजग रही है. बसपा के शासनकाल में मुसलमानों के लिए तमाम कल्याणकारी कार्य किए गए थे. समाज का कहना था कि बसपा राज में कोई दंगा नहीं होता. प्रदेश में चार-चार बार बसपा की सरकार बनी, कभी दंगा नहीं हुआ.■

उर्दू पत्रकारों की सलाह : मुसलमान चतुराई से वोट करें

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर देश और प्रदेश के उर्दू मीडिया में खासी सरगर्मी है. कई प्रदेशों से उर्दू सहाफी लखनऊ में जुटे हैं और अलग-अलग जिलों में जाकर वहां का जायजा ले रहे हैं. उत्तर प्रदेश के उर्दू अखबार भी इन दिनों चुनावी लेखों, विश्लेषण, संपादकीय और पाठकों की प्रतिक्रियाओं से भरे पड़े हैं. यूपी चुनाव में मुस्लिमों की भूमिका के इर्द-गिर्द लिखे जा रहे लेखों में मुस्लिमों के वोट डालने के तरीके पर बात की जा रही है. कुछ में अखिलेश यादव के लिए सलाह है तो कुछ अखबार मायावती को फायदा होने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं. कुछ अखबार अखिलेश को यूपी का लोकप्रिय नेता बता रहे हैं. उर्दू अखबार के स्तंभकार हिलाल अहमद कहते हैं कि मुस्लिमों को जमीनी हकीकत को देखना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल चतुराई से करना चाहिए. अहमद का मानना है कि मुस्लिम-दलित गठजोड़ भी प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को बदल सकता है क्योंकि बसपा को मुस्लिम समुदाय से बहुत उम्मीदें हैं. उर्दू पत्रकार जफर आगा कहते हैं कि बीएसपी ने कई मुस्लिमों को टिकट दिए हैं और पारिवारिक झगड़े ने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है. लिहाजा, मायावती को इससे फायदा होगा. स्तंभकार हसन कमाल कहते हैं कि इस चुनाव में किसी पार्टी की राह आसान नहीं रहने वाली है. यूपी का चुनाव सभी दलों के लिए अग्निपरीक्षा होगा. अखिलेश को यह साबित करना होगा कि उनका विकास कार्य भाजपा से अलग है, जबकि बसपा को यह बताना होगा कि दलित अब भी मजबूती से उसके साथ खड़े हैं. भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दांव पर है. कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. उर्दू पत्रकार राशिद अंसारी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक डर बना हुआ है कि छोटे मुस्लिम दलों की वजह से मुसलमानों के वोट बंट जाएंगे. कई मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में हर सीट पर एक दर्जन से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं. अंसारी भी इस बात पर जोर देते हैं कि मुसलमानों को बुद्धिमानी से वोट देना चाहिए. उर्दू पत्रकार असीम जलाल मानते हैं कि सेकुलर पार्टियों का गठबंधन भाजपा को धराशाई कर देगा.

feedback@chauthiduniya.com

हिंदू युवा वाहिनी ने भाजपा को ललकारा

शाह का मठ उजाड़ देंगे योगी!

प्रभात रंजन दीन

हिंदू युवा वाहिनी ने जब उत्तर प्रदेश में अपने 60 प्रत्याशी उतारने की घोषणा की, तब लगा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी में मुलायम ने झगड़े का नियोजित नाटक खेला था, कहीं उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी में नियोजित प्रहसन की शुरुआत तो नहीं की! दोनों के मकसद अलग-अलग हो सकते हैं, पर रास्ता तकरीबन एक ही जैसा था. प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हुआ कि हिंदू युवा वाहिनी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया. योगी की मर्जी के खिलाफ जाकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने बगावती प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी. उत्तर प्रदेश में खास तौर पर और देशभर में सामान्य तौर पर राजनीतिविद् सतर्क और सक्रिय हो गए. समीक्षा होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा की, उसके परिणामस्वरूप योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के जरिए भाजपा पर दबाव बनाने का नेपथ्य से इशारा किया हो. वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष ने यही कहा भी कि भाजपा द्वारा योगी की उपेक्षा किए जाने के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी ने तकरीबन 60 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और भाजपा को सीधी टक्कर देने का फैसला किया है.

वाहिनी ने जैसे ही विद्रोह का शंख फूंका, वैसे ही भाजपा आलाकमान फुंकने लगा. संयोग देखिए कि जिस दिन वाहिनी ने समानान्तर प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा की, उसके अगले ही दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में थे. योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ पहुंचे. दोनों नेताओं की बातचीत हुई. इस बातचीत का नतीजा यह निकला कि हिंदू युवा वाहिनी के 60 प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कुछ सीटों पर ही टिका रह गया. संक्षिप्त बातचीत में योगी ने 'चौथी दुनिया' से पहले तो कहा, 'यह फेक (फर्जी) न्यूज़ है.' फिर कहा, 'इस तरह की घोषणा करने वाले वाहिनी के पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.' योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाहिनी सामाजिक संगठन है और उसके राजनीति में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है. वाहिनी के जो लोग राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यह अवैध है और वाहिनी की नीतियों और विचारों के खिलाफ है.

कार्रवाई के बारे में पूछने पर उस दिन हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि योगी हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक जरूर हैं, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार उन्हें नहीं, अनुशासन समिति को है. हालांकि बाद में सुनील सिंह को अपनी बर्खास्तगी की कार्रवाई देखनी पड़ी. उसके बाद भी वे यही कहते रहे कि वाहिनी के किसी भी पदाधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार अनुशासन समिति को है, जिसे कोर कमेटी गठित करती है. सुनील बोले, 'हम किसी दुकान के कर्मचारी नहीं हैं कि दुकानदार शटर गिरा दे और कह दे कि कल से दुकान पर मत आना.' इस बोली के बावजूद सुनील सिंह योगी के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक कुर्बानी देने की बात कहते रहे. उन्होंने कहा, ' मेरी बगावत योगी के अपमान का बदला है. पिछले पच्चीस साल में जब-जब योगी आदित्यनाथ का अपमान हुआ, हमने उसका बदला लिया है. चाहे कुसुम राय ने अपमान किया हो या फिर चंपा देवी पार्क में डॉ. अय्यूब ने. हम योगी के अपमान का बदला हमेशा लेते रहेंगे. इस बार भाजपा ने योगी का अपमान किया है. इस चुनाव में हम भाजपा से बदला लेंगे. भाजपा योगी आदित्यनाथ को अपमानित कर रही है. मैंने भाजपा को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है. हम पूर्वांचल की 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. हम पूर्वांचल में तय कर रहे हैं कि हमारा एक ही चुनाव चिन्ह हो. तकनीकी रूप से हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं. कोर कमेटी के निर्णय पर अमल होगा. हमने आज तक योगी व भाजपा से टिकट नहीं मांगा. भाजपा अगर योगी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे तो मैं पूरे पांच साल तक भाजपा कार्यालय पर कप प्लेट धोऊंगा.' सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग चाहते थे कि योगी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में घोषित किया जाए, लेकिन भाजपा ने पहले राजी होने के बाद फिर उसे टाल दिया. दूसरी तरफ पार्टी ने योगी को चुनाव प्रबंध समिति में भी शामिल नहीं किया. योगी ने लगभग 10 उम्मीदवारों की सूची दी थी, लेकिन भाजपा ने उनमें से दो को ही टिकट दिया. हम किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. भाजपा ने परिवर्तन यात्रा के दौरान भी योगी की उपेक्षा की थी. इस चुनाव में भी हमारे जन नेता की तस्वीर, पोस्टर और यात्रा के बैनर पर नहीं है. यूपी से सिर्फ राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती और कलराज मिश्र को वरीयता दी गई.

इस घटनाक्रम के पहले हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने बाकायदा मीडिया के समक्ष यह ऐलान किया था कि वाहिनी कम से कम 60 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी. पहली खेप में वाहिनी ने छह विधानसभा सीटों पडरौना से राजन जायसवाल, खड्डा से हियुवा के जिला प्रभारी अजय गोविंद शिशु, कसया से राजेश्वर सिंह (सभी कुशीनगर), पनियारा (गोरखपुर) से सतीश सिंह, सिसवा से ज्योतिषमणि त्रिपाठी और फरेंदा (महाराजगंज) से जीतेन्द्र शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी. दूसरी खेप में हिंदू युवा वाहिनी की ओर से बस्ती सदर से सुधा ओझा और रामकोला सुरक्षित सीट से अनिल कुमार बादल को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई. सुनील सिंह ने यह भी कहा था कि वाहिनी गोरखपुर के चौरीचौरा क्षेत्र से दीपक जायसवाल और झांसी सदर से अरविंद वर्मा को भी उतारने जा रही है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान बाद में किया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

योगी का असर

हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक योगी आदित्य नाथ हैं. 2002 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक यह संगठन भाजपा का साथ देता आ रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ खुद 1998 से लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं. उसके पहले भी गोरखपुर लोकसभा सीट गोरक्षधाम के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ के कब्जे में थी. महंत अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद योगी आदित्यनाथ महंत अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी बने. पूर्वांचल की सभी सीटें कमोबेश योगी के प्रभावक्षेत्र में रही हैं. फायरब्रांड योगी को भाजपा अपना चुनावी चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में भाजपा ने अपनी रणनीति बदल ली. इतना ही नहीं, योगी को दरकिनार भी कर दिया. टिकटों के निर्धारण के लिए बनी चुनाव समिति में भी योगी को मनोनीत नहीं किया गया. यहां तक कि योगी ने जो डेढ़ दर्जन नाम आलाकमान को टिकट के लिए भेजे थे, उनमें से महज पांच नाम चुने गए. भाजपा नेतृत्व के ऐसे रवैये का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ऐसा योगी समर्थक कहते हैं. उनके मुताबिक गोरखपुर बस्ती मंडल की तकरीबन 40 से 45 सीटों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है. भाजपा के कुछ पुराने नेताओं का कहना है कि हाल ही राज्यसभा के लिए चुने गए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ल योगी की मुखालफत करते हैं. योगी की उपेक्षा से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह का दावा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा सौ सीटें पार कर जाए, वही बहुत है. ■

भाजपा को योगी के चेहरे का ही भरोसा

हिंदू युवा वाहिनी द्वारा समानान्तर प्रत्याशी खड़ा किए जाने की घोषणा रही हो या बुलंदशहर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद हुए व्यापक असर की आईबी रिपोर्ट, भाजपा आलाकमान ने अंदर ही अंदर यह तय कर लिया है कि गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे. भाजपा और संघ के प्रतिबद्ध और भरोसेमंद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच उक्त आशय का संदेश भी दे दिया गया है. इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि बुलंदशहर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ के भाषण के व्यापक असर के बारे में आईबी की तरफ से केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि योगी के भाषण का न केवल बुलंदशहर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में व्यापक असर पड़ा है. इसे देखते हुए ही भाजपा ने योगी के प्रति बरती जा रही उपेक्षा की नीति बदली और योगी को फौरन दिल्ली बुला कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे बातचीत की. भाजपा आलाकमान ने योगी के लिए अलग से एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, जो चुनाव तक उनके साथ ही रहेगा.

उल्लेखनीय है कि बुलंदशहर की चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों से हो रहे हिन्दुओं के पलायन पर गहरी चिंता जताई थी और कहा था कि समुचित कार्रवाई नहीं हुई तो यूपी में कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. उन्होंने सत्ताधारी सपा सरकार और निवर्तमान बसपा सरकार पर हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था और कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिन्दुओं को वैसे ही आतंकित किया जा रहा है, जैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर करने के लिए किया गया था. योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद की स्थिति को भयावह बताया. उन्होंने मुस्लिम-बहुल सात देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की तारीफ की और कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत में भी इसी तरह की कार्रवाई किए जाने की जरूरत है.

आप याद करें, उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के शुरुआती दौर में भाजपा द्वारा योगी आदित्यनाथ को चुनावी चेहरा बनाए जाने संबंधी खबरें काफी सुर्खियों में रहीं. लेकिन बाद में यह खबर नेपथ्य में चली गई. योगी को भाजपा ने उपेक्षित भी किया और उन्हें चुनाव समिति में भी शामिल नहीं किया. यहां तक कि उनके चाहे हुए प्रत्याशियों को टिकट भी नहीं दिया गया. योगी की उपेक्षा को अपमान मानते हुए ही हिंदू युवा वाहिनी ने तकरीबन 60 प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा कर भाजपा को चौंका दिया था. हालांकि योगी ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह को संगठन से निष्कासित कर दिया, लेकिन सुनील सिंह यही कहते रहे कि योगी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया तो वाहिनी के प्रत्याशी भाजपा को हर हाल में कड़ी टक्कर देंगे. सुनील सिंह ने यह भी माना कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात तभी होगी जब योगी अगले मुख्यमंत्री के बतौर स्वीकार कर लिए जाएंगे. हिंदू युवा वाहिनी से निष्कासित किए जाने के बावजूद योगी के लिए वफादारी के शब्दों पर की गई जिज्ञासा के जवाब में सुनील सिंह कहते हैं, 'हम महाराज जी के सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.' ■

पाठकीयता के भूगोल का हो विस्तार

अनंत विजय

इन दिनों हिंदी में नई वाली हिंदी की काफी बातें हो रही हैं. कुछ ऐसी किताबें भी प्रकाशित की गईं जिसकी मार्केटिंग के लिए इस नई वाली हिंदी का सहारा लिया गया. इस नई वाली हिंदी में बोलचाल की भाषा को जस का तस रखा गया है. यह अच्छी बात है, लेकिन एक खास आयुवर्ग के समाज पर लिखते वक्त अगर बोलचाल की भाषा को जस का तस रख दिया जाता है तो उससे पाठकीयता बढ़ती हो, इसपर किसी नतीजे पर पहुंचना शेष है. दरअसल साहित्य और पाठकीयता, यह विषय बहुत गंभीर है और उतनी ही गंभीर मंथन की मांग करता है. आजादी के पहले हिंदी में दस प्रकाशक भी नहीं थे और इस वक्त एक अनुमान के मुताबिक तीन सौ से ज्यादा प्रकाशक साहित्यिक कृतियों को छाप रहे हैं. प्रकाशन जगत के जानकारों के मुताबिक हर साल हिंदी की करीब दो से ढाई हजार साहित्यिक किताबें छपती हैं. अगर पाठक नहीं हैं तो किताबें छपती क्यों हैं? यह एक बड़ा सवाल है, जिससे टकराने के लिए ना तो लेखक तैयार हैं और ना ही प्रकाशक. क्या लेखक और प्रकाशक ने अपना पाठक वर्ग तैयार करने के लिए कोई उपाय किया? हम साठ से लेकर अस्सी के दशक को देखें तो उस वक्त पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ने हमारे देश में एक पाठक वर्ग तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. पीपीएच ने उन दिनों एक खास विचारधारा की किताबों को छाप कर सस्ते में बेचना शुरू किया. हर छोटे से लेकर बड़े शहर तक रूस के लेखकों की किताबें सहज, सस्ता और हिंदी में उपलब्ध होती थी. उसके इस प्रयास से हिंदी में एक विशाल पाठक वर्ग तैयार हुआ. सोवियत रूस के विघटन के बाद जब पीपीएच की शाखाएं बंद होने लगीं तो ना तो हिंदी के लेखकों ने और ना ही हिंदी के प्रकाशकों ने उस खाली जगह को भरने की कोशिश की. फॉर्मूला बद्ध रचनाओं ने पाठकों को निराश किया. नई सोच और नए विचार सामने नहीं आ पाए. यह प्रश्न उठ सकता है कि इससे पाठकीयता का क्या लेना-देना है. संभव है कि इस प्रसंग का पाठकीयता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो लेकिन इसने परोक्ष रूप से पाठकीयता के विस्तार को बाधित किया है. अगर किसी ने विचारधारा के दायरे से बाहर जाकर विषय उठाए तो उसे हतोत्साहित किया गया. नतीजा यह हुआ कि साहित्य से नवीन विषय छूटते चले गए और पाठक एक ही विषय को बार-बार पढ़कर उबते से चले गए.

नए जमाने के पाठक बेहद मुखर और अपनी रुचि को हासिल करने के लिए बेताब हैं. नए पाठक इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पर कोई रचना पढ़ेंगे. अगर अब गंभीरता से पाठकों की बदलती आदत पर विचार करें तो पाते हैं कि उनमें काफी बदलाव आया है. पहले पाठक सुबह उठकर अखबार का इंतजार करता था और आते ही उसको पढ़ता था लेकिन अब वो अखबार के आने का इंतजार नहीं करता है. खबरें पहले जान लेना चाहता है. खबरों के विस्तार की रुचिवाले पाठक अखबार अवश्य देखते हैं.

दरअसल नए जमाने के पाठक बेहद मुखर और अपनी रुचि को हासिल करने के लिए बेताब हैं. नए पाठक इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पर कोई रचना पढ़ेंगे. अगर अब गंभीरता से पाठकों की बदलती आदत पर विचार करें तो पाते हैं कि उनमें काफी बदलाव आया है. पहले पाठक सुबह उठकर अखबार का इंतजार करता था और आते ही उसको पढ़ता था लेकिन अब वो अखबार के आने का इंतजार नहीं करता है. खबरें पहले जान लेना चाहता है. खबरों के विस्तार की रुचिवाले पाठक अखबार अवश्य देखते हैं. खबरों को जानने की चाहत उससे इंटरनेट सर्फ करवाता है. इसी तरह से पहले पाठक किताबों का इंतजार करता था. किताबों की दुकानें खत्म होते चले जाने और इंटरनेट पर कृतियों की उपलब्धता बढ़ने से पाठकों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू किया. हो सकता है कि अभी किंडल और आई फोन या आई पैड पर पाठकों की संख्या कम दिखाई दे, लेकिन जैसे-जैसे देश में इंटरनेट का घनत्व बढ़ेगा, वैसे-वैसे पाठकों की इस प्लेटफॉर्म पर संख्या बढ़ सकती है.

अगर संपूर्णता में विचार करें तो पाठकीयता के बढ़ने-घटने के लिए कई कड़ियां जिम्मेदार हैं. पाठकीयता को एक व्यापक संदर्भ में देखें तो इसके लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है. इसका एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें सरकार, टेलीकॉम, सर्च इंजन, लेखक, डिवाइस मेकर, प्रकाशक, मीडिया और मीडिया मालिक शामिल हैं. इन सबको मिलाकर पाठकीयता का निर्माण होता है. सरकार, प्रकाशक और लेखक की भूमिका सबको ज्ञात है. टेलीकॉम यानी कि फोन और उसमें लोड सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन जहां जाकर कोई भी अपनी मनपसंद रचना को ढूंढ सकता है. पाठकीयता के निर्माण का एक पहलू डिवाइस मेकर भी है. डिवाइस यथा किंडल और आई प्लेटफॉर्म जहां रचनाओं को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है. प्रकाशक पाठकीयता बढ़ाने और नए पाठकों के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रचनाओं को उपलब्ध करवाने में महती भूमिका निभाता है.

हिंदी साहित्य को पाठकीयता बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है कि वो इस इको सिस्टम के संतुलन को बरकरार रखे. इसके अलावा लेखकों और प्रकाशकों को नए पाठकों को साहित्य की ओर आकर्षित करने के लिए नित नए उपक्रम करने होंगे. पाठकों के साथ लेखकों के बाधित संवाद को बढ़ाना होगा. देश भर के अलग-अलग शहरों में हो रहे करीब ढाई सौ लिटरेचर फेस्टिवल भी इसको बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं. इसके अलावा लेखकों को इंटरनेट के माध्यम से पाठकों से जुड़ कर संवाद करना चाहिए और अपनी रचनाओं पर फीडबैक भी लें. फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे की लेखिका ई एल जेम्स ने ट्राइलॉजी लिखने के पहले इंटरनेट पर एक सिरीज लिखी थी और बाद में पाठकों की राय पर उसे उपन्यास का रूप दिया. उसकी सफलता अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है और उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है. इन सबसे ऊपर हिंदी के लेखकों को नए-नए विषय भी ढूंढने होंगे. जिस तरह से हिंदी साहित्य से प्रेम गायब हो गया है, उसको भी वापस लेकर आना होगा. आज भी पूरी दुनिया में प्रेम कहानियों के पाठक सबसे ज्यादा हैं. हिंदी में बेहतरीन प्रेम कथा की बात करने पर धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता और मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसप ही याद आता है. हाल में खत्म हुए दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया कि लोगों में पढ़ने की भूख है. जरूरत है पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर लिखा जाए और अगर इसपर आपत्ति हो तो पाठकों के अंदर की रुचि का परिष्कार करने का उपक्रम किया जाए, ताकि पाठकों में साहित्य पढ़ने का एक संस्कार विकसित हो सके. हिंदी को इस मामले में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए. ■

anant.ibn@gmail.com

पूतिकरंज

परिचय

पूतिकरंज के सदाबहार आरोही क्षुप विश्व में म्यांमार एवं श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यतः पहाड़ियों पर 1000 मी की उंचाई तक, पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी भारत के समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं तथा मध्य एवं पूर्वी हिमालय पर पाए जाते हैं. नदियों के किनारे अथवा जलाशयों के आस-पास यह अधिक पाया जाता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग- पूतिकरंज के बीजों की गिरी के साथ समभाग सहजन के बीज, तेजपात, वच और खांड मिलाकर खरल कर महीन चूर्ण बनाकर रखें. इसको अल्प मात्रा में नाक में डालने से खूब छींकें आती हैं, जिसमें दूषित कफ का साव होकर आधासीसी तथा अन्य सिर के विकार दूर होते हैं.

नेत्ररोग- नेत्ररोग में (जब पलक लाल और रोम रहित हो जाए) 1-2 ग्राम पूतिकरंज बीज की गिरी, तुलसी और चमेली की कलियों को समभाग लेकर कूटकर आठ गुने जल में पकाएं. चौथाई शेष रहने पर, छानकर पुनः पकाकर गाढ़ा कर लें, इसे पलकों पर लगाते रहने से लाभ होता है.

दंतरोग- पूतिकरंज की टहनी का दातून करने एवं इसके तेल को दांतों पर घिसने से पायरिया में लाभ होता है.

एक ग्राम पूतिकरंज के बीजों को एक ग्राम मिश्री के साथ मिलाकर दांतों पर मलने तथा सेवन करने से दांतों से खून आना बंद हो जाता है.

1-2 ग्राम पूतिकरंज बीज को जल में घिसकर, कूटकर या जल में उबालकर, जल को दिन में तीन बार पिलाने से कुक्कुर खांसी में लाभ होता है.

पूतिकरंज के बीजों को भूनकर उसमें आधा भाग शक्कर मिलाकर कूट-पीसकर चने जैसी गोलियां बना लें, रोगी को 10-10 मिनट पर 1-1 गोली सेवन कराएं. शीघ्र वमन की शांति होती है.

मधुमेह- 1-2 ग्राम बीज चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है.

चर्मरोग, कुष्ठ- 10-12 मिली पूतिकरंज पत्र-स्वरस में चित्रकमूल, काली मिर्च और सेंधानमक का चूर्ण

यथोचित मात्रा में मिलाकर, दुगने पतले दही में मिलाकर दिन में दो बार 3-4 महीने तक लगातार पीते रहने से गलित कुष्ठ का शमन होता है.

1-2 ग्राम पूतिकरंज के फल या बीजों को 1-2 ग्राम इन्द्र जौ के साथ पीसकर लेप करने से भी चर्म रोगों में लाभ होता है.

पूतिकरंज, नीम और खैर के पत्रों को पीसकर लेप करें तथा तीनों के क्वाथ से स्नान करें और इसी पानी को पिलाते रहें. इससे चर्मरोगों में लाभ होता है.

1-2 ग्राम पूतिकरंज बीजों के साथ समभाग हल्दी, हरड़ और राई पीसकर लेप करने से चर्मरोगों में लाभ होता है.

1-2 ग्राम बीजों के साथ श्वेत कनेर की जड़ को पीसकर लेप करने से भी त्वचा विकारों में लाभ होता है.

करंज तेल में समभाग नींबू का रस लेकर मिला लें, जब पीले रंग का सुंदर घोल तैयार हो जाए तो इसे लगाते रहने से उपदंशजन्य या किसी अन्य विकार से हुए शरीर के चट्टों पर लगाने से वे ठीक हो जाते हैं तथा खुजली, झांई आदि चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं.

साधारण कुष्ठ पर इसके पत्रों को पीसकर लगाने से लाभ होता है.

पूतिकरंज के 25 मिली तेल में चित्रक और सेंधानमक का चूर्ण मिलाकर लेप करने से काकणक नामक महाकुष्ठ में लाभ होता है.

पूतिकरंज के पत्तों की पुल्टिस बनाकर कृमियुक्त घावों पर लगाने से लाभ होता है.

पूतिकरंज बीज तथा बीज तेल को लगाने से सफेद दाग तथा कुष्ठ में लाभ होता है.

पूतिकरंज बीज के साथ समभाग काला नमक, सोंठ और हींग मिलाकर चूर्ण करें. 500 मिग्रा से 1 ग्राम तक की मात्रा में सुखोष्ण जल के साथ सेवन करने से पार्श्व शूल में लाभ होता है.

इसके एक बीज की मींगी और 125 मिलीग्राम शुद्ध नीला थोथा, दोनों को पीसकर सरसों जैसी 12 गोलियां बनाकर 1-1 गोली नित्य सेवन करें. इससे वातज-शूल में लाभ होगा.

10-20 ग्राम पूतिकरंज के कोमल पत्तों को तिल के तेल में भूनकर नित्य सेवन करने से कफ-ज्वर में लाभ होता है.

पूतिकरंज की 3 कोमल और 2 काली मिर्च को जल में पीसकर नाभि पर लगाने से कफ-ज्वर में लाभ होता है.

1-2 ग्राम पूतिकरंज बीज चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से ज्वर में लाभ होता है.

2-4 ग्राम पूतिकरंज बीज-मज्जा चूर्ण का सेवन करने से सर्वांग शूल का शमन होता है.

मिर्गी रोग- 10-12 मिली पूतिकरंज पत्र रस को दिन में तीन बार देने से मिर्गी में लाभ होता है. ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

साईं भक्ति-प्रवाह के रहस्य

मानसिक जड़ता के कारण सहते हैं दुख

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

पिछले अंक से आगे

शिरडी में बाबा ने श्री काका साहेब दीक्षित से चुपचाप उगे-मुगे दीक्षित वाड़ा में रहने के लिए कहा था और दूसरों से मिलने के लिए मना किया था. उन्होंने दीक्षित जी से कहा था कि वे वाड़े में चोरों से सावधान रहें, नहीं तो वे सब कुछ ले जाएंगे. बाबा के इस कथन का अभिप्राय था कि यदि दीक्षित जी उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो वे अपने अच्छे गुणों एवं शांति से वंचित हो जाएंगे. इसी प्रकार उन्होंने श्री उपासनी बाबा से भी खंडोबा मंदिर में रहने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि वे किसी से भी न मिलें. श्री साईं बाबा यद्यपि उनसे कुछ सौ गज की ही दूरी पर थे, किंतु श्री उपासनी बाबा को श्री साईं बाबा से मिलने की अनुमति नहीं थी. असली साधकों को आम सांसारिक बातों और संबंधों से दूर रखकर बाबा चाहते थे कि वे मन की शुद्धतर एवं सकारात्मक अवस्था बनाए रखें और दूसरों के नकारात्मक विचारों से दूषित न होने पाएं, जैसा कि सामाजिक मेल-जोल में अक्सर होता है. बाबा विभिन्न भक्तों को इस प्रकार की शिक्षा दिया करते थे, जैसे- सदैव अपने दिए वचन का पालन करना, किसी से यदि सेवा प्राप्त करो तो उसे उसका समुचित पारिश्रमिक देना, चाहे कोई कितना ही उत्तेजित क्यों न करे उसे सहन करना और झगड़ा न करना, दूसरों की निंदा न करना, भौतिक या सामाजिक आधार पर किसी से भेद-भाव नहीं करना आदि और अंततः हर वस्तु, हर भाव में ईश्वर को देखना.

पूजा, आरती, प्राणायाम आदि सभी धार्मिक विधि-विधान मनुष्य की चेतना के विकास की प्रथम अवस्था हैं. मानसिक विचार-प्रक्रिया, दृष्टिकोण, मनोभाव आदि का विकास बीच की स्थिति है और अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा आत्मा की मुक्ति तीसरी एवं अंतिम अवस्था है. चूंकि सर्वज्ञ बाबा अपने भक्तों के विचारों एवं मनोभावों को आसानी से जान लेते थे, इसलिए जिस भक्त के आध्यात्मिक विकास के लिए जो आवश्यक था, उसी के अनुरूप मनोभाव-नियंत्रण के द्वारा वे उनका मार्ग-दर्शन करते थे.

इतिहास दर्शाता है कि मनुष्य की बुद्धि की सकारात्मक शक्ति ने महान् सभ्यताओं को निर्मित किया है और उसकी नकारात्मक शक्तियों के कारण सभ्यताओं का पूर्णतः विध्वंस हुआ है, जैसा कि रोम, मिस्र एवं पेरू आदि में हुआ था. इस संसार को हम वैसा ही देखते हैं, जैसा कि हमारा मन उसे देखता है और

हमारा मनोभाव बहुत सीमित एवं विकृत है. हम संसार को कैलाइडोस्कोप अर्थात बहुरूपदर्शी यंत्र द्वारा किसी स्थिर स्थिति में एक निश्चित कोण से देखते हैं. यदि इस कैलाइडोस्कोप को घुमाया जाए तो विभिन्न रूप एवं आकृतियां प्रकट होंगी. चूंकि हर व्यक्ति जीवन को एक विशेष स्थिर कोण से देखता है, यही कारण है कि हर व्यक्ति उसमें एक विशेष आकृति देखता है. जीवन और जगत का वह रूप जिसका वह अनुभव करता है, वही केवल उसे सत्य लगता है. उन लोगों की बात तो अलग ही है, जो कि बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं. यहां तक कि श्रेष्ठ गुणों से युक्त लोग भी अपनी मानसिक जड़ता के संकुचित दायरे में बंधे होने के कारण जीवन में दुख भोगते रहते हैं. कभी-कभी यह भी देखा गया है कि किन्हीं परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुण उसकी चेतना के विकास में सबसे अधिक बाधक होते हैं. उदाहरण के लिए एक दयालु व्यक्ति था, जो कि सबकी मदद किया करता था. और जैसा कि मनुष्य के साथ होता है, उसकी भी लोगों से आशाएं थीं कि दूसरे भी उसके बुरे समय में उसके साथ वैसा ही दयापूर्ण व्यवहार करें, जैसे कि उसने लोगों की सहायता की थी. लेकिन जब वह मुसीबत में आया तो सबने उसकी उस रूप में सहायता नहीं की, फलस्वरूप वह दयालु गुण पर मूलभूत प्रश्न करने लगा और आगे उसने दूसरों की सहायता न करने का निश्चय किया. ■

जारी...

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं. क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

सिंधु बनी मोदी बैडमिंटन की चैम्पियन, समीर वर्मा को पुरुषों का ख़िताब

सायना की ग़ैरमौजूदगी का सिंधु को मिला फ़ायदा

रियो ओलंपिक के बाद चाइना ओपन सुपर सीरीज में विजेता व हांगकांग ओपन सुपर सीरीज में उपविजेता रही पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपनी झोली में एक और खिताब अपने नाम कर लिया. सिंधु के खेल की बात की जाये तो उनमें कोर्ट पर अलग तरह का जुनून देखा जा सकता है. जहां एक ओर सायना कोर्ट पर चारों ओर अपना अधिकार जमाने का हुनर रखती है, दूसरी ओर सिंधु में अलग तरह की चपलता कोर्ट पर देखने को मिलेगी. हालांकि यह बात भी सत्य है कि सिंधु को अपने लंबे कद का कोर्ट पर पूरा फायदा जरूर मिलता है.

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने उम्मीद के मुताबिक सैयद मोदी बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया है, जबकि पुरुष वर्ग में समीर वर्मा ने सबको चौंकाते हुए पहली बार मोदी बैडमिंटन का खिताब जीता है. दरअसल इस बार चैम्पियनशिप में कई बड़े खिलाड़ियों के हटने के बाद सिंधु इस खिताब की तगड़ी दावेदार मानी जा रही थी. क्वार्टर फाइनल से लेकर खिताबी जंग जीतने में कोई खास परेशानी नहीं हुई. सायना ने इस टूर्नामेंट में अपनी फिटनेस का हवाला देकर प्रतियोगिता से किनारा कर लिया था, जबकि कश्यप ने पहले ही इससे अपना नाम वापस ले लिया था. ऐसे में प्रतियोगिता के रंग में भंग पड़ गया था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में उत्तर प्रदेश की राजधानी के बैडमिंटन अकादमी में पीवी सिंधु को लेकर एक अलग उत्साह देखा जा सकता था. सिंधु की एक झलक पाने के लिए बैडमिंटन अकादमी में हुजूम देखा जा सकता था. दूसरी ओर पुरुष खिलाड़ियों को लेकर लोगों में जोश ठंडा होता दिखा. इस बार प्रतियोगिता से भी ज्वाला ने अपना हाथ खींच लिया था. इसके बाद से लगने लगा कि मोदी बैडमिंटन को लेकर शहर में क्रेज खत्म होता दिख रहा है लेकिन आयोजकों ने अकादमी में इंट्री फ्री करने का फैसला किया, ताकि भारी संख्या में लोग मैच देखने आएं. खैर पीवी सिंधु के लिए खिताब का सबसे बड़ा रोड़ा सायना नेहवाल के न आने से उनका खिताब जीतना भी तय हो गया था. सिंधु ने बड़ी आसानी से पहली बाधा को पार भी कर लिया. देश की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों में शुमार पीवी सिंधु ने अपने पहले मैच में भारत की अनुरा प्रभु देसाई को 21–9 और 21–11 से पराजित कर टूर्नामेंट में अपना शानदार आगाज किया. इसके बाद अगला मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. क्वार्टर फाइनल में भी हमवतन खिलाड़ी वैदेही चौधरी को 21–15, 21–11 से पराजित कर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया था. इसके बाद पीवी सिंधु के पास खिताब जीतने का सुनहरा अवसर प्रदान हो गया था, क्योंकि राह में अब कोई बड़ा कांटा नहीं था. सेमीफाइनल में पीवी सिंधु की टक्कर फित्रयानी की चुनौती को 21–11,21–19 से धूल चटाते हुए खिताब की ओर मजबूती से कदम बढ़ा दिया. फाइनल में उनकी टक्कर इंडोनेशिया की जार्जिया से थी. सिंधु ने गैर वरीय इंडोनेशिया की जार्जिया मारीस्का चुनौती को भी बड़ी आसानी से केवल 30 मिनट में 21–13, 21–14 से पराजित कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया. इसमें कोई शक नहीं कि पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में खिताब की दावेदार थी, लेकिन वे इस टूर्नामेंट में कोई गेम नहीं हारीं, जबकि हर मुकाबला करीब 30 मिनटों में निपटाने में भी सफल रही. रियो ओलंपिक के बाद चाइना ओपन सुपर सीरीज में विजेता व हांगकांग ओपन सुपर सीरीज में उपविजेता रही पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपनी झोली में एक और खिताब अपने नाम कर लिया. सिंधु के खेल की बात की जाए तो उनमें कोर्ट पर अलग तरह का जुनून देखा जा सकता है. जहां एक ओर सायना कोर्ट पर चारों ओर अपना अधिकार जमाने का हुनर रखती है दूसरी ओर सिंधु में अलग तरह की चपलता कोर्ट पर देखने को मिलेगी. हालांकि यह बात भी सत्य है कि सिंधु को अपने लम्बे कद का कोर्ट पर पूरा फायदा मिलता है. कुल मिलाकर पीवी सिंधु के हालिया प्रदर्शन को देखकर यही लगता है कि उन्होंने ओलम्पिक में कोई तुक्का नहीं मारा था बल्कि अपने खेल की बदौलत वह देश का मान बढ़ाने में लगी हुई है.

इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्गों में भी कई उतार–चढ़ाव देखने को मिले. प्रतियोगिता में कश्यप जैसे खिलाड़ी के न होने से श्रीकांत जैसे खिलाड़ी इस खिताब पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन उनका यह दावा खोखला साबित हुआ. नवाबों के शहर लखनऊ में पुरुष वर्ग में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले. शुरुआत पुरुष क्वार्टर फाइनल में भारत के स्टार खिलाड़ी के श्रीकांत की बात की जाए तो उन्होंने मलेशिया के सातवीं वरीय जुल्किफेली जुल्फादी को 21–12, 21–17 से हराया. लगभग 43 मिनट तक चले इस मुकाबले में श्रीकांत को प्रतिद्वंद्वी से कड़ी टक्कर मिली. पिछले मैचों की तरह श्रीकांत इस मैच में भी जूझते नजर आए लेकिन अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने स्मैश व ड्रॉपशॉट का अच्छा इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी पर दबदबा बनाया और मैच में जीत अपने नाम कर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. दूसरी ओर भारत के हर्षील दानी व समीर वर्मा ने दिग्गज व ऊंची रैंकिंग प्राप्त शटलरों के खिलाफ काफी शानदार खेल दिखाया. अंडर–19 जूनियर नेशनल चैंपियन रहे हर्षील दानी ने लगातार दूसरा उलटफेर करते हुए 12वीं रैंकिंग वाले डेनमार्क के एमिल होस्ट को को 21–16, 17–21, 21–11 से मात दी. वहीं भारत के आठवीं वरीय समीर वर्मा ने दूसरी वरीय डेनमार्क के हैंस क्रिस्टियान विटिंगस को 21–15, 21–13 से हराया. हांगकांग ओपन सुपर सीरीज के उपविजेता रहे आठवीं वरीय भारत के समीर वर्मा ने चोट से उबर रहे हैंस के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया. हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी रक्षात्मक रणनीति अपनाई, लेकिन नेट पर अच्छा खेलने व कुछ अच्छे स्मैश के सहारे समीर ने मैच में दबदबा बनाए रखा. यह मैच 35 मिनट तक चला, जिसमें समीर ने थोड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज की. दूसरी ओर श्रीकांत के खिलाफ बी साई प्रणीत की उलटफेर करते हुए जीत दर्ज कर बैडमिंटन फलक पर भारतीय खेल प्रेमियों के दिल में दस्तक दी. इसके बाद पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन तीसरी वरीयता के श्रीकांत के अभियान का अंत हमवतन नौवीं वरीय साई प्रणीत के हाथों 15–21, 21–10, 21–17 आश्चर्यजनक हार के साथ समाप्त हो गया. इस हार के बाद श्रीकांत काफी निराश लग रहे थे. पहले गेम में जीत दर्ज करने के बाद लगा कि श्रीकांत इस मुकाबले को एक तरफा कर देंगे, लेकिन साई प्रणीत ने ऐसा नहीं होने दिया. इस तरह से दो खिलाड़ी बैडमिंटन की दुनिया में नया नाम थे लेकिन समीर वर्मा ने हालिया फॉर्म को यहां भी जारी रखते हुए साई प्रणीत को संभलने का मौका नहीं दिया. 2011 में लखनऊ में हुई एशियन जूनियर चैंपियनशिप के उपविजेता रहे आठवीं वरीय समीर वर्मा ने नौवीं वरीय बी साई प्रणीत को 21–19, 21–16 से मात देकर अपना पहला सैयद मोदी खिताब जीता. इस मुकाबले में पहले गेम में दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई. इस मैच में साई प्रणीत ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन 19–16 के स्कोर पर पिछड़े हुए समीर वर्मा ने नेट पर कुछ अच्छे शॉट की बदौलत अंक जुटाते हुए 21–19 से यह गेम अपने नाम कर लिया. दूसरे गेम में साई प्रणीत ने शुरुआत में बढ़त बनाई लेकिन 11–6 के बाद समीर ने वापसी करते हुए अंक जुटाए और एक–एक अंक जुटाते हुए अपना पहला ग्रांपी गोल्ड खिताब अपने नाम कर लिया. कुल मिलाकर देखा जाये तो गोपीचंद जैसे कोच लगातार भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर बदलने में जुटे हुए हैं. यह बात भी सत्य है कि सायना और सिंधु देश का गौरव हैं, लेकिन आने वाले समय में भारतीय बैडमिंटन विश्व खेल जगत पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेगा. ■

सिंधु की नजर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पर

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु एक बार फिर शानदार फॉर्म में हैं. प्रीमियर बैडमिंटन लीग में इसका उदाहरण देखने को मिल चुका है. बैडमिंटन के कई बड़े खिताब अपने नाम करने वाली पीवी सिंधु को लगता है कि अगर आने वाले समय में फिटनेस ने उनका साथ दिया तो वह अपने करियर को नई उड़ान देने में कामयाब रहेंगी. पीवी सिंधु सैय्यद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान बेहद शानदार फॉर्म में नजर आईं. सायना के सैय्यद मोदी बैडमिंटन चैंम्पियनशिप से किनारा करने के बाद पीवी सिंधु इस खिताब की तगड़ी दावेदार के रूप में सामने आईं. इस दौरान चौथी दुनिया ने उनके करियर के बारे में जानने की कोशिश की. पीवी सिंधु ने कहा कि वह अभी भारत के लिए कई और खिताब जीतना चाहती है, लेकिन उनकी फिटनेस का रोल इसमें काफी अहम होगा. उन्होंने बताया कि वह लगातार हर टूर्नामेंट के लिए पसीना बहाती है लेकिन जीत और हार उनके हाथ में नहीं है. पीवी सिंधु भले ओलम्पिक में मेडल जीतने में कामयाब रही हो लेकिन वह ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में भारत का झंडा बुलंद करना चाहती है. सिंधु ने बताया कि इस साल उनकी लिस्ट में यह टूर्नामेंट सबसे महत्वपूर्ण है. उनकी कोशिश है कि वह इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करें. दरअसल बैडमिंटन के हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ऑल इग्लैंड चैम्पियनशिप का खिताब जीते. भारत के लिए अभी तक किसी महिला खिलाड़ी ने इस खिताब पर कब्जा नहीं किया है. उन्होंने बताया कि वह भी इस टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है. सिंधु ने भरोसा जताया कि वह अगर पूरी तरह से फिट रही तो इस टूर्नामेंट में कुछ बेहतर कर सकती है. पीवी सिंधु ने हाल में एक मैच में सायना को हराकर खेल जगत में सनसनी फैला दी थी. जानकारों की मानें तो पीवी सिंधु आने वाले वक्त में सायना से भी आगे जा सकती है. पीवी सिंधु ने कहा कि वह हर टूर्नामेंट में कुछ नया सीखती है. सिंधु के अनुसार बैडमिंटन के खेल में लगातार बदलाव आ रहा है. ऐसे में वह अपने खेल में भी वक्त की मांग के साथ बदलाव करती है. दूसरी ओर पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में उनकी राय थी कि पुरस्कार अगर मिलता तो अच्छा होता. हालांकि इस बार उनको यह पुरस्कार नहीं मिला है. सिंधु ने कहा कि पुरस्कार हमेशा खेलों के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाता है. भारत की स्टार शटलर ने बताया कि वह टॉप टेन में शामिल हैं, लेकिन आने वाले समय में वह बैडमिंटन की नम्बर वन कुर्सी पर काबिज होने का दम भरती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सोनाक्षी ने फिल्म करने से किया इनकार!

एक फिल्म बनाई जा रही है *सर्कस*, जिसके लिए हीरोइन ढूंढने में निर्माता-निर्देशकों को पसीने आ रहे हैं. तीन बड़ी हीरोइनों ने इस फिल्म को ठुकरा दिया है. फिल्म में सूरज पंचोली को बतौर हीरो लिया गया है, जिनकी पहली फिल्म *हीरो* के बाद कोई फिल्म अब तक शुरू नहीं हो पाई है. हीरो की रिलीज होने के पहले उन्हें बड़ा हीरो बताया गया था, लेकिन फिल्म के असफल होते ही ऐसा कहने वाले गायब हो गए. *सर्कस* में सोनाक्षी सिन्हा ने काम करने से इनकार कर दिया है. सोनाक्षी सिन्हा को स्क्रिप्ट पसंद थी और इसीलिए उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भरी थी. लेकिन सूरज पंचोली नामी हीरो नहीं हैं. इसलिए सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म करने से मना कर दिया.■

“जाहिर सी बात है कि फिल्म के अंत में हीरो मर जाए तो उनके फैंस को दुख तो होता ही है. शाहरुख खान की कई ऐसी फिल्में रही हैं, जिसमें आखिर में वो मर जाते हैं. इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं. लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकीं, पर शाहरुख के अभिनय की जरूर तारीफ की गई. आइए जानते हैं शाहरुख खान की वे फिल्में जिनमें वे मर जाते हैं और फिल्मों को हिट करा जाते हैं.”

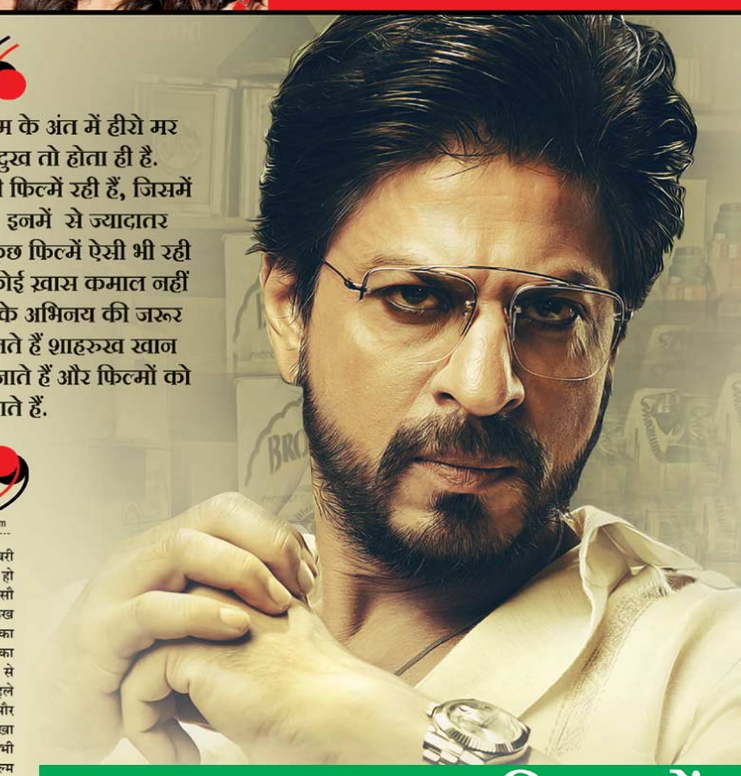

शाहरुख खान का फिल्म में मरना
हिट की गारंटी

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

शाहरुख खान की फिल्म रईस 26 जनवरी के मौके पर रिलीज़ हुई. फिल्म हिट हो चुकी है और साल 2017 की पहली सौ करोड़ी फिल्म भी बन चुकी है. शाहरुख की फिल्म रईस ने मात्र 6 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. बॉक्स ऑफिस पर रईस का कड़ा मुकाबला ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल से हुआ, जिसमें रईस ने बाजी मार ली. इससे पहले शाहरुख खान की पिछली दो फिल्में दिलवाले और फैन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई थी. इसके चलते शाहरुख के स्टारडम में भी कमी आ गई थी. इस समय उनको एक हिट फिल्म की जरूरत थी जो रईस ने पूरी कर दी. शाहरुख खान की फिल्म रईस को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. फिल्म के आखिर में जरूर दर्शकों को थोड़ा मायूस होना पड़ा क्योंकि शाहरुख खान फिल्म में मर जाते हैं. पूरी फिल्म इंज्वॉय करने के बाद अंत में दर्शक दुखी होकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले.

जाहिर सी बात है कि फिल्म के अंत में हीरो मर जाए तो उनके फैंस को दुख तो होता ही है. शाहरुख खान की कई ऐसी फिल्में रही हैं, जिसमें आखिर में वो मर जाते हैं. इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं. लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकीं, पर शाहरुख के अभिनय की जरूर तारीफ की गई. आइए जानते हैं शाहरुख खान की वे फिल्में जिनमें वे मर जाते हैं और ऐसा कर फिल्मों को हिट करा जाते हैं.

बाज़ीगर

शाहरुख खान ने वैसे तो अपना फिल्मी करियर 1992 में ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ फिल्म दीवाना से शुरू किया था. इसमें उनके अभिनय को काफी सराहा भी गया और फिल्मफेयर की ओर से शाहरुख को फिल्मफेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला. इसी साल शाहरुख की तीन फिल्में चमत्कार, दिल आशना है और राजू बन गया जैंटलमैन आईं, सभी फिल्में ठीक ठाक रहीं, पर शाहरुख खान को बॉलीवुड में वो मुकाम नहीं मिला जो वे चाहते थे.

इसके बाद शाहरुख की किस्मत खुली वर्ष 1993 में, जी हां यह वह साल था जिसने शाहरुख खान को बॉलीवुड में एक अभिनेता के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर दिया. इस साल शाहरुख की फिल्म बाज़ीगर ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी. बाज़ीगर में वह सब कुछ था जिसे देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खुद ब खुद खिंचे चले आए. शाहरुख का शानदार अभिनय, अच्छी स्क्रिप्ट, शानदार गाने फिल्म में वह सबकुछ था जिसके चलते फिल्म बाज़ीगर साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई. यह शाहरुख खान की पहली ऐसी फिल्म थी, जिसमें वे मर जाते हैं. बाज़ीगर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें शाहरुख खान ने एक विलेन की भूमिका निभाई थी. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. शाहरुख खान को बाज़ीगर के लिए फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिल चुका है.■

डर

कि कि... किरण! याद है ना आपको. जी हां, शायद ही कोई हो, जो शाहरुख खान के इस डायलॉग को नहीं जानता हो. उस समय शाहरुख खान अपने डायलॉग थोड़ा हकलाकर बोला करते थे. फिल्म का यह डायलॉग कि कि कि... किरण, सबसे यादगार डायलॉग था, जिसे लोग आज भी शाहरुख की एक्टिंग करने वक्त बोलते हैं. वर्ष 1993 में बाज़ीगर के बाद शाहरुख को यह दूसरी ऐसी फिल्म मिली जिसमें उन्होंने एक बार फिर से विलेन की भूमिका अदा की. फिल्म में सनी देओल और जूही चावला मुख्य अभिनय करते नजर आए, पर शाहरुख खान की शानदार अदाकारी सभी पर भारी पड़ी. फिल्म में शाहरुख ने एक सिरफिरे आशिक की भूमिका निभाई, जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था. इस फिल्म में भी शाहरुख खान को मरते दिखाया गया है. फिल्म डर भी उस साल की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है.■

अंजाम

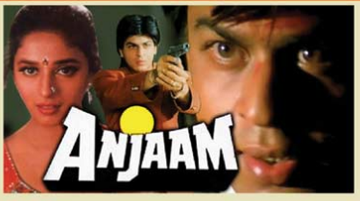

वर्ष 1994 में माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की मुख्य अभिनीत फिल्म अंजाम आई. फिल्म में दोनों कलाकारों का रोल जबरदस्त था. अंजाम के जरिए हमें एक बार फिर से शाहरुख खान का निगेटिव किरदार देखने को मिला. फिल्म में शाहरुख, माधुरी दीक्षित को पाने के लिए एक से बढ़कर एक बुरे काम को अंजाम देते नजर आए. उनकी यह चाहत फिल्म में उन पर भारी पड़ी और माधुरी दीक्षित के हाथों उन्हें मरना पड़ा. इस फिल्म को भी शाहरुख खान के फैंस ने बहुत पसंद किया और फिल्म हिट रही.■

करण अर्जुन

वर्ष 1995 में आई राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन. फिल्म में पहली बार शाहरुख खान और सलमान खान दोनों साथ नज़र आए थे. फिल्म में दोनों अभिनेताओं को मरते और उनका पुनर्जन्म दोनों दिखाया गया. करण अर्जुन एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी. फिल्म ने उस साल सिल्वर जुबली का भी रिकॉर्ड बनाया था. शाहरुख खान की यह फिल्म उस वर्ष ब्लॉकबस्टर रही.■

रामजाने

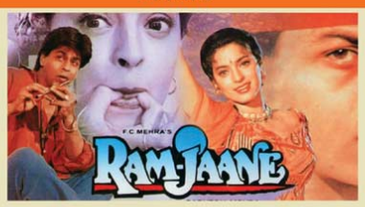

वर्ष 1995 में शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म रामजाने आई. फिल्म को राजीव मेहरा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में शाहरुख खान ने गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें उनका नाम रामजाने था. नकारात्मक भूमिका में शाहरुख की यह चौथी फिल्म थी. इससे पहले वह फिल्म बाज़ीगर, डर और अंजाम कर चुके थे. फिल्म में शाहरुख खान लास्ट में मर जाते हैं. लेकिन यह फिल्म ज्यादा बड़ी हिट साबित नहीं हो सकी. फिल्म को औसत हिट से ही काम चलाना पड़ा.■

दिल से

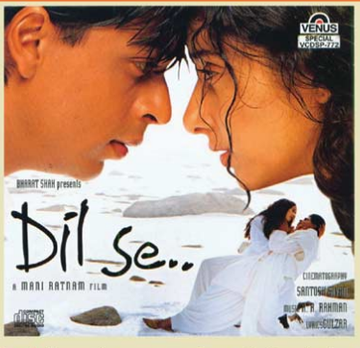

वर्ष 1998 में शाहरुख खान की एक और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी, फिल्म थी दिल से, जिसे मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में शाहरुख के अलावा मनीषा कोईराला और प्रीति जिंटा ने अहम किरदार निभाया था. फिल्म में शाहरुख खान मनीषा कोईराला की सच्चाई जाने बगैर उनसे प्यार कर बैठते हैं. जब शाहरुख खान को पता चलता है कि मनीषा एक सुसाइड बॉम्बर है, तो उसको रोकते हुए बम ब्लास्ट में दोनों मर जाते हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही लेकिन सभी कलाकारों के अभिनय की जमकर तारीफ हुई. फिल्म दिल से को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है.■

देवदास

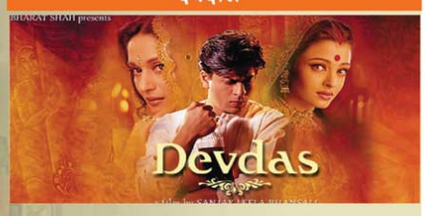

शाहरुख खान की फिल्म देवदास 2002 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. फिल्म में शाहरुख ने देवदास की भूमिका निभाई. इसके अलावा फिल्म में शाहरुख का साथ माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय ने बखूबी दिया. देवदास एक बंगाली उपन्यास पर आधारित है. इस उपन्यास को बंगाली लेखक शरतचन्द्र चटोपाध्याय ने लिखा है. फिल्म देवदास को संजय लीला भंसाली ने बखूबी ढंग से बनाया है. फिल्म हिट रही और सभी कलाकारों की खूब प्रशंसा भी हुई. इस फिल्म ने पांच राष्ट्रीय पुरस्कार और नौ फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए.■

डुप्लीकेट

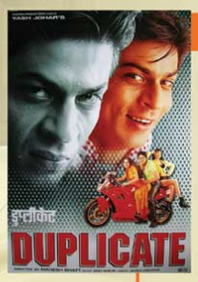

शाहरुख खान की फिल्म डुप्लीकेट वर्ष 1998 में प्रदर्शित हुई. फिल्म में शाहरुख खान को डबल रोल में दिखाया गया था. जिसमें एक को सीधा-साधा और दूसरा निगेटिव दिखाया गया. फिल्म में निगेटिव शाहरुख खान को मरते दिखाया गया. फिल्म में कुछ ख़ास देखने को नहीं था. शाहरुख खान की यह फिल्म फ्लॉप रही और दर्शकों को भी पसंद नहीं आई.■

कल हो ना हो

शाहरुख खान के फैंस अगर सबसे ज्यादा रोए होंगे तो फिल्म कल हो ना हो में, जी हां निखिल आडवाणी द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में इमोशन्स का तड़का कुछ ज्यादा ही लगाया गया था. फिल्म में शाहरुख को एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित दिखाया गया है. जब फिल्म में शाहरुख को मरते दिखाया गया तो यकीनन सभी दर्शकों की आंखों से पानी बहा होगा. फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड से भी नवाजा गया. इसके अलावा 7वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में भी कल हो ना हो ने कई अवॉर्ड अपने नाम किए.■

ओम शांति ओम

साल 2007 में फिल्म फराह खान निर्देशित फिल्म ओम शांति ओम बॉक्स ऑफिस पर आई. फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण ने एंट्री मारी. फिल्म के पहले हाफ में शाहरुख ने एक जूनियर आर्टिस्ट की भूमिका निभाई इसके बाद शाहरुख खान एक हादसे में दीपिका को बचाने के चक्कर में मर जाते हैं. फिल्म के दूसरे भाग में दोनों का पुनर्जन्म होता है. फिल्म हिट रही और शाहरुख खान का मरना भी इस फिल्म के लिए फायदेमंद रहा.■

रा-वन

शाहरुख खान की फिल्म रा-वन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई. फिल्म में अभिनेत्री के रूप में करीना कपूर ने उनका साथ दिया. फिल्म एक वीडियो गेम पर आधारित थी, जिसमें गेम का विलेन असली दुनिया में शाहरुख के बेटे को मारना चाहता था. पहले हाफ में फिल्म का विलेन अर्जुन रामपाल शाहरुख को मार देता है तो वहीं दूसरे हाफ में शाहरुख की एंट्री रा-वन के रूप में होती है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा झंडे तो नहीं गाड़े पर इस फिल्म के लिए शाहरुख खान की खूब तारीफ हुई.■